



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 1983/भाद्र 5, 1905

No. 35]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 1983/BHADRA 5, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

## PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India  
(other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1983

का. आ. 3351.—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहब, अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार के परामर्श से उक्त अधिनियम के अधीन नजीम को अपने कृत्यों के निर्वहन में सलाह देने के प्रयोजन के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए भी जो दरगाह समिति की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार समिति का इसके द्वारा तुरन्त गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

1. दीन सैयद जैमूल अबेदिन अली खान, साजादनशिन, दरगाह हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन चिश्ती, अजमेर।

2. मंसूर मोहम्मद आयाज महाराज, विधायक मासूदा, महाराज हाउस, इमामबारा, दरगाह शरीफ, अजमेर।

3. मुफ्ती अशाफाक हुसैन, दास्तउल्लूम इशाकिया, मोहल्ला यरीदयान, जोधपुर।

4. मोहम्मद याकूब खान, सेवा निवृत्त अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

5. श्री रजा अली खान, सेवा निवृत्त जिला और सेशन न्यायाधीश, नवाब का चौराहा, जयपुर।

6. मास्टर मोहम्मद यूसूफ, अजीज, मोहल्ला चुगगरान, दीकानेर।

7. श्री एजाज मोहम्मद खान, वकील, डोग, जिला भालावर।

[फाइल सं. 11(3)/76-बकफ]

जमाल अबदुल समद, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS  
(Legislative Department)

New Delhi, the 8th August, 1983

S.O. 3351.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955), the Central Government in consultation with the Government of Rajasthan, hereby Constitutes, with immediate effect, an Advisory Committee for a period of one year for

purpose of advising the Nazim in the discharge of his functions under said Act and also for such other purposes as may be specified in the byelaws of the Durgah Committee, consisting of the following persons, namely :—

1. Dewan Syed Zaimul Abedin Ali Khan, Sajjadanashin, Durgah Hazrat Khawaja Moinuddin Hasan Chisti, Ajmer.
2. Sri Syed Mohammad Ayaz Maharaj, M. L. A. Masuda, Maharaj House, imamsbara, Durgah Sherif, Ajmer.
3. Mufti Ashfaq Hussain, Darul-uloom Ishaquia, Mohalla Kharadiyan, Jodhpur.
4. Mohammed Yakub Khan, Retd. Chairman, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
5. Sri Raza Ali Khan, Retd. Dist. & Session Judge, Nawab Ka Chauraha, Jaipur.
6. Master Mohammad Yusuf Ajiz, Mohalla Chungran, Bikaner.
7. Sri. Aijaz Mohammed Khan, Vakil, Dog, Dist. Jhalawar.

[F. No. 11(3)/76-Wakf]

JAMAL ABDUL SAMAD, Dy. Secy.

### गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1983

का. अ. 3852.—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 8 के साथ पठित धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, पंजाब सरकार की सहमति से, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 148, 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दण्डनीय अपराधों के और उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और षड्यंत्रों के तथा पंजाब राज्य में पुलिस थागा सदर मालौट, जिला फरीदकोट में रजिस्ट्रीकृत अपराध संख्या 623, तारीख 26-10-1982 के संबंध में जो श्री सरोजन सिंह के पुत्र श्री गुरदीप सिंह की हत्या से संबंधित है, वैसे ही तथ्यों से उत्पन्न होने वाले वैसे ही संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए किसी अन्य अपराध के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण सम्पूर्ण पंजाब राज्य पर करती है।

[संख्या 228/16/83-ए.वी.डी.-2]

एच. के. वर्मा, अवर सचिव

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

### ORDER

New Delhi, the 18th August, 1983

S.O. 3352.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of Punjab, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to whole

of the State of Punjab for the investigation of offences punishable under section 302 read with sections 148 and 149 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860), and attempts, abetment and conspiracies in relation to or in connection with the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction arising out of the same facts in regard to Crime No. 623 dated 26-10-1982 relating to murder of Shri Gurdip Singh S/o Shri Sarain Singh registered at P. S. Sadar Malout, District Faridkot, in the State of Punjab.

[No. 228/16/83-AVD-II]

H. K. VERMA, Under Secy.

### योजना आयोग

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1983

का. आ. 3353.—भारत में नियमित कराधान से सम्बन्धित अध्ययन दल गठित करने का निर्णय किया गया है। इस दल का गठन इस प्रकार होगा :—

1. डा. आई. एस. गुलाटी, अध्यक्ष
2. श्री एम. पी. चितले, सदस्य
3. डा. अमरीश बागची, संयोजक

2. इस अध्ययन दल के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(1) व्यापार लाभों के कराधान की विद्यमान प्रणाली की विशेष रूप से धनमालिखित के सम्बन्ध में जांच करना।

(क) कराधान के लिए लाभों का संगणन/परिकलन, और

(ख) कर आधार/सिद्धांत पर पहुँचने के लिए विद्यमान कानून में दी गई विभिन्न कटौतियाँ और भत्ते।

(2) व्यापार लाभों के कराधान के लिए वैकल्पिक आधारों और संरचनाओं और भारतीय संदर्भ में उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

(3) सुधारों के संबंध में उपयुक्त सुझाव देना।

3. अध्ययन दल के सदस्य अपने निर्णयानुसार हवाई-जहाज में यात्रा करने के हक्दार/पात्र होंगे।

4. अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट आर्थिक सलाहकार परिषद को 4 मास के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

5. अध्ययन दल के यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते से संबंधित व्यय वर्ष 1983-84 के योजना आयोग के बजट अनुदान में से वहन किए जाएंगे।

[सं. ए.-12024/7/83-प्रशा.-1]

एच. के. अग्रवाल, उप सचिव

Planning Commission

New Delhi, the 23rd July, 1983

S.O. 3353.—It has been decided to set up a Study Group on Corporate Taxation in India. The composition of the Group will be as under :—

1. Dr. I. S. Gulati, Chairman,
2. Shri M. P. Chitale, Member,

3. Dr. Ansaresh Bagchi, Convenor.

2. The terms of the Study Group will be as follows :—

(i) To examine the present system of taxation of business profits particularly with regard to :

(a) the computation of profits for taxation, and

(b) the various deductions and allowance provided in the existing law in arriving at the tax base.

(ii) To evaluate alternative bases and structures for taxation of business profits and their suitability in the Indian context.

(iii) To suggest appropriate lines of reforms.

3. The members of the Study Group will be entitled to travel by air, at their discretion. Orders regarding their daily allowance will issue separately.

4. The Study Group will submit its Report to the Economic Advisory Council within a period of four months.

5. The expenditure of the Study Group on T. A. and D. A. will be met from within the Budget Grant of the Planning Commission for the year 1983-84.

[No. A-12024/7/83-Admn. II]  
N. K. AGGARWAL, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1983

## स्टाम्प

कांआ० 3354.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 20 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की विनांक 27 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना संख्या 16/83 स्टाम्प फा०सं० 33/2/83 वि०क० (सं० कांआ० 2049) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में स्टाम्प शुल्क की संगणना के प्रयोजनार्थ उस सारणी के स्तम्भ (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में सम्परिवर्तित करने के लिए, विनिमय की दर निर्धारित करती है :—

## सारणी

क्रम सं०	विदेशी मुद्रा	100 रुपए के सम- तुल्य विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर
1	2	3
1.	ऑस्ट्रियन शिल्लिंग	175.10
2.	ऑस्ट्रेलियन डालर	11.175
3.	बेल्जियम फ्रैंक	496
4.	कनाडियन डालर	12.035
5.	डेनिश क्रोनर	89.50
6.	डुत्चे मार्क	24.83
7.	डच गिल्डर	27.86
8.	फ्रेंच फ्रैंक	74.65
9.	हांग कांग डालर	70.35

1	2	3
10.	इटालीयन लीरा	14717
11.	जापानी येन	2340
12.	मलेशियन डालर	22.80
13.	नार्वेजियन क्रोनर	71.40
14.	पौंड स्टर्लिंग	6.4460
15.	स्वीडिश क्रोनर	74.60
16.	स्विस फ्रैंक	20.57
17.	अमरीकी डालर	9.850
18.	सिंगापुर डालर	20.79

[संख्या 24/83/स्टाम्प/फा०सं० 33/2/83-वि०क०]

भगवान दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th August, 1983

## STAMPS

S.O. 3354.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 16/83-Stamps F. No. 33/2/83-ST (No. S.O.2049), dated the 27th April, 1983, the Central Government hereby prescribes in column (3) of the Table below, the rate of exchange for the conversion of the foreign currency specified in the corresponding entry in column (2) there of into the currency of India for the purposes of calculating stamp duty.

## TABLE

S.No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equi- valent to Rs. 100.
1.	Austrian Shillings	175.10
2.	Australian Dollars	11.175
3.	Belgian Francs	496
4.	Canadian Dollar	12.035
5.	Danish Kroners	89.50
6.	Deutsche Marks	24.83
7.	Dutch Guilders	27.86
8.	French Francs	74.65
9.	Hong Kong Dollars	70.35
10.	Italian lire	14717
11.	Japanese Yen	2340
12.	Malayasian Dollars	22.80
13.	Norwegian Kroners	71.40
14.	Pound sterling	6.4460
15.	Swedish Kroners	74.60
16.	Swiss Francs	20.57
17.	U.S.A. Dollars	9.850
18.	Singapore Dollars	20.79

[No. 24/83-Stamps/F.No.33/2/83-ST]

BHAGWAN DAS Under Secy

नई दिल्ली, 8 मई, 1983

### आयकर

का०आ० 3355.—सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजनार्थ नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है :—

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परि- प्यूरीफिकेशन एण्ड करक्टराइजेशन आफ गोंडोट्रोपिन्स फ्रॉम इंडियन बफैलोस।
2. प्रायोजक का नाम हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई।
3. कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।
4. प्रारम्भ करने की तारीख 1-7-1983
5. पूरा करने की तारीख 30-6-1986
6. परियोजना की अवधि अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष
7. अनुमानित परिच्छद 1,86,600 रु०

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद आयकर अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के अंतर्गत 29-5-1985 तक अनुमोदित है, देखिए, वित्त मंत्रालय की दिनांक 6 अगस्त, 1982 की अधिसूचना सं० 4884 [फा०सं० 203/99/82-आ०का०नि० II]।

यह अनुमोदन 29-5-1985 तक मान्य है।

[सं० 5355/फा०सं० 203/87/83-आ०का०नि० II]

New Delhi, the 8th May, 1983

### INCOME TAX

S.O. 3355.—It is hereby notified for general information that the following scientific research programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income Tax Act, 1961 read with rule 6 of the Income Tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi being the Prescribed Authority :—

1. Scientific Research Project : Purification and Characterisation of Gonadotropins from Indian buffaloes.
2. Name of the Sponsor M/s. Hindustan Lever Limited, Bombay.
3. Implementing Lab. University of Hyderabad, Hyderabad.
4. Date of Commencement 1-7-1983
5. Date of completion 30-6-1986

6. Duration of the Project 3 years from the date of approval

7. Estimated outlay Rs. 1,86,600/—

University of Hyderabad, Hyderabad is approved under section 35(1) (ii) of the I.T. Act vide Ministry of Finance Notification No. 4884 [F.No. 203/99/82-ITA-II] of 6th August, 1982, up to 29-5-1985.

This approval is valid up to 29-5-1985.

[No. 5355/F.No. 203/87/83-ITA-II]

### आयकर

का०आ० 3356.—सर्व साधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली में निम्नलिखित वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम को, आयकर नियम, 1962 के नियम 6(iv) के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (2क) के प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमोदित कर दिया है :—

1. वैज्ञानिक अनुसंधान परि- डेवलेपमेंट आफ लीफ टाइप योजना क्वार्ट्ज क्रिस्टल फार इलेक्ट्रॉनिक वाचेज/क्लॉक्स बाई केमिकल मिलिंग टेक्निक्स।
2. संस्था का नाम मैसर्स हिन्दुस्तान गशीन टूल्स लि०, बंगलौर
3. कार्यान्वित करने वाली प्रयोगशाला इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स बंगलौर
4. प्रारंभ करने की तारीख 1-4-1983
5. पूरा करने की तारीख 31-3-1985
6. अनुमानित लागत 8,90,600 रु०

2. इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(2)(xiii) के अंतर्गत अनुमोदित है, देखिए, वित्त मंत्रालय की दिनांक 23-11-1946 की अधिसूचना सं० 341।

[सं० 5354/फा०सं० 203/47/83-आ०का०नि० III]

### INCOME TAX

S.O. 3356.—It is hereby notified for general information that the following Scientific Research Programme has been approved for the period specified below for the purpose of sub-section (2A) of the Section 35 of the Income Tax Act, 1961 read with Rule 6 (iv) of the Income Tax Rules, 1962 by the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi :—

1. Scientific Research Project : Development of Leaf Type Quartz Crystal for Electronic Watches/ Clocks by Chemical Milling Techniques.

2. Name of the Sponsor M/s. Hindustan Machine Tools Ltd. Bangalore.
3. Name of the implementing authority Indian Institute of Science, Bangalore.
4. Date of commencement 1-4-1983
5. Proposed date of completion 31-3-1985
6. Estimated outlay Rs. 8,90,600/—

2. Indian Institute of Science, Bangalore is approved under section 10(2) (xiii) of the I. T. Act, 1922 vide late Department of Finance, Notification No. 34 dated 23-11-1946.

[No. 5354/F. No. 203/47/83-ITA.III]

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1983

#### आय-कर

का० आ० 3357.—सर्वसाधारण को जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने नीचे उल्लिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है :—

1. यह कि जल साधन विकास और प्रबंध केन्द्र कोजीकोड़े कृषि/पशु-पालनों/मत्स्य-पालन और औषध से भिन्न अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त केन्द्र अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त केन्द्र अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परि-संपत्तियां, देनदारियां दशति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रति वर्ष विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत करेगा तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भी भेजेगा।

#### संस्था

जल साधन विकास और प्रबंध केन्द्र कोजीकोड़े।

यह अधिसूचना 15-5-82 से 14-5-85 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 4807/फा० सं० 203/44/82-आ०क०नि-II]

एम० जी० सी० गोयल, अवर सचिव

New Delhi, the 17th July, 1983

#### INCOME TAX

S.O. 3357.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

- (i) That the Centre for Water Resources Development & Management, Kozhikode, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural and applied sciences other than Agricultural/Animal husbandry/Fisheries and medicines;
- (ii) That the Centre will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Centre will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy each of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

#### INSTITUTION

Centre for Water Resources Development and Management, Kozhikode.

This notification is effective for a period of three years from 15-5-82 to 14-5-85.

[No. 4807/F. No. 203/44/82-ITA. II]

M. G. C. GOYAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1983

#### आय-कर

का० आ० 3358.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23ग) के खण्ड (v) द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "श्री गुरुवयोरप्पन आस्तिक समाजम्" को उक्त धारा के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं० 5351/फा० सं० 197/70/80-आ०क०नि० -I]

वी० बी० श्रीनिवासन, निदेशक

New Delhi, the 30th July, 1983

#### INCOME-TAX

S.O. 3358.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Guruvayoorappan Ashthika Samajam" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 to 1983-84.

[No. 5351/F. No. 197/70/80-IT(A1)]

V. B. SRINIVASAN, Director

**केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड**

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1983

सं. 243/83-सीमा-शुल्क

का. आ. 3359 :—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य में जिला सिंहभूम में तहसील आदित्यपुर के कामारिया को भाण्डा-गारण केन्द्र के रूप में घोषित करता है।

[फा. सं. 473/132/83-सी. शु.-7]

**CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS**

New Delhi, the 27th August, 1983

No. 243/83-CUSTOMS

S.O. 3359.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Camaria, Tehsil Adityapur in Singhbhum District in the State of Bihar to be a warehousing station.

[F. No. 473/132/83-CUS.]

सं. 244/83-सीमाशुल्क

का. आ. 3360.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के जिला राँची में टुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र को भाण्डा-गारण केन्द्र के रूप में घोषित करता है।

[फा. सं. 473/117/83-सी. शु. 7]

No. 244/83-CUSTOMS

S.O. 3360.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Tupudana Industrial Area in Ranchi District in the State of Bihar to be a warehousing station.

[F. No. 473/117/83-CUS.VII.]

सं. 245/83-सीमाशुल्क

का. आ. 3361.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केरल राज्य में कवीलोन जिले के पतनपुरम तालुक के पुनालुर ग्राम को भाण्डागारण केन्द्र घोषित करता है।

[फा. सं. 473/17/82-सी. शु.-7]

आनन्द छाबड़ा, सचिव

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

No. 245/83-CUSTOMS

S.O. 3361.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares village Punalur in Pathanapuram Taluk of Quillon District in the State of Kerala to be a warehousing station.

[F. No. 473/17/82-CUS.VII.]

A. K. CHHABRA, Secy.

Central Board of Excise and Customs.

(केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय)

इलाहाबाद, 2 अगस्त, 1983

समाहर्तालय अधिसूचना सं. 2/1983

विषय: के. उ. शु. :—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन समाहर्ता की शक्तियों को सौंपना।

का. आ. 3362.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं इसके द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली के नियम 56 सी (1) के दूसरे, तीसरे और चौथे परन्तुक के अन्तर्गत उक्त उपबन्धों का लाभ उठाने वाले विनिर्माताओं के लिए समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की शक्तियों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर प्रयोग करने के लिए इस समाहर्तालय के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डलों के प्रभारी सहायक समाहर्ता को सौंपता हूँ।

[पत्र संख्या IV (16) 175-नीति/83/10319]

धर्मपाल आर्य, समाहर्ता

(Office of the Controller of Central Excise)

Allahabad, the 2nd August, 1983

COLLECTORATE NOTIFICATION NO. 2/1983

Subject.—C. E.—Delegation of Collector's power under Central Excise Rules, 1944.

S.O. 3362.—In exercise of the powers vested in the under Rule 5 of Central Excise Rules, 1944 I hereby delegate the Collector's powers under second, third and fourth provisos to rule 56C(1) of C. E. Rules, 1944 to the Assistant Collector of Central Excise, Incharge of Divisions in this Collectorate, to be exercised within their respective jurisdiction to a manufacturer who seeks to avail of the said provisions.

[C. No. IV(16)175-Pol/83/10319]

D. P. ARYA, Collector.

**वाणिज्य मंत्रालय****आदेश**

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1983

का०आ० 3363.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसार में तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1090 तारीख 31 मार्च, 1979 को अधिक्रान्त करते हुए उक्त प्रस्तावों को ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करनी है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है।

सूचना की जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई व्यक्ति कोई आपेक्ष या सुझाव भेजना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद—प्रगति टावर, 11 वीं मंजिल, 26 राजेन्द्र प्लेस नई दिल्ली, 110008 को भेज सकता है।

**प्रस्ताव**

(1) यह अधिसूचित करना कि स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होंगे;

(2) इस आदेश के उपाबंध-क में दिए गए स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण नियम, 1983 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना है जो निर्यात से पूर्व ऐसे स्विच गियरों तथा नियंत्रण गियरों पर लागू होगा।

(3) (क) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को,

(ख) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को,

(ग) परेक्षण के लिए, संविदात्मक विनिर्देशों को जिनके लिए अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के आरम्भ से ठीक पहले विनिर्माताओं/निर्यात-कर्ताओं द्वारा मांग (आर्डर) प्राप्त कर लिया गया

है तथा उसके पश्चात् अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण आरम्भ होने की तारीख से साठ दिन तक के लिए मान्यता देना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे स्विच गियरों तथा नियंत्रण गियरों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं तथा निर्यात योग्य हैं या उन पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सील या चिह्न लगा हुआ है।

2. इस आदेश की कोई भी बात—

(क) भावी क्रेताओं को भू-मार्ग, जल मार्ग, या वायु मार्ग द्वारा स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के वास्तविक नमूनों के निर्यात पर लागू नहीं होगी।

(ख) उन परेक्षणों पर लागू नहीं होगी जो अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण के आरम्भ होने से ठीक पहले निर्यातकर्ता/विनिर्माता के परिसर से जा चुके हैं।

3. इस आदेश में स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर से नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित कोई स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर या उनका समुच्चय एक अभिप्रेत है।

**अनुसूची**

क्रम संख्या स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर

1. सर्किट ब्रेकर
2. एयर ब्रेक, कील, नियंत्रण तथा आशियग स्विच
3. मोटर स्टार्टर
4. बस तालिकाओं सहित अन्तः मेलक बस छड़ें
5. मेलक (कान्ट्रैक्टर)
6. फ्यूज, फ्यूज ब्रॉड तथा कट-आउट
7. विभाजित पिलर
8. बिजली से चलने वाले गेट के अन्त के डिब्बे
9. वियोजक (आइसोलेटर)
10. विद्युत शक्ति मेलक।

**उपाबंध 'क'**

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा आरम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

- (क) 'अधिनियम' से नियमित (क्वालिटी) नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;
- (ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित नियमित निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है;
- (ग) 'परिषद' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित नियमित निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है;
- (घ) 'स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर' से नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित कोई स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर या उनका समुच्चय अभिप्रेत है।

#### अनुसूची-1

क्रम संख्या स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर

1. सर्किट ब्रेकर
2. एयर ब्रेक, कॉल, नियंत्रण तथा अधिग स्विच
3. मोटर स्टार्टर
4. बस तालिकाओं सहित अन्तः मेलक बस छुंटे
5. मेलक (कान्ट्रैक्टर)
6. फ्यूज, फ्यूज बोर्ड तथा कट-आउट
7. विभाजित पिलर
8. बिजली से चलने वाले गेट के अन्त के डिब्बे
9. वियोजन (इन्सुलेटर)
10. बिद्युत शक्ति मेलक।

3. निरीक्षण का आधार:—नियमित के लिए स्विच गियरों तथा नियंत्रण गियर का निरीक्षण यह देखने का दृष्टि से किया जाएगा कि स्विच गियर और नियंत्रण गियर अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों, अर्थात् राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा नियमित निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों के अनुरूप हैं ;

या

(क) यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादन इस अधिसूचना के उपाबंध 1 में यथावर्णित उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है ;

या

(ख) इस अधिसूचना के उपाबंध II में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया गया है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के परेपण का नियमित करने का इच्छुक नियमितकर्ता नियमित संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यांग देते हुए, अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उपाबंध-I में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करते हुए विनिर्मित स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के नियमित के लिए और यदि इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनाल ने यह निर्णय दिया है कि विनिर्माण एकक में उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण ट्विनों की पर्याप्त व्यवस्था है तो भी नियमितकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी प्रस्तुत करेगा कि नियमित के लिए आशयित स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर का परेपण उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करते हुए किया गया था तथा परेपण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) नियमितकर्ता नियमित किए जाने वाले परेपण पर लगाए गए पहचान चिह्न भी अभिकरण को देगा।

(4) उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर से परेपण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी, जबकि उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माता के परिसर से परेपण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उपनियम (1) के अधीन सूचना तथा उपनियम (2) के अधीन घोषणा के यदि कोई हो प्राप्त होने पर अभिकरण,—

(क) अपना यह सनाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता के उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया था तथा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पादन का विनिर्माण करने के लिए इस संबंध में परिषद/अभिकरण द्वारा जारी अनुदेशों का, यदि कोई हो, पालन किया है तो तीन दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर का परेपण नियमित-योग्य है। उस दशा में जहां विनिर्माता नियमितकर्ता नहीं है वहां परेपण का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा और अभिकरण द्वारा ऐसा सत्यापन और निरीक्षण, यदि आवश्यक हो तो, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह उपरोक्त शर्तों के अनुरूप है।

अभिकरण नियमित के लिए आशयित कुछ परेपणों की स्थल पर ही जांच करेगा तथा उत्पादन के दौरान विनिर्माण एकक के द्वारा अपनाए गए क्वालिटी नियंत्रण ट्विनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाने का सत्यापन करने के लिए विनिर्मित अन्तगाल पर एककों में जाएगा। यदि विनिर्माण के किसी



भी प्रक्रम पर यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक में अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों की व्यवस्था नहीं की गयी है या परिपक्व/अभिकरण की सिफारिशों को पूरा नहीं किया गया है तो यह घोषित किया जाएगा कि एकक के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण डिवीज़न नहीं है। ऐसे मामलों में, एकक, यदि चाहे तो, उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण डिवीज़न की पर्याप्तता को बनाए रखने के समायोजन के लिए फिर से आवेदन कर सकता है।

(ख) यदि निर्यातकर्ता ने अपना यह समाधान कर लेने पर कि स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर का परेपण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, उपाबंध-II में यथा अधिकथित निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर उप-नियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया है तो वह ऐसा निरीक्षण करने के सात दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि स्विच गियर और नियंत्रण गियर का परेपण निर्यात योग्य है:

परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह निर्यातकर्ता को ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा कि स्विच गियर और नियंत्रण गियर का परेपण निर्यात योग्य है तथा ऐसे इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित सात दिन के भीतर देगा।

(6) यदि उपनियम (5) (ख) के अधीन विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, तो अभिकरण निरीक्षण के ठीक पश्चात् परेपण के पैकेज को इस प्रकार सील बन्द करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि सील बंद पैकेजों के साथ फेर-बदल नहीं की जा सकती है। परेपण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेपण अभिकरण द्वारा सील बंद नहीं किया जा सकेगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृत के विरुद्ध कोई भी अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण—

(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसरों पर, या

(ख) ऐसे परिसरों पर जहां निर्यातकर्ता ने माल प्रस्तुत किया है परन्तु यह तब जबकि वहां निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों, किया जाएगा।

6. निरीक्षण फीस :—निरीक्षण फीस का संशय विनिर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निम्नानुसार किया जाएगा :

1. नियम 3 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए प्रति परेपण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.25% की दर से।

2. नियम 3 (ख) के अधीन निरीक्षण के लिए प्रति परेपण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

3. संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र में रजिस्ट्रार/सुपु उद्योग एक्को को उप-नियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट निरीक्षण फीस की दर में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

7. मान्यता प्राप्त चिन्ह लगाने तथा उसकी प्रक्रिया :— भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक संस्थान (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के उपाबंध निर्यात में पूर्व स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर पर मुद्रा या मान्यता प्राप्त चिन्ह लगाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित स्विच गियरों तथा नियंत्रण गियरों का नियम 3 के अधीन कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन प्रमाण-पत्र देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे विशेषज्ञ पैनल को अपील कर सकेगा, जिसमें कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे।

(2) पैनल की कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य अग्रभागीय होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी।

### उपाबंध—I

[अधिसूचना के उपाबंध 'क' का नियम 3(क) देखिए]

स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के क्वालिटी नियंत्रणों का विनिर्माता इससे उपाबंध अनुसूची-II में दिए हुए नियंत्रण के स्तरों के साथ उत्पादन की पैकिंग तथा परिरक्षण विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों को प्रभावित करते हुए प्रयोग करेगा।

1. क्रय की गई सामग्री तथा संघटकों का नियंत्रण—

(क) विनिर्माता प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशेषता तथा सक्षमताओं सहित विस्तृत विमाओं को समाविष्ट करते हुए क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेपणों के साथ या तो क्रय का विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए उत्पादन का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र के न होने पर क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रत्येक परेपण में से नमूनों की नियमित जांच की जाएगी। उत्पादक के परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता सत्यापित करने के लिए पांच परेपणों में से कम से कम एक की जांच की जाएगी।

(ग) आने वाले परेषणों का निरीक्षण और परीक्षण सांख्यिकी नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण के पश्चात् त्रुटियों के निपटान तथा पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) उपरोक्त नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जायेंगे।

2. प्रक्रिया नियंत्रण : (क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ब्योरेबार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) प्रक्रमित सामग्री की प्रक्रिया विनिर्देशों के साथ अनुरूपता की जांच के लिए नमूना (जहां कहीं अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

3. उत्पाद नियंत्रण (क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान हैं।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) परीक्षण किए जाने वाले उत्पाद के विवरण का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे।

4. माप-पद्धति नियंत्रण : उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों तथा उपकरणों की कालिक जांच या उसका अंशशोधन किया जाएगा तथा अभिलेख वृत्त कार्ड के रूप में रखे जायेंगे।

5. परिरक्षण नियंत्रण : (क) उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता द्वारा ब्योरेबार विनिर्देश अधिकथित किए जायेंगे।

(ख) उत्पाद भंडारण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी प्रकार से परिरक्षित रखा जाएगा।

6. पैकिंग नियंत्रण : उत्पादों की पैकिंग के साथ ही निर्यात पैकेज के लिए विनिर्देश अधिकथित किए जायेंगे और उनका कठोरता से पालन किया जाएगा।

## उपाबंध II

[अधिसूचना के उपाबंध 'क' का नियम 3(ख) देखिए]

1. स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के परेषण

अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों से उसकी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण तथा परीक्षण के अधीन होंगे।

2. नमूना लेने के तथा अनुरूपता के मानकों के संबंध में संविदात्मक विनिर्देशों में किसी विनिर्दिष्ट अनुबंध की अनुपस्थिति में वह लागू होना जो नीचे अधिकथित है।

2.1 सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में दिए गए स्वीकृत परीक्षण नीचे सारणी-1 में दिए गए लाटों में से चुने गए नमूनों के लिए किए जायेंगे तथा लाटों की सारणी में दी गयी अनुरूपता के लिए मानदंड के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

### सारणी-I

अनुरूपता के लिए नमूना आकार तथा मानदंड

लाट आकार	पहला नमूना	दूसरा नमूना	पहली अस्वीकृति	दूसरी अस्वीकृति
1	2	3	4	5
50 तक	5	5	2	2
51 से 100	8	8	2	2
101 से 300	13	13	2	2
301 से 500	20	20	2	3
501 से ऊपर	32	32	3	4

नोट : लाट से अभिप्रेत एक परेषण में एक ही बनावट, माडल तथा प्रकार के एक साथ ग्रुप किए गए सभी स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर हैं।

2.2 चुनाव की बेतरतीबी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भा०मा० 4905-1968 में दी गई प्रक्रिया (बेतरतीबी नमूने का तरीका) का अनुसरण किया जाएगा।

2.3 सारणी-I के स्तम्भ-I तथा II के अनुसार एक साथ चुने गए स्विच गियरों तथा नियंत्रण गियरों को, अलग अलग स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर विनिर्देश में विनिर्दिष्ट स्वीकृत परेषण के अधीन किया जाएगा एक भी स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर स्वीकृत परेषणों में से किसी का भी समाधान करने में असमर्थ होता है तो उसे दोषपूर्ण समझा जाएगा। यदि नमूने में दोष नहीं पाया जाता है, तो लाट को अपेक्षाओं के अनुरूप समझा जाएगा। यदि नमूने में दोषों की संख्या पाई जाती है तो पहली अस्वीकृति (स्तम्भ 4 देखिए) के बराबर या अधिक है तो उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा यदि दोषों की संख्या पहली अस्वीकृति संख्या से कम है तो स्तम्भ 3 में दिया गया दूसरा नमूना उसी समय लिया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा। यदि दोषों की संख्या मिश्रित नमूनों में दूसरे अस्वीकृति संख्या (स्तम्भ 5 देखिए) के बराबर पायी जाती है तो लाट अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा स्वीकृत कर लिया जाएगा।

2.4 निरीक्षण करने से पहले अभिकरण को अपना समाधान कर लेना चाहिए कि प्रत्येक स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर पर दैनिक परीक्षण जैसा कि सुसंगत मानक में दिया गया है नियतिकर्ता/विनिर्माता द्वारा पोषण कर दिया गया है।

2.5 विनिर्माता/नियतिकर्ता द्वारा निरीक्षण के लिए दिए गए एक ही प्रकार तथा दर के स्विच गियर तथा नियंत्रण गियर के उस निरन्तर परीक्षणों के (या वर्ष में कम से

कम एक बार) एक में से दो नमूने लिए जायेंगे और मानक विनिर्देशों में दिए गए के अनुसार प्रकार परीक्षण किया जाएगा और दोनों नमूनों को प्रकार परख से पास होना चाहिए।

2.6 परीक्षण की पद्धति : यदि निर्यात संविदा में विनिर्दिष्ट न हो अन्यथा परीक्षण प्रक्रिया सुसंगत राष्ट्रीय मानक विनिर्देश के अनुसार या भारतीय मानक विनिर्देशों का नवीनतम रूपान्तर होगी।

### अनुसूची-II

(नियम 3 देखिए)

नियंत्रण के स्तर

क्रम सं०	परख/निरीक्षण विशेषताएं	अपेक्षाएं	निरीक्षण/परख किए जाने वाले नमूनों की संख्या	लॉट आकार/आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	कच्ची सामग्री :				
1.1	रसायनिक मिश्रण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक परीक्षण	जहां भी उत्पादक के परीक्षण प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित हैं वहीं इन विशेषताओं का स्थापन पांच परीक्षणों में से कम से कम एक बार किया जाएगा।
1.2	यांत्रिक विशेषताएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक परीक्षण	
2.	संघटक :				
2.1	कार्य कोशल और फिनिश	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक परीक्षण	
2.2	विमाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक परीक्षण	
2.3	रसायनिक/भौतिक विशेषताएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक परीक्षण	
3.	प्रक्रिया नियंत्रण :				
3.1	ठलाई :				
3.1.1	चाक्षुष तथा विसाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक दिन का उत्पादन	
3.1.2	तनन सामर्थ्य/अनुप्रस्थ शक्ति दीर्घिकरण तथा कठोरता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक दिन का उत्पादन	
3.1.3	रसायनिक संरचना	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक दिन का उत्पादन	

1	2	3	4	5	6
3.1.4	जलय परीक्षण (जहाँ अपेक्षित हों)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक दिन का उत्पादन	
3.2	यंत्रीकरण :				
3.2.1	चाक्षुष तथा विमाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक दिन का उत्पादन	
3.3	दाब :				
3.3.1	चाक्षुष तथा विमाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
3.4	ताप अभिक्रिया :				
3.4.1	तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक मूल्य	
3.4.2	कठोरता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक मूल्य	
3.4.3	चाक्षुष	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक मूल्य	
3.5	लेपन :				
3.5.1	उष्मक संकेन्द्रण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.2	उष्मक तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.3	वोल्टता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.4	प्रवाह	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.5	परीक्षण :				
3.5.5.1	लेपन परत की मोटाई	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.5.2	आसंजन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.5.5.3	लवण फुहार	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.6	वैलिडिंग गढ़ाई :				
3.6.1	चाक्षुष	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक टुकड़ा		
3.6.2	विमाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक टुकड़ा	प्रत्येक बैच	
3.6.3	वैलड परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.7	संशोधन :				
3.7.1	विस्तारिता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.7.2	वैक्यूम गेज गठन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	

1	2	3	4	5	6
3.8	डाई कास्टिंग				
3.8.1	डाई तथा धातु का ताप-मान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.8.2	ड्राई का बनाव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.8.3	चाक्षुष	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक टुकड़ा		
3.8.4	दशर गेज	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक टुकड़ा		
3.9	वसांतरकृत				
3.9.1	उष्णक संरचना	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.9.2	उष्णक तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.9.3	चाक्षुष	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.10	सेकना				
3.10.1	तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.11	संमजन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक		
3.12	पेंट करना				
3.12.1	शाट ब्लास्ट सहित सतह तैयार करना	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.12.2	विस्कासिता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.12.3	तापमान	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.12.4	आंसजन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.12.5	पेंट परत की मोटाई	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.13	वाइडिंग (कुण्डलन)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.13.1	घुमाव/अनुपात की संख्या	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.13.2	कुण्डल प्रतिरोध	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
3.13.3	उष्मानेधी	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	प्रत्येक बैच	
4.	उत्पाद नियंत्रण				

1	2	3	4	5	6
4.1	नित्यक्रम और प्रतिग्रहण परीक्षण नोट : यद्यपि प्रत्येक मद की दैनिक जांच के लिए लाया जाएगा परन्तु अनु-मोदित जांच निम्नलिखित के अनुसार होगी। (स्विच गियर और नियंत्रण-गियर पर, उप-युक्तता के आधार पर सुसंगत मानक विनिर्देश में दिए गए के अनुसार निम्नलिखित परीक्षण का कोई अन्य परीक्षण किए जाएंगे)				
4.1.1	सर्किट ब्रेकरस				
क.	उच्च वोल्टता परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
ख.	अधिक धारा यंत्र अंशशोधन परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
ग.	संचालन परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
घ.	अंशशोधन नियुक्त	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
ङ.	विद्युत रहित परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
च.	मुख्य सर्किटों के प्रति-रोध माप	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
छ.	स्वयं री-क्लोजर और सहायक सर्किट पर एक मिनट अधिक क्षमता की वोल्टता परख की जाएगी।	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
ज.	चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
4.1.2	एयर ब्रेक स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच
क.	संचालन परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	मानक के	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच

1	2	3	4	5	6
ख. विद्युत् रहित परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ग. चाक्षुष और विभीष जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4.1.3 टॉगल स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. उच्च वोल्टता परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. उष्मासंघाति प्रति-परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ग. मिलीवाल्ड विन्डु पात परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
घ. अधिक भार परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ङ. परिचालन दाव परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
च. स्विचिंग यंत्रावली (यंत्रचक्रना)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
छ. चाक्षुष और विभीष जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4.1.4 नियंत्रण स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. सामान्य मशीनी निरीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. उच्च वोल्टता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ग. मंचालन सीमाओं का स्थापन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
घ. निर्माण और तोड़ने की क्षमता के अनुपात के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		

1	2	3	4	5	6
	उ. चाक्षुष और विभीष जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
4.1.5	भयोजन (अधिग) रिच				
	क. शक्ति आवृत्ति बोल्टता गुणक परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	ख. सहायक (अतिरिक्त) सर्किट पर शक्ति आवृत्ति बोल्टता	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	ग. मुख्य सर्किट प्रतिरोध का माप	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	घ. संतोषजनक संचालन को प्रभावित करने के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	उ. चाक्षुष और विभीष परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
4.1.6	प्रवर्तक (मोटर-स्टार्टर)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए. क्यू. एल. मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	क. संचालन परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	ख. विद्युत रहित परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	ग. आटो ट्रांसफार्मर टैपस पर बोल्टता का सत्यापन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	घ. मोटर सिरों का सत्यापन जिनका पक्ष क्रम आरंभ और स्टार्ट दोनों स्थिति में एक सा रहता है।	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	उ. प्रारम्भिक प्रतिरोध मूल्य का सत्यापन जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
	च. चाक्षुष और विभीष जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
4.1.7	बम नलिकाओं सहित अन्तर्मेयक बस छे	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	



1	2	4	5	6
क. शक्ति आवृत्ति वोल्टता सह्यता परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ख. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
4. 1. 8 मेलक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
क. संचालन परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ख. विद्युत रहित परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ग. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
4. 1. 9 फ्यूज, फ्यूज बोर्ड और कट आउट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
क. बाहरी परिवर्तनशीलता की जांच के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ख. विद्युत शाक की सुरक्षा के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ग. आर्द्रता प्रतिरोधक के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
घ. विद्युत क्षमता और पृथक्करण (रोधन) प्रतिरोधक के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ङ. मशीनी क्षमता के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
छ. निर्वन्त दाब के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
ज. तापमान वृद्धि के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	
झ. जल शोषण के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच	

1	2	3	4	5	6
ट. उच्च बोल्टता के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ठ. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4. 1. 10 विभाजित स्तम्भ (पिलर)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. उच्च बोल्टता परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. चाक्षुष और विमीय	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4. 1. 11 विद्युत चालित गेट के अन्त के बक्से	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. उच्च बोल्टता परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. उत्पादन परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन के प्रत्येक बैच		
ग. मिलीवाल्ड पात परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
घ. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4. 1. 12 नियोजक (अ.इसोलेटर)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. मिलीवाल्ड पात परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. मुख्य सर्किट पर शक्ति आवृत्ति बोल्टता गुष्क परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ग. सहायक सर्किट पर शक्ति आवृत्ति बोल्टता परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए० यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
घ. मुख्य सर्किट के प्रति रोधक का माप	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए० क्यू० एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		

1	2	3	4	5	6
ड. संतोषजनक संचालन को प्रमाणित करने के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
च. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4.1.13 विद्युत शक्ति सेलक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
क. पतन परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ख. प्रतिरोधक जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
ग. गाल्वनीकृत परख (जहां लागू हो)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
घ. चाक्षुष और विमीय जांच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	ए०क्यू०एल० मानक के आधार पर	विनिर्माण की एक जैसी दशा के अधीन उत्पादन का प्रत्येक बैच		
4.2 प्रकार परख					
नोट : (स्विच गियर और नियंत्रण गियर पर उपयुक्तता के आधार पर सुसंगत मानक विनिर्देश में दिए गए निम्नलिखित परीक्षण या अन्य परीक्षण किए जाएंगे)।					
4.2.1 तापमान वृद्धि के लिए परख	मानक विनिर्देशों के अनुसार	न्यूनतम दो नमूनों सहित अभिलिखित पड़ताल के आधार पर निश्चित किया जाएगा।	जब कभी भी कच्चे माल के प्रकार को बदला जाएगा सभी प्रकार परखों के लिए दो नमूनों की जांच की जाएगी और नयी धातु के प्रारंभ में ही स्विच गियर और नियंत्रण गियर उत्पादन के लिए पास किए जाएंगे।		
4.2.2 रोधन प्रतिरोधक परख					
4.2.3 विद्युत रहित गुणों की जांच					
4.2.4 उच्च वोल्टता परख					
4.2.5 आवेग वोल्टेज परख					
4.2.6 एक मिनट शक्ति आवृत्ति वोल्टता शुष्क तथा गीली परख					
4.2.7 शार्टसकिट निर्माण और ढाड़ने की क्षमता के लिए परख					
4.2.8 शार्ट सकिट क्षमता परख					
4.2.9 अधिक भार निष्पादन परख					

1	2	3	4	5	6
3. 2. 10	अधिक धारा यंत्र अंश शोधन परख				
4. 2. 8	शार्ट सर्किट क्षमता परख				
4. 2. 9	अधिक भार निष्पादन				
4. 2. 10	अधिक धारा यंत्र अंश शोधन परख				
4. 2. 11	मशीनी तथा विद्युतीय क्षमता परीक्षा परख				
4. 2. 12	मुख्य सर्किट के प्रति रोधक का माप				
4. 2. 13	समय/धारा विशेषताएं परख				
4. 2. 14	लचीली कोर्ड परख				
4. 2. 15	शाक परख				
4. 2. 16	मशीनी शक्ति के लिए परख				
4. 2. 17	परिचालन वायु परख				
4. 2. 18	तोड़ने की क्षमता के लिए परख				
4. 2. 19	जल अवशोषण के लिए परख				
4. 2. 20	चीनी मिट्टी की सामग्री के लिए परख				
4. 2. 21	प्रज्वलन परख				
4. 2. 22	संरचनात्मक सर्किट की निरन्तरता के लिए जांच				
4. 2. 23	तनम परख				
4. 2. 24	निर्माण क्षमता, तोड़ने की धारा तथा शार्ट समय धारा परख				
4. 2. 25	संचारन परख				
4. 2. 26	अर्थशस्त्रियों के निर्माण क्षमता के सत्यापन के लिए परीक्षण				
5.	माप पद्धति नियंत्रण				
5. 1	उपस्कर तथा गैज सहित तापमान गैज, वायु गैज आदि सहित गैज	परिशुद्धता	प्रत्येक टुकड़ा	निरन्तर आंशिक आवृत्ति पर	
5. 2	जिग्स और फिसर	परिशुद्धता	प्रत्येक टुकड़ा	नियमित आंशिक आवृत्ति	
6.*	पैकिंग				
6. 1	रूप सज्जा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित जांच के आधार पर	प्रत्येक परेक्षण	

1	2	3	4	5	6
6.2	पात परख	नीचे दिए के अनुसार	एक		प्रत्येक परेषण
6.3	रोलिंग परख	नीचे दिए के अनुसार	एक		प्रत्येक परेषण
6.4	जल फुहार परख	नीचे दिए के अनुसार	छ: महीने में एक बार		प्रत्येक डिजाइन

\*पैकेज की अच्छी फिनिश होगी और देखने में सुन्दर होंगे। पैकेजों में रखी अन्तर्वस्तु इस प्रकार से पैक की जाएगी कि वह नीचे दिए गए पात परख, रोलिंग परख और जल फुहार परख को सहन कर सके।

- (i) पात परख (केवल 37 किलोग्राम तक के भार तक निर्बन्धित होगा) 150 सें.मी० की ऊँचाई से गिराया जाने वाला पैकेज एक बार बड़ी समतल सतह पर एक बार लम्बे किनारे पर एक बार उसके किसी भी किनारे पर गिराया जाएगा।
- (ii) रोलिंग परख (केवल 500 किलोग्राम तक के भार तक निर्बन्धित होगा) रोलिंग करने के लिए पैकेज को इसके किसी भी ओर 6 मीटर आगे की तरफ तथा 6 मीटर पीछे की तरफ या 12 मीटर एक ही तरफ रोल किया जायगा।
- (iii) जल फुहार परख—पैकेजों को पांच मिनट के लिए सामान्य आकस्मिक मानसून बौछार के समतुल्य जल फुहार में रखा जाएगा।

[सं० 6(6)/83-ई०आई० एण्ड ई०पी०]  
सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE

### ORDER

New Delhi, the 18th August, 1983

**S.O. 3363.**—Whereas the Central Government is of the opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India that Switchgear and Controlgear shall be subjected to Quality Control and Inspection prior to export;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of Rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Commerce No. S.O. 1090, dated the 31st March, 1979, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within fortyfive days of the date of publication of this Order in the Gazette of India, to the Export Inspection Council, Pragati Tower, 11th Floor, 26-Rajendra Place, New Delhi-110008.

### PROPOSALS

(1) To notify that Switchgear and Controlgear shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Switchgear and Controlgear (Quality Control and Inspection) Rules, 1983 set out in Annexure 'A' to this Order as the type of quality control and inspection, which shall be applied to such Switchgears and Controlgears prior to export.

(3) To recognise—

(a) National and International standards.

(b) Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council.

(c) The contractual specifications for consignments, for orders secured by the Manufacturers' Exporters immediately prior to introduction of compulsory

Quality Control and Inspection and thereafter upto 60 days from the date of introduction of compulsory Quality Control and Inspection.

(4) To prohibit the Export in the course of international trade of such Switchgears and Controlgears unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the Agencies recognised or established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Switchgears and Controlgears satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy or carry a mark or seal recognised by the Central Government under section 8 of the said Act.

2. Nothing in this Order shall apply to :—

- (a) The export by land, sea or air of bonafide samples of Switchgear and Controlgear to prospective buyers.
- (b) The consignments that have already left the exporter's/ manufacturer's premises immediately prior to the introduction of the compulsory Quality Control and Inspection.

3. In this Order Switchgear and Controlgear shall mean any of the Switchgears and Controlgears or a combination thereof mentioned in the Schedule given below :—

### SCHEDULE

Sl. No. Switchgear and Controlgear

1. Circuit Breakers.
2. Air Break, Toggle, Control and Earthing Switches
3. Motor starters.
4. Inter Connecting Bus-Bars including Bus-ducts.
5. Contactors.
6. Fuses, Fuse-Boards and cut-outs
7. Distribution Pillars
8. Electrically operated Gate-end boxes
9. Disconnectors (Isolators)
10. Electric power Connectors.

### ANNEXURE 'A'

Draft Rules proposed to be made under Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Switchgear and Controlgear (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act ;
- (c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;
- (d) "Switchgear and Controlgear" means any of the Switchgears and Controlgears or a combination thereof mentioned in the Schedule-I given below :—

#### SCHEDULE-I

##### SI. No. Switchgear and Controlgear

1. Circuit Breakers.
2. Air Break, Toggle, Control and Earthing Switches.
3. Motor starters.
4. Inter Connecting Bus-Bars including Bus- ducts.
5. Contactors.
6. Fuses, Fuse-Boards and cut-outs.
7. Distribution Pillars.
8. Electrically operated Gate-end boxes.
9. Disconnectors (Isolators).
10. Electric power Connectors.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Switchgears and Controlgears for export shall be carried out with a view to seeing that the Switchgears and Controlgears conform to the standard specifications recognised by the Central Government Under section 6 of the Act, namely; National and International standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council :

either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality controls as specified in Annexure-I to this notification,

or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in annexure II to this notification.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Switchgear and Controlgear shall give an intimation in writing to the Agency furnishing therein details of the contractual specification alongwith a copy of the export contract or order to enable the Agency to carry out inspection in accordance with rule 3.

(2) For export of Switchgear and Controlgear manufactured by exercising adequate inprocess quality controls as laid down in Annexure-I and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a panel of experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Switchgear and Controlgear intended for export has been manufactured by exercising adequate quality controls as laid down in Annexure-I, and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the Agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than 7 days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while the intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2) the Agency.

(a) On satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer has exercised adequate quality controls as laid down in Annexure-I and followed the instruction, if any, issued by the Council/Agency in this regard to manufacture the product so as to conform to the standard specifications recognised for the purpose, shall, within three days, issue a certificate declaring the consignment of Switchgear and Controlgear as export-worthy. In case where the manufacturer is not the exporter, the consignment shall be physically verified and such verification and/or inspection, if necessary shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with.

The Agency shall, however, carry out the spot-check of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing Unit at regular interval to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the Unit. If the manufacturing Unit is found not maintaining the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council/Agency, the Unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control drills. In such cases, the Unit, if so desires, shall apply afresh for adjudgment of the adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure-I had been exercised, on satisfying itself that the consignment of Switchgear and Controlgear conforms to the standard specification recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Annexure-II, shall within seven days of carrying out such inspection, issue a certificate declaring the consignment of Switchgear and Controlgear as exportworthy;

Provided that where the Agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of Switchgear and Controlgear as exportworthy and shall communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reason therefor. (6) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5)(b), the Agency shall, immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in the manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either—(a) at the premises of the manufacturer of such products; or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided required facilities for inspection exist therein.

6. Inspection fee.—The inspection fee shall be paid by the manufacturers/exporters to the Agency as under :

(1) For inspection under rule 3(a) at the rate of 0.2 per cent of F.O.B. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment.

(2) For inspection under rule 3(b) at the rate of 0.4 per cent of F.O.B. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment.

(3) A rebate of at the rate of 10 per cent on the rate of inspection fee given in sub-rule (1) and (2) shall be given to small scale units registered with the concerned State Government or Union Territory.

7. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Switchgear and Controlgear prior to export and Switchgear and Controlgear so marked shall not be subjected to any inspection under rule 3.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts constituting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

#### ANNEXURE I

(See rule 3(a) of Annexure 'A' of the notification) The quality control of the Switchgear and Controlgear shall be exercised by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, prevention and packing of the products as laid down together with the levels of control as set out in the Schedule II appended hereto.

1. Bought out materials and components control.—(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirement of the purchase specifications or in the absence of such test certificates samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counter-checked atleast one in five consignments to verify their correctness.

(c) The incoming consignment shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After inspection and testing, systematic method shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for various processes of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Sampling (Wherever required) for checking the conformity of the processed materials with the process specifications shall be based upon the recorded investigation.

(d) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls adopted during the process of manufacture.

3. Product Control.—(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on recorded investigations.

(c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the details of product testing.

4. Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards :—

5. Preservation Control.—(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

(b) The products shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control.—Specifications shall be laid down for packing the product(s) as well as for export packages and the same shall be strictly adhered to.

#### ANNEXURE—II

[See rule 3(b) of the Annexure 'A' of the Notification]

1. The consignments of Switchgear and Controlgear shall be subject to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under Section 6 of the Act.

2. In the absence of any specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling and criteria of conformity, the same as laid down below shall become applicable.

2.1 The acceptance tests as given in the relevant national standards shall be carried out on the samples selected from the lots as given in Table-I below and the lots shall be accepted or rejected on the basis of criterion for conformity given in the Table.

TABLE—I

SAMPLE SIZE AND CRITERION FOB CONFORMITY

Lot Size	First Sample	Second Sample	First Rejection	Second Rejection
1	2	3	4	5
Upto 50	5	5	2	2
51 to 100	8	8	2	2
101 to 300	13	13	2	2
301 to 500	20	20	2	3
501 and above	32	32	3	4

Note :—The lot shall mean all Switchgears and Controlgears of the same make, model and type grouped together in a consignment.

2.2 In order to ensure the randomness of selection, procedure given in IS : 4905:1968 (Methods of Random Sampling) shall be followed.

2.3 The Switchgears and Controlgears selected at random according to Col. 1 and 2 of Table-I, shall be subjected to the acceptance tests specified in the individual Switchgear and Controlgear specification. A Switchgear and Controlgear failing to satisfy any of the acceptance test, shall be considered as defective. The lot shall be considered as conforming to the requirements if no defective is found in the sample and shall be rejected if the number of defectives found in the sample is greater than or equal to the first rejection number (see Col. 4). If the number of defectives is less than the first rejection number, second samples as given in Column 3 shall be drawn at random and tested. If the number of defectives found in the combined sample is greater than or equal to the second rejection number (see Col. 5) the lot shall be rejected, otherwise the lot shall be accepted.

2.4 Before undertaking the inspection, the Agency shall satisfy itself that the routine tests on each Switchgear and Controlgear as given in the relevant standard have been carried out on the consignment by the exporter/manufacturer.

2.5 Two samples belonging to one out of ten consecutive consignments (or atleast once in a year) of Switchgear and Controlgear of same type and rating offered for inspection by exporter/manufacturer shall be drawn and tested for type tests as given in the standard specification and both the samples should pass the type tests.

2.6 Methods of testing : if not otherwise specified in the export contract, the testing procedure shall be as prescribed in the relevant national standard or the latest version of Indian Standard specification.

### SCHEDULE-II

(See Rule-3)

#### LEVELS OF CONTROL

Sl. No.	Test/Inspection Characteristics	Requirements	No. of Samples to be inspected/frequency tested	Lot Size/frequency	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

#### 1. Raw-Materials :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Components				
2.1	Workmanship and finish	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each consignment.	
2.2	Dimensions.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each consignment.	
2.3	Chemical/Physical properties.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each consignment.	
3.	Process Control				
3.1	Casting				
3.1.1	Visual & Dimensions.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each day's production	
3.1.2	Tensile strength, transverse strength.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each day's production.	
3.1.3	Chemical composition.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each day's production.	
3.1.4.	Hydraulic test (Whenever required)	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each day's production.	
3.2	Machining				
3.2.1.	Visual and dimensional.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each day's production.	
3.3	Pressing				
3.3.1	Visual and dimensional.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
3.4	Heat Treatment				
3.4.1	Temperature.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each charge.	
3.4.2	Hardness.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each charge.	
3.4.3	Visual	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each charge.	
3.5	Electroplating				
3.5.1.	Bath concentration.	As per standard specification	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.5.2	Bath temperature.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	

1	2	3	4	5	6
1.1	Chemical Composition.	As per Standard Specification.	On the basis of Standard A.Q.L.	Each Consignment	Wherever Supported by producer's test
1.2	Mechanical Properties	As per Standard Specification.	On the basis of Standard A.Q.L.	Each consignment.	certificate these characteristics shall be verified at least once in five consignments.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.5.3	Voltage.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.5.4	Current.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.5.5	Tests.				
3.5.5.1	Thickness of coating.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.5.5.2	Adhesion.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.5.5.3	Salt spray.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.6	Welding Fabrication				
3.6.1	Visual.	As per standard specification.	Each piece	Each batch.	
3.6.2	Dimensions.	As per standard specification.	Each piece.	Each batch.	
3.6.3	Weld test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.7	Impregnation				
3.7.1	Viscosity	As per standard specification	On the basis of recorded investigations	Each batch	
3.7.2	Vacuum gauge reading	As per standard specification	On the basis of recorded investigations	Each batch	
3.8	Die Casting				
3.8.1	Temperature of die and metal.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch	
3.8.2	Pressure of casting.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch	
3.8.3	Visual.	As per standard specification.	Each piece.		
3.8.4	Crack detection.	As per standard specification.	Each piece.		
3.9	Degreasing				
3.9.1	Batch composition.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch	
3.9.2	Batch temperature.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch	
3.9.3	Visual.	As per standard specifications.	Each piece.		
3.10	Baking				
3.10.1	Temperature.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch	
3.11	Assembly	As per standard specification.	Each.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.12	Painting				
3.12.1	Surface preparation including shot blasting.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.12.2	Viscosity.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.12.3	Temperature.	As per standard specification.	On the basis of recorded investigations.	Each batch.	
3.12.4	Adhesion.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Production of each batch, under identical conditions.	
3.12.5	Coating thickness.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Production of each batch under identical conditions.	
3.13.	Winding.				
3.13.1	Number of turns/ratio.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.13.2	Winding resistance.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
3.13.3	Insulation resistance.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch.	
4.	Product control				
4.1	Routine/acceptance tests Note : While the routine tests shall be carried out on each item, the acceptance test shall be carried out as given below.  Depending upon applicability, the following tests and any other test as given in the relevant standard specification shall be carried out on Switchgears and Controlgears.				
4.1.1	Circuit Breakers				
(a)	High voltage test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(b)	Over current device calibration test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(c)	Operation test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(d)	Calibration of releases.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(e)	Di-electric test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(f)	Measurement of resistance on main circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	

1	2	3	3	5	6
	(g) One-minute power frequency voltage dry with stand test on the auto recloser and auxiliary circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(h) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
4.1.2	Air Break Switches				
	(a) Operation test	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(b) Di-electric test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(c) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
4.1.3	Toggle switches				
	(a) High voltage test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(b) Insulation resistance test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(c) Milli-volt drop test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(d) Over load test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(e) Operating force test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(f) Switching mechanism test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(g) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
4.1.4	Control Switch				
	(a) General mechanical inspection.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(b) High voltage test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(c) Verification of operating limits.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(d) Test for rated making & braking capacities.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.
	(e) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.		Each batch of production under identical conditions of manufacturing.

1	2	3	4	5	6
<b>4.1.5 Earthing Switches</b>					
(a)	Power frequency voltage dry test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(b)	Power frequency voltage on auxilliary circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(c)	Measurement of resistance of the main circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(d)	Test to prove satisfactory operation.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(e)	Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
<b>4.1.6 Motor Starters</b>					
(a)	Operation test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(b)	Di-electric test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(c)	Verification of voltage at the auto-transformer taps.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(d)	Verification at the motor terminals that phase sequence is same in both the starting and the FULL-ON positions of starter.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(e)	Verification of resistance value of the starting resistance.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(f)	Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
<b>4.1.7 Inter-connecting Bus-bars including bus-ducts</b>					
(a)	Power frequency voltage withstand test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(b)	Visual and dimensional checks	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
<b>4.1.8 Contactors</b>					
(a)	Operating test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
(b)	Di-electric test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	

1	2	3	4	5	6
	(c) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.1.9	Fuses, Fuse board and Cut outs.				
	(a) Test for checking non-inter changeability.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(b) Test for protection against electric shock.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(c) Test for moisture resistance.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(d) Test for insulation resistance and electric strength.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(e) Test for heating.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(f) Test mechanical endurance.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(g) Test for withdrawal force.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(h) Test for temperature rise.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(i) Test for water absorption.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(j) Test for high voltage.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(k) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.1.10	Distribution Pillars				
	(a) High voltage test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(b) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.1.11	Electrically operated gate-end box				
	(a) High voltage test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	

1	2	3	4	5	6
	(b) Performance test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(c) Milli-volt drop test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(d) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.1.12 Disconnectors (Isolators)					
	(a) Milli volt drop test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(b) Power frequency voltage dry test on main circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(c) Power frequency voltage test on auxiliary circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(d) Measurement of resistance of main circuit.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(e) Test to prove satisfactory operation.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(f) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.1.13 Electric power Connectors					
	(a) Tensile test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(b) Resistance test.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(c) Galvanising test (Where applicable)	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
	(d) Visual and dimensional checks.	As per standard specification.	On the basis of standard A.Q.L.	Each batch of production under identical conditions of manufacturing.	
4.2 Type Tests					
Note :—Depending upon applicability, the following tests and any other test as given in the relevant standard specification shall be carried out on Switchgear and Controlgear.					
4.2.1	Temperature rise test.	As per standard specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation with a minimum of two samples.	As and when the type of raw material is changed two samples shall be tested for all the type tests and they shall pass before production of Switchgear and Controlgear made out of new material is commenced.	
4.2.2	Insulation resistance test.				
4.2.3	Verification of dielectric properties.				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.2.4	High voltage test.				
4.2.5	Impulse voltage test.				
4.2.6	One-minute power frequency voltage dry and withstand test.				
4.2.7	Short circuit making and breaking capacities test.				
4.2.8	Short circuit capacity test.				
4.2.9	Over load performance test.				
4.2.10	Over current device calibration test.				
4.2.11	Mechanical and Electrical endurance tests.				
4.2.12	Measurement of resistance of main circuit.				
4.2.13	Time/current characteristics test.				
4.2.14	Flexible cord test.				
4.2.15	Shock test.				
4.2.16	Test for mechanical strength.				
4.2.17	Test for withdrawal force.				
4.2.18	Test for breaking capacity.				
4.2.19	Test for water absorption.				
4.2.20	Test for ceramic materials.				
4.2.21	Ig tition test.				
4.2.22	Verification of continuity of protective circuit.				
4.2.23	Tensile test.				
4.2.24	Making capacity breaking current & short time current tests.				
4.2.25	Operation test.				
4.2.26	Test to prove making capacity of earthing switches.				
5.	Metrological Control				
5.1	Instruments & gauges including temperature gauge, pressure gauge etc.	Accuracy.	Each piece.	At a regular periodic frequency.	
5.2	Jigs and fixtures.	Accuracy.	Each piece.	At a regular periodic frequency.	
6.	*Packing				
6.1	Appearance.	As per standard specification.	On the basis of the recorded investigations.	Each consignment.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.2	Drop test.	As given below.	One		Each consignment.
6.3	Rolling test.	As given below.	One		Each consignment.
6.4	Water spraying test.	As given below.	Once in six months.		Each design.

\*The packages shall be well finished and have a good appearance. The inner content of the packages shall be so packed as to withstand drop test, rolling test and water spraying test as given below :—

- (i) Drop test (to be restricted to head load upto 37 kgs.). The package to be dropped from a height of 150 cms, once on the largest flat surface, once on the largest edge and once on any corner of its own.
- (ii) Rolling test (to be restricted upto a weight of 500 kgs.) The package to be subjected to rolling on its sides either 6 metres forward and 6 metres backwards or twelve metres in one direction only.
- (iii) Water spraying test—The packages to be exposed against a water spray equivalent to a normal sudden monsoon shower for five minutes.

[No. 6(6)/83-EI&EP]  
C.B. KUKRETI, Joint Director

### (बस्त्र विभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1983

का० आ० 3364.—भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अन्तर्गत बम्बई में पंजीकृत भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 46(क) के अनुसरण में भारत सरकार श्री एस० के० मिश्र, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (हथकरघा) को इस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल प्रभाव से तथा दो वर्षों की अवधि के लिए एतद्वारा मनोनीत करती है।

[का० सं० 26011/18/83-रेशम]

के० चौधुरी, उप सचिव

(Department of Textiles)

New Delhi, the 11th August, 1983

S.O. 3364.—In pursuance of Article 46(a) of the Articles of Association of the Indian Silk Export Promotion Council registered in Bombay under section 25 of the Indian Companies Act 1956 (41 of 1956), the Government of India hereby nominates Shri S. K. Misra, Additional Secretary and Development Commissioner (Handlooms) to serve as Chairman of the Council with immediate effect and for a period of two years.

[F. No. 26011/18/83-Silk]

K. CHAUDHURI, Dy. Secy.

मुख्य निर्यातक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1983

का० आ० 3365.—श्री अब्दुल जलील अब्दुल रहीम; मालाबार हाउस, करुणागपल्ली, केरल की आरबी जी एल

डीजल 82 माडल कार के आयात के लिए केवल 55,000/- रुपए का सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/0391052 दिनांक 14-6-82 प्रदान किया गया था। आवेदक ने उपर्युक्त सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है। आगे यह भी बताया गया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराया गया था और इस प्रकार उसके मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया है।

2. अपने तर्कों के समर्थन में लाइसेंसधारी ने यथोचित न्यायिक प्राधिकारी के सम्मुख विधिबद्ध शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूँ कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी/जे/0391052 दिनांक 14-6-82 आवेदक से खो गया है। समय-समय पर यथा संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उप खंड 9 (सीसी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए सर्वश्री अब्दुल जलील अब्दुल रहीम को जारी किया गया उक्त मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० पी०/जे/0391052 दिनांक 14-6-82 एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

3. सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है।

[सं० ए-40/82-83-बीएलएस/877]

एन० एस० कृष्णामूर्ति, उप मुख्य निर्यातक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 5th August, 1983

S.O. 3365.—Shri Abdul Jaleel Abdulrahim, Malabar House, Karunagapalli, Kerala was granted a Customs Clearance



Permit No. P/J/0391052 dated 14-6-82 for Rs. 55,000 only for import of Audi. GL Diesel 82 Model car. The applicant has applied for issue of Duplicate copy of the above mentioned Customs clearance Permit on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further been stated that the original CCP was not registered with any Customs authority and such the value of the CCP has not been utilised at all.

2. In support of this contention, the licensee has filed an affidavit duly sworn before appropriate judicial authority. I am accordingly satisfied that the original CCP No. P/J/0391052 dated 14-6-82 has been lost by the applicant. In exercise of the powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended from time to time, the said original CCP No. P/J/0391052 dated 14-6-82 issued to Shri Abdul Jaleel Abdulrahman is hereby cancelled.

3. A duplicate copy of the Customs Clearance Permit is being issued to the party separately.

[No. A-40/82-83/BLS/877]

N. S. KRISHNAMURTHY, Dy. Chief Controller  
of Imports and Exports

### आदेश

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1983

का० का० 3366.—सर्वश्री नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, 62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को आई डी ए क्रेडिट सं० 1027-आई एन के अधीन पश्चिम जर्मनी से 420 के० वी० सर्किट ब्रेकर शिंगरौली के आयात के लिए 10,34,300/- रुपए (दस लाख चौतीस हजार तीन सौ रुपए) का आयात लाइसेंस सं० जी/एच/2039598 दिनांक 19-9-81 जारी किया गया था।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। उन्होंने यह भी बताया है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा-शुल्क प्राधिकारी मद्रास के पास पंजीकृत करवाई गई थी और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति का 10,17,081.40 रु० तक उपयोग किया गया है।

2. अपने इस तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत साक्ष्यांकित शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि आयात लाइसेंस सं० जी/एच/2039598 दिनांक 19-9-81 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9 (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि० को जारी की गई मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सं० 2039598 दिनांक 19-9-81 को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

589 GI/83-5

3. आवेदक को 17,218.60 रु० के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रहा है।

[सं० सी० जी०-2/एच०ई०पी० (यू-6-7)/81-82/577]

### ORDER

New Delhi, the 10th August, 1983

S.O. 3366.—M/s. National Thermal Power Corporation Ltd. 62-63, Nehru Place, New Delhi-110019 were granted an import licence No. G/H/2039598 dated 19-9-81 for Rs. 10,34,300/- (Rupees ten lakhs thirty four thousand and three hundred) for import of 420 KV Circuit Breaker Shingrauli from West Germany, issued under IDA Credit No 1027-IN.

The firm has applied for issue of duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Madras Customs Authority and as the value of Customs purposes copy has been utilised to extent of Rs. 10,17,081.40

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. G/H/2039598 dated 19-9-81 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No. 2039598 dated 19-9-81 issued to M/s. National Thermal Power Corpn. Ltd., is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence to the extent of Rs. 17,218.60 is being issued to the party separately.

[No. CGH/HEP(U-6-7)/81-82/577]

### आदेश

का० आ० 3367.—सर्वश्री नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि०, 62-63, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली की आई डी ए क्रेडिट सं०, 874-आई एन के अधीन पश्चिमी जर्मनी से 420 के० वी० सर्किट, रामगुंडम के आयात के लिए 1,04,83,500/- रु० (एक करोड़ चार लाख तिरासी हजार पांच सौ रुपए) का आयात लाइसेंस सं० जी/एच/2039599 दिनांक 19-9-81 प्रदान किया गया था।

फर्म ने उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई है अथवा अस्थानस्थ हो गई है। आगे यह बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति को मद्रास सीमा-शुल्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत कराया गया था और इस प्रकार सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति का 99,23,092.20 रुपए तक उपयोग किया गया है।

2. अपने इस तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, दिल्ली के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत साक्ष्यांकित शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि फर्म ने आयात लाइसेंस सं० जी/एच/2039599 दिनांक 19-9-81 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा

अस्थानस्थ हो गई है। यथासंशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उप-धारा 9(सीसी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि०, नई दिल्ली को जारी की गई मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति सं० जी/एच/2039599 दिनांक 19-9-81 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3. पार्टी को 5,60,407.80 रुपए के लिए उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही है।

[सं० सी जी-2/एच ई पी(यू-6-7)/81-82/578]]

पाल बेक, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

#### ORDER

S.O. 3367.—M/s. National Thermal Power Corporation Ltd. 62-63, Nehru Place, New Delhi were granted an import licence No. G/H/2039599 dated 19-9-81 for Rs. 1,04,83,500 (Rupees one crore four lakhs eighty three thousand and five hundred) for import of 420 KV Circuit, Ramagundem from West Germany issued under IDA Credit No. 874-IN.

The firm has applied for issue of duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground the original Customs Purposes copy of the licence has been misplaced. It has further been stated that the customs purposes copy of the licence was registered with Madras Customs Authority and as the value of Customs Purpose copy has been utilized to the extent of Rs. 99,23,092.20.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a notary Public Delhi. I am accordingly satisfied that the original Customs Purposes copy of import licence No. G/H/2039599 dated 19-9-81 has been misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Central Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original Customs purposes copy No. G/H/2039599 dated 19-9-81 issued to M/s National Thermal Power Corp. Ltd., New Delhi is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence to the extent of Rs. 5,60,407.80 is being issued to the party separately.

[No. CGII/HFP(U-6-7)/81-82/578]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller  
of Imports and Exports

#### भारतीय मानक संस्था

#### भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1983-07-25

क्र० आ० 3368— समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम, 1955 के विनियम, 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 263 लाइसेंसों के ध्येय नीचे अनुसूची में दिए गए हैं उनका जनवरी 1983 में नवीकरण किया गया है :

#### अनुसूची

क्रम संख्या	सी एस/एल संख्या	वैध	भारतीय मानक विनिर्दिष्ट की पद संख्या
1	2	3	4
1.0071-15	83-10-01	83-12-31	IS : 261-1966

1	2	3	4	5
2.	00112 07	83-01-01	83-12-31	IS : 388-1972
3.	00253 19	83-01-01	83-12-31	IS : 1507-1977
4.	00339 24	82-12-01	83-11-30	IS:325-1978
5.	00361 22	82-12-16	83-12-15	IS : 916-1975
6.	00369 30	83-01-01	83-12-31	IS : 916-1975
7.	00371 24	83-01-01	83-12-31	IS : 916-1975
8.	00547 30	82-12-16	83-12-15	IS : 10 (भाग 4) —1976
9.	00591 34	82-12-01	83-11-30	IS : 1580-1969
10.	00752 33	83-01-16	84-01-15	IS : 2548-1980
11.	00839 39	82-12-01	83-11-30	IS : 1221-1971
12.	00850 34	82-12-01	83-11-30	IS : 2818(भाग 2) —1971
13.	00884 44	82-12-01	83-11-30	IS : 2566-1965
14.	01006 33	82-12-01	83-11-30	IS : 2566-1965
15.	00910 29	82-12-01	83-11-30	IS : 2566-1965
16.	00942 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566-1965
17.	00977 48	82-12-01	83-11-30	IS : 220-1972
18.	01013 09	82-06-16	83-06-15	IS : 774-1971
19.	01131 14	83-01-01	83-12-31	IS : 694-1977
20.	01146 21	82-10-16	83-10-15	IS : 226-1975
21.	01218 20	81-09-16	83-09-15	IS : 1856-1977
22.	01219 21	83-01-01	83-12-31	IS : 814 (भाग 1 और 2)-1974
23.	01319 24	83-01-16	84-01-15	IS : 2645-1975
24.	01353 26	83-01-01	83-12-31	IS : 1551-1976
25.	01613 27	83-02-01	84-01-31	IS : 2567-1978
26.	01707 32	82-11-16	83-11-15	IS : 398 (भाग I) —1976
27.	01715 32	82-12-16	83-12-15	IS : 226-1975
28.	01716 33	82-12-16	83-12-15	IS : 1977-1975
29.	01889 53	83-01-16	84-01-15	IS : 10(भाग 1) —1976
30.	02023 15	82-08-01	83-07-31	IS : 2548-1967
31.	02456 36	82-11-16	83-11-15	IS : 1165-1975
32.	02583 42	82-12-16	83-12-15	IS : 325-1978
33.	02690 44	82-11-16	83-11-15	IS : 325-1978
34.	02728 41	83-01-01	83-12-31	IS : 5086-1981
35.	02856 48	83-01-01	83-12-31	IS : 10(भाग 2) —1976
36.	02857 49	82-12-16	83-12-31	IS : 1333-1978
37.	02866 50	83-01-16	84-01-15	IS : 1322-1970
38.	02906 41	83-01-01	84-06-30	IS : 1601-1960
39.	02950 45	83-01-01	83-12-31	IS : 1222-1973
40.	02970 49	83-01-16	84-01-15	IS : 1223 (भाग I) —1970
41.	03106 21	83-01-01	83-12-31	IS : 1322-1970
42.	03126 25	82-12-01	83-11-30	IS : 2082-1978
43.	03207 25	82-12-16	83-12-15	IS : 694-1977
44.	03260 30	83-01-01	83-12-31	IS : 814 (भाग 1) —1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
45.	03279 41	83-01-01	83-12-31	IS 3196-1974	87.	05003 23	83-01-01	83-12-31	IS 398 (भाग 2) —1976
46.	03280 34	83-01-16	84-01-15	IS : 1601—1960	88.	05130 29	82-07-01	83-06-30	IS : 226—1975
47.	03283 37	83-01-01	84-06-15	IS : 434(भाग 1 और 2)—1964	89.	05131 30	82-07-01	83-06-30	IS : 1977—1975
48.	03284 38	83-01-01	84-06-15	IS : 694—1977	90.	05146 37	83-01-01	83-12-31	IS 39 (भाग 1) —1982
49.	03285 39	83-01-01	84-06-15	IS : 1544(भाग 1) —1976	91.	05378 51	83-01-16	84-01-15	IS : 1891 (भाग 1 और 2)—1978
50.	03286 40	83-01-01	84-06-15	IS : 1596—1977	92.	05554 49	83-02-01	84-01-31	IS : 633—1975
51.	03477 45	83-01-01	83-12-31	IS : 4382—1967	93.	05590 53	83-01-01	83-12-31	IS : 4174—1977
52.	03541 36	83-01-01	83-12-31	IS : 4885—1968	94.	05633 47	82-11-6	83-11-15	IS : 1239 (भाग 1) —1979
53.	03561 40	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1966	95.	05638 52	82-12-01	83-11-30	IS : 10(भाग 4) —1976
54.	03590 45	82-11-16	83-11-15	IS : 5423—1978	96.	05761 51	82-12-01	83-11-20	IS : 4323—1980
55.	03596 51	82-12-01	83-11-30	IS : 1726(भाग 2) —1974	97.	05666 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1011—1981
56.	03609 93	82-12-01	83-11-30	IS : 5455—1969	98.	05716 49	82-12-01	83-11-30	IS : 633—1975
57.	03635 41	82-12-16	83-12-15	IS : 325—1978	99.	05730 47	83-01-01	83-12-31	IS 1239 (भाग 1) —1976
58.	03667 49	83-01-16	84-01-15	IS : 2148—1968	100.	05741 50	82-12-16	83-12-15	IS : 5430—1981
59.	03848 52	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976	101.	05760 53	82-01-01	83-06-30	IS : 6914—1978
60.	04029 29	82-11-16	83-11-15	IS : 4663—1968	102.	05761 54	82-07-01	83-06-30	IS : 6915—1978
61.	0480 32	82-12-01	83-11-30	IS : 335—1972	103.	05763 56	83-01-16	84-01-15	IS: 10 (भाग 2) —1976
62.	04108 27	83-01-01	83-12-31	IS : 4246—1978	104.	05794 63	83-01-01	83-12-31	IS : 4654—1974
63.	04150 29	83-01-16	84-01-15	IS 398 (भाग 1 और 2)—1976	105.	05810 46	83-01-16	84-01-15	IS : 2465—1969
64.	04189 44	83-02-01	84-01-31	IS : 5346—1975	106.	05815 51	83-01-06	84-01-15	IS : 3865—1978
65.	04369 46	82-12-16	83-12-15	IS : 781—1977	107.	05931 54	83-01-01	83-12-31	IS : 4927—1968
66.	04375 44	82-11-16	83-11-15	IS : 2567—1978	108.	06096 49	82-12-01	83-11-30	IS : 171—1973
67.	04590 49	82-09-01	83-08-31	IS : 2548—1967	109.	06122 33	83-01-01	83-12-31	IS : 3450—1976
68.	04735 48	83-01-01	83-12-31	IS : 3062—1974	110.	06401 37	82-09-16	83-09-15	IS : 5430—1981
69.	04736 49	83-01-01	83-12-31	IS 1970 (भाग 1) —1982	111.	06428 48	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980
70.	04773 50	83-10-01	83-12-31	IS : 1971—1982	112.	06434 46	82-07-01	83-06-30	IS : 1239 (भाग 1) —1979
71.	04738 51	83-10-01	83-12-31	IS : 3897—1978	113.	06529 52	82-12-01	83-11-30	IS : 3652—1982
72.	04739 52	83-01-01	83-12-31	IS : 3652—1982	114.	06535 50	82-11-16	83-11-15	IS : 6914—1978
73.	04742 47	83-01-01	83-12-31	IS : 3634—1977	115.	06536 51	82-11-16	83-11-15	IS : 6915—1978
74.	04743 48	83-01-01	83-12-31	IS : 2928—1978	116.	06551 50	82-12-01	83-11-30	IS : 4974—1980
75.	04744 49	83-01-01	83-12-31	IS : 2870—1977	117.	06554 53	82-11-16	83-11-15	IS : 1547—1968
76.	04781 54	82-10-31	83-10-31	IS : 1186—1971	118.	06563 54	82-12-01	83-11-10	IS : 226—1975
77.	04809 49	82-12-01	83-11-30	IS : 2865—1978	119.	06579 53	82-12-16	83-12-15	IS : 6915—1978
78.	04810 42	82-12-01	83-11-30	IS : 204 (भाग 2) —1978	120.	06571 54	82-12-16	83-12-15	IS : 694—1977
79.	04852 52	82-12-01	84-03-15	IS : 398 (भाग 2) —1976	121.	06576 59	83-01-01	83-12-31	IS : 1222—1973
80.	04863 55	82-12-16	83-12-15	IS : 1322—1970	122.	06582 57	82-12-16	83-12-15	IS : 1011—1981
81.	04871 55	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (भाग 1) —1974	123.	06587 62	83-01-01	83-12-31	IS : 1161—1979
82.	04878 62	82-12-16	83-12-15	IS : 2865—1978	124.	06591 58	83-01-01	83-12-31	IS : 1161—1979
83.	04880 56	82-12-16	83-12-15	IS : 419—1967	125.	06616 50	83-01-01	83-12-31	IS : 4148—1967
84.	04888 64	82-12-16	83-12-1	IS : 633—1975	126.	06620 46	83-01-01	83-12-31	IS : 4989—1974
85.	04955 58	83-01-16	84-01-15	IS: 325—1978 & IS : 1520—1972	127.	06640 50	83-01-16	84-01-15	IS : 2325—1963
86.	04978 65	83-02-01	84-01-31	IS : 1554 (भाग 1) —1976	128.	06642 52	83-01-16	84-01-15	IS : 1223 (भाग 2) —1972
					129.	06643 53	83-01-01	83-12-31	IS : 5410—1969
					130.	06676 62	83-01-01	83-12-31	IS : 780—1980

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
131. 06773 62	83-02-01	84-01-31	IS : 1307—1973	
132. 07303 40	82-11-16	83-11-15	IS : 7577—1975	
133. 07312 41	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
134. 07317 46	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
135. 07322 43	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
136. 07326 47	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
137. 07336 49	82-11-16	83-11-15	IS : 1601—1960	
138. 07341 46	82-11-16	83-11-15	IS : 1239 (भाग 1) —1979	
139. 07348 53	82-12-01	83-11-30	IS : 565—1975	
140. 07339 54	82-12-01	83-11-30	IS : 6439—1980	
141. 07362 51	82-11-16	83-11-15	IS : 1660 (भाग 1) —1982 IS : 1660 (भाग 2 और 3 )—1972 IS : 1660 (भाग 4)—1977	
142. 07372 53	82-12-01	83-11-30	IS : 1320—1981	
143. 07385 58	82-12-01	84-02-15	IS : 398 (भाग 1) —1976	
144. 07407 47	83-01-01	84-04-30	IS : 934—1976	
145. 07419 51	82-07-01	83-06-30	IS : 1786—1979	
146. 07425 49	83-01-01	83-12-31	IS : 10 (भाग 4) —1976	
147. 07427 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1970 (भाग 1) 1974	
148. 07439 55	83-01-01	83-12-31	IS : 261—1966 I	
149. 07455 55	83-01-16	84-01-15	IS : 3906 (भाग 1974	
150. 07456 56	83-01-16	84-01-15	IS : 5662—1970	
151. 07466 58	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
152. 07469 61	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
153. 07470 54	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
154. 07486 62	83-02-01	84-01-31	IS : 694—1977	
155. 07520 47	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
156. 08114 41	82-11-16	83-11-15	IS : 6595—1980	
157. 08116 43	83-11-16	83-11-15	IS : 2339—1963	
158. 08142 45	82-11-16	83-11-15	IS : 10 (भाग 4) 1976	
159. 08153 48	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	
160. 08190 53	82-12-16	83-12-15	IS : 3906 (भाग 1) —1982 1982—	
161. 08217 47	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976	
162. 08235 49	83-01-01	83-12-31	IS : 4654—1974	
163. 08252 50	82-12-01	83-11-30	IS : 2874—1964	
164. 08256 54	82-12-16	83-12-15	IS : 7406 (भाग 1) —1974	
165. 08263 53	83-01-01	83-12-31	IS : 1061—1975	
166. 08286 60	83-01-16	84-01-15	IS : 1795—1974	
167. 08289 63	83-01-16	84-01-15	IS : 848—1974	
168. 08292 58	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
169. 08296 62	82-12-16	83-12-15	IS : 1943—1964	
170. 08301 42	83-01-16	84-01-15	IS : 3975—1979	
171. 08305 46	83-01-16	84-01-15	IS : 694—1977	
172. 08314 47	83-01-16	84-01-15	IS : 1165—1975	
173. 08369 62	82-04-16	83-04-15	IS : 5277—1978	
174. 08384 61	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	
175. 08476 64	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	
176. 08529 60	82-04-16	83-06-30	IS : 1161—1979	
177. 09028 48	82-10-16	83-10-15	IS : 4142—1967	
178. 09099 63	82-11-16	83-11-15	IS : 8960—1978	
179. 09133 48	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980	
180. 09137 52	83-01-01	83-12-31	IS : 7593 (भाग 1) —1975	
181. 09139 54	82-12-01	83-11-30	IS : 612—1971	
182. 09142 49	82-12-01	83-11-30	IS : 8960—1978	
183. 09154 53	82-12-01	83-11-30	IS : 371—1979	
184. 09156 55	82-12-01	83-11-30	IS : 6595—1980	
185. 09157 56	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (भाग 4) —1976	
186. 09158 57	82-12-01	83-11-30	IS : 7370—1974	
187. 09162 53	82-12-01	83-11-30	IS : 9128—1979	
188. 09178 61	82-12-16	83-12-15	IS : 2509—1973	
189. 09184 59	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1979	
190. 09185 60	82-12-16	83-12-15	IS : 694—1977	
191. 09186 61	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (भाग 1)—1976	
192. 09189 64	82-12-16	83-12-15	IS : 2713 (भाग 2)—1980	
193. 09194 61	82-12-16	83-12-15	IS : 564—1975	
194. 09197 64	82-12-01	83-11-30	IS : 4323—1980	
195. 09198 65	82-12-01	83-11-30	IS : 4159—1976	
196. 09200 42	82-12-16	83-12-15	IS : 2818 (भाग 2)—1971	
197. 09207 49	82-12-16	83-12-15	IS : 1660 (भाग 1) —1982 IS : 1660 (भाग 2 और 3)—1972 IS : 1660 (भाग 4)—1977	
198. 09210 44	82-12-16	83-12-15	IS : 9301—1982	
199. 09227 53	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1976	
200. 09229 55	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1979	
201. 09232 50	82-12-16	83-12-15	IS : 4431—1978	
202. 09240 50	83-01-01	83-12-31	IS : 694—1977	
203. 09241 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1554 (भाग 1) —1976	
204. 09263 57	83-01-01	83-12-31	IS : 8737 (भाग 2)—1978	
205. 09283 61	83-01-16	84-01-15	IS : 2312—1967	
206. 09288 66	83-01-16	84-01-15	IS : 3537—1966	
207. 09310 47	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1968	
208. 09322 51	82-02-01	83-01-31	IS : 2074—1962	
209. 09326 55	83-02-01	84-01-31	IS : 133—1975	
210. 09327 56	83-02-01	84-08-31	IS : 564—1975	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
211.	09334 55	83-02-01	84-01-31	IS : 4246—1978
212.	09409 57	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980
213.	09868 80	82-08-16	83-08-15	IS : 264—1976
214.	09869 81	82-08-16	83-08-15	IS : 265—1976
215.	09870 74	82-08-16	83-08-15	IS : 266—1977
216.	09871 75	82-08-16	83-08-15	IS : 695—1975
217.	10033 14	82-11-01	83-10-31	IS : 1475—1978
218.	10048 21	82-11-16	83-11-15	IS : 7270—1974
219.	10058 23	82-11-16	83-11-15	IS : 565—1975
220.	10060 17	82-11-16	83-11-15	IS : 7122—1973
221.	10083 24	82-12-01	83-11-30	IS : 3317—1965
222.	10084 25	82-12-01	83-11-30	IS : 5672—1970
223.	10085 26	82-12-01	83-11-30	IS : 2653—1980
224.	10086 27	82-12-01	83-11-30	IS : 2653—1980
225.	10112 12	82-12-01	83-11-30	IS : 4984—1978
226.	10113 13	82-12-01	83-11-30	IS : 171—1973
227.	10117 17	82-12-01	83-11-30	IS : 1011—1981
228.	10127 19	82-12-16	83-12-15	IS : 2861—1980
229.	10142 18	82-12-16	83-12-15	IS : 2730—1977
230.	10148 24	82-12-16	83-12-15	IS : 1783—1974
231.	10149 25	82-12-16	83-12-15	IS : 2834—1981
232.	10158 26	82-12-16	83-12-15	IS : 8074—1976
233.	10159 27	82-12-16	83-12-15	IS : 758—1982
234.	10168 28	82-12-16	83-12-15	IS : 1011—1981
235.	10174 26	82-12-16	83-12-15	IS : 1729—1979
236.	10178 30	82-12-16	83-12-15	IS : 226—1975
237.	10185 29	82-12-16	83-12-15	IS : 1596—1977
238.	10187 31	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976
239.	10191 27	83-01-01	83-12-31	IS : 5604—1970
240.	10192 28	83-01-01	83-12-31	IS : 1135—1973
241.	10194 30	83-01-01	83-12-31	IS : 1729—1979
242.	10196 32	83-01-01	83-12-31	IS : 2465—1969
243.	10209 20	83-01-01	83-12-31	IS : 4654—1974
244.	10212 15	83-01-01	83-12-31	IS : 5424—1969
245.	10224 19	83-01-01	83-12-31	IS : 633—1975
246.	10225 20	83-01-01	83-12-31	IS : 3903—1975
247.	10226 21	83-01-01	83-12-31	IS : 1011—1981
248.	10227 22	83-01-01	83-12-31	IS : 2567—1978
249.	10231 18	83-01-01	83-12-31	IS : 2400—1976
250.	10234 21	83-01-01	83-12-31	IS : 2400—1976
251.	10235 22	83-01-15	84-01-15	IS : 1786—1979
252.	10238 25	83-01-15	84-01-15	IS : 428—1969
253.	10239 26	82-12-16	83-12-15	IS : 4985—1981
254.	10241 20	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
255.	10249 28	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
256.	10250 21	83-01-16	84-01-15	IS : 7834 (भाग 2) —1975
257.	10251 22	83-01-16	84-01-15	IS : 1703—1977
258.	10252 23	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
259.	10253 24	83-01-16	84-01-15	IS : 1307—1982
260.	10273 28	83-01-16	84-01-15	IS : 4246—1978
261.	10274 29	83-01-16	84-01-15	IS : 694—1977

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
262.	10331 21	82-12-01	83-11-30	IS : 3790—1971
263.	10338 28	83-02-16	84-02-15	IS : 4984—1978

[सं०. सीएमडी/13 : 12]

**MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES  
INDIAN STANDARDS INSTITUTION**

New Delhi, the 1983-07-25

**S.O. 3368.**—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 263 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of January, 1983

**SCHEDULE**

Sl No.	CM/L No.	Valid From	To	Indian Standard Specification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	00071 15	83-01-01	83-12-31	IS : 261—1966
2.	00112 07	83-01-01	83-12-31	IS : 388—1972
3.	00253 19	83-01-01	83-12-31	IS : 1507—1977
4.	00339 24	82-12-01	83-11-30	IS : 325—1978
5.	00361 22	82-12-16	83-12-15	IS : 916—1975
6.	00369 30	83-01-01	83-12-31	IS : 916—1975
7.	00371 24	83-01-01	83-12-31	IS : 916—1975
8.	00547 30	82-12-16	83-12-15	IS : 10 (Part IV)—1976
9.	00591 34	82-12-01	83-11-30	IS : 1580—1969
10.	00752 33	83-01-16	84-01-15	IS : 2548—1980
11.	00839 39	82-12-01	83-11-30	IS : 1221—1971
12.	00850 34	82-12-01	83-11-30	IS : 2818 (Part II)—1971
13.	00884 44	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965
14.	00906 33	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965
15.	00910 29	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965
16.	00942 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965
17.	00977 48	82-12-01	83-11-30	IS : 220—1972
18.	01013 09	82-06-16	83-06-15	IS : 774—1971
19.	01131 14	83-01-01	83-12-31	IS : 694—1977
20.	01146 21	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975
21.	01218 20	81-09-16	83-09-15	IS : 1856—1977
22.	01219 21	83-01-01	83-12-31	IS : 814 (Part I & II)— 1974
23.	01319 24	83-01-16	84-01-15	IS : 2645—1975
24.	01353 26	83-01-01	83-12-31	IS : 1551—1976
25.	01613 27	83-02-01	84-01-31	IS : 2567—1978
26.	01707 32	82-11-16	83-11-15	IS : 398 (Part I)—1976
27.	01715 32	82-12-16	83-12-15	IS : 226—1975
29.	01716 33	82-12-16	83-12-15	IS : 1977—1975
29.	01889 53	83-01-16	84-01-15	IS : 10 (Part II)—1976
30.	02023 15	82-08-01	83-07-31	IS : 2548—1967
31.	02456 36	82-11-16	83-11-15	IS : 1165—1975
32.	02583 42	82-12-16	83-12-15	IS : 325—1978
33.	02690 44	82-11-16	83-11-15	IS : 325—1978
34.	02728 41	83-01-01	83-12-31	IS : 5086—1981
35.	02856 48	83-01-01	83-12-31	IS : 10 (Part II)—1976
36.	02857 49	82-12-16	83-12-31	IS : 1333—1978

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37.	32866	50	83-01-16	84-01-15 IS : 1322—1970	97.	05666	56	82-12-01	83-11-30 IS : 1011—1981
38.	02906	41	83-01-01	84-06-30 IS : 1601—1960	98.	05716	49	82-12-01	83-11-30 IS : 633—1975
39.	02950	45	83-01-01	83-12-31 IS : 1222—1973	99.	05730	47	83-01-01	83-11-31 IS : 1239 (Part I)—1976
40.	02970	49	83-01-16	84-01-15 IS : 1223 (Part I)—1970	100.	05741	50	82-12-16	83-12-15 IS : 5430—1981
41.	03106	21	83-01-01	83-12-31 IS : 1322—1970	101.	05760	53	82-01-01	83-06-30 IS : 6914—1978
42.	03126	25	82-12-01	83-11-30 IS : 2082—1978	102.	05761	54	82-07-01	83-06-30 IS : 6915—1978
43.	03207	25	82-12-16	83-12-15 IS : 694—1977	103.	05763	56	83-01-16	84-01-15 IS : 10 (Part II)—1976
44.	03260	30	83-01-01	83-12-31 IS : 814 (Part I)—1974	104.	05794	63	83-01-01	83-12-31 IS : 4654—1974
45.	03279	41	83-01-01	83-12-31 IS : 3196—1974	105.	05810	46	83-01-16	84-01-15 IS : 2465—1969
46.	03280	34	83-01-16	84-01-15 IS : 1601—1960	106.	05815	51	83-01-16	84-01-15 IS : 3865—1978
47.	03283	37	83-01-01	84-06-15 IS : 434 (Part I & II)—1964	107.	05931	54	83-01-01	83-12-31 IS : 4927—1968
48.	03284	38	83-01-01	84-06-15 IS : 694—1977	108.	06097	49	82-12-01	83-11-30 IS : 171—1973
49.	03285	39	83-01-01	84-06-15 IS : 1554 (Part I)—1976	109.	06122	33	83-01-01	83-12-31 IS : 3450—1976
50.	03286	40	83-01-01	84-06-15 IS : 1596—1977	110.	06401	37	82-09-16	83-09-15 IS : 5430—1981
51.	03477	45	82-01-01	83-12-31 IS : 4382—1967	111.	06428	48	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
52.	03541	36	83-01-01	83-12-31 IS : 4985—1968	112.	06434	46	82-07-01	83-06-30 IS : 1239 (Part I)—1979
53.	03561	40	82-12-16	83-12-15 IS : 1786—1966	113.	06529	52	82-12-01	83-11-30 IS : 3652—1982
54.	03590	45	82-11-16	83-11-15 IS : 5423—1978	114.	06535	50	82-11-16	83-11-15 IS : 6914—1978
55.	03596	51	82-12-01	83-11-30 IS : 1726 (Part II)—1974	115.	06536	51	82-11-16	83-11-15 IS : 6915—1978
56.	03609	39	82-12-01	83-11-30 IS : 5455—1969	116.	06551	50	82-12-01	83-11-30 IS : 4964—1980
57.	03635	41	82-12-16	83-12-15 IS : 325—1978	117.	06554	53	82-11-16	83-11-15 IS : 1547—1968
58.	03667	49	83-01-16	84-01-15 IS : 2148—1968	118.	06563	54	82-12-01	83-11-30 IS : 226—1975
59.	03848	52	82-12-16	83-12-15 IS : 1554 (Part I)—1976	119.	06570	53	82-12-16	83-12-15 IS : 6915—1978
60.	04029	29	82-11-16	83-11-15 IS : 4663—1968	120.	06571	54	82-12-16	83-12-15 IS : 694—1977
61.	04080	32	82-12-01	83-11-30 IS : 335—1972	121.	06576	59	83-01-01	83-12-31 IS : 1222—1973
62.	04108	27	83-01-01	83-12-31 IS : 4246—1978	122.	06582	57	82-12-16	83-12-15 IS : 1011—1981
63.	04150	29	83-01-16	84-01-15 IS : 398 (Part I & II)—1976	123.	06587	62	83-01-01	83-12-31 IS : 1161—1979
64.	04189	44	83-02-01	84-01-31 IS : 5346—1975	124.	06591	58	83-01-01	83-12-31 IS : 1161—1979
65.	04369	46	82-12-16	83-12-15 IS : 781—1977	125.	06616	50	83-01-01	83-12-31 IS : 4148—1967
66.	04375	44	82-11-16	83-11-15 IS : 2567—1978	126.	06620	46	83-01-01	83-12-31 IS : 4989—1974
67.	04590	49	82-09-01	83-08-31 IS : 2548—1967	127.	06640	50	83-01-16	84-01-15 IS : 2325—1963
68.	04735	48	83-01-01	83-12-31 IS : 3062—1974	128.	06642	52	83-01-16	84-01-15 IS : 1223 (Part II)—1972
69.	04736	49	83-01-01	83-12-31 IS : 1970 (Part I)—1982	129.	06643	53	83-01-01	83-12-31 IS : 5410—1969
70.	04737	50	83-01-01	83-12-31 IS : 1971—1982	130.	06676	62	83-01-01	83-12-31 IS : 780—1980
71.	04738	51	83-01-01	83-12-31 IS : 3897—1978	131.	06773	62	83-02-01	84-01-31 IS : 1307—1973
72.	04739	52	83-01-01	83-12-31 IS : 3652—1982	132.	07303	40	82-11-16	83-11-15 IS : 7577—1975
73.	04742	47	83-01-01	83-12-31 IS : 3634—1977	133.	07312	41	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
74.	04743	48	83-01-01	83-12-31 IS : 2928—1973	134.	07317	46	82-11-16	83-11-16 IS : 4964—1980
75.	04744	49	83-01-01	83-12-31 IS : 2870—1977	135.	07322	43	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
76.	04781	54	82-11-01	83-10-31 IS : 1186—1971	136.	07326	47	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
77.	04809	49	82-12-01	83-11-30 IS : 2865—1978	137.	07336	49	82-11-16	83-11-15 IS : 1601—1960
78.	04810	42	82-12-01	83-11-30 IS : 204 (Part II)—1978	138.	07341	46	82-11-16	83-11-15 IS : 1239 (Part I)—1979
79.	04852	52	82-12-01	84-03-15 IS : 398 (Part II)—1976	139.	07348	53	82-12-01	83-11-30 IS : 565—1975
80.	04863	55	82-12-16	83-12-15 IS : 1322—1970	140.	07349	54	82-12-01	83-11-30 IS : 6438—1980
81.	04871	55	82-12-01	83-11-30 IS : 7406 (Part I)—1974	141.	07362	51	82-11-16	83-11-15 IS : 1660 (Part I)—1982
82.	04878	62	82-12-16	83-12-15 IS : 2865—1978					IS : 1660 (Part II & III)—1972
83.	04880	56	82-12-16	83-12-15 IS : 419—1967	142.	07372	53	82-12-01	83-11-30 IS : 1320—1981
84.	04888	64	82-12-16	83-12-15 IS : 633—1975	143.	07385	58	82-12-01	84-02-15 IS : 398 (Part I)—1976
85.	04955	58	83-01-16	84-01-15 IS : 325—1978 & IS : 1520—1972	144.	07407	47	83-01-01	84-04-30 IS : 934—1976
86.	04978	65	83-12-01	84-01-31 IS : 1554 (Part I)—1976	145.	07419	51	82-07-01	83-06-30 IS : 1786—1979
87.	05003	23	83-01-01	83-12-31 IS : 398 (Part II)—1976	146.	07425	49	83-01-01	83-12-31 IS : 10 (Part IV)—1976
88.	05130	29	82-07-01	83-06-30 IS : 226—1975	147.	07427	51	83-01-01	83-12-31 IS : 1970 (Part I)—1974
89.	05131	30	82-07-01	83-06-30 IS : 1977—1975	148.	07439	55	83-01-01	83-12-31 IS : 261—1966
90.	05146	37	83-01-01	83-12-31 IS : 3906 (Part I)—1982	149.	07455	55	83-01-16	84-01-15 IS : 3906 (Part I)—1974
91.	05378	51	83-01-16	84-01-15 IS : 1891 (Part I & II)—1978	150.	07456	56	83-01-16	84-01-15 IS : 5662—1970
92.	05554	49	83-02-01	84-01-31 IS : 633—1975	151.	07466	58	82-11-16	83-11-16 IS : 4964—1980
93.	05590	53	83-01-01	83-12-31 IS : 4174—1977	152.	07469	51	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
94.	05633	47	82-11-16	83-11-15 IS : 1239 (Part I)—1979	153.	07470	54	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
95.	05638	52	82-12-01	83-11-30 IS : 10 (Part IV)—1976	154.	07486	62	83-02-01	84-01-31 IS : 694—1977
96.	05661	51	82-12-01	83-11-30 IS : 4323—1980	155.	07520	47	82-11-16	83-11-15 IS : 4964—1980
					156.	08114	41	82-11-16	83-11-15 IS : 6595—1980
					157.	08116	43	82-11-16	83-11-15 IS : 2339—1963

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
158.	08142 45	82-11-16	83-11-15	IS : 10 (Part IV)—1976
159.	08153 48	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979
160.	08190 53	82-12-16	83-12-15	IS : 3906 (Part I)—1982
161.	08217 47	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (Part I)—1976
162.	08235 49	83-01-01	83-12-31	IS : 4654—1974
163.	08252 50	82-12-01	83-11-30	IS : 2874—1964
164.	08256 54	82-12-16	83-12-15	IS : 7406 (Part I)—1974
165.	08263 53	83-01-01	83-12-31	IS : 1061—1975
166.	08286 60	83-01-16	84-01-15	IS : 1795—1974
167.	08289 63	83-01-16	84-01-15	IS : 848—1974
168.	08292 58	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964
169.	08296 62	82-12-16	83-12-15	IS : 1943—1964
170.	08301 42	83-01-16	84-01-15	IS : 3975—1979
171.	08305 46	83-01-16	84-01-15	IS : 694—1977
172.	08314 47	83-01-16	84-01-15	IS : 1165—1975
173.	08369 62	82-04-16	83-04-15	IS : 5277—1978
174.	08384 61	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964
175.	08476 64	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964
176.	08529 60	82-04-16	83-06-30	IS : 1161—1979
177.	09028 48	82-10-16	83-10-15	IS : 4142—1967
178.	09099 63	82-11-16	83-11-15	IS : 8960—1978
179.	09133 48	82-11-16	83-11-15	IS : 4964—1980
180.	09137 52	83-01-01	83-12-31	IS : 7593 (Part I)—1975
181.	09139 54	82-12-01	83-11-30	IS : 612—1971
182.	09142 49	82-12-01	83-11-30	IS : 8960—1978
183.	09154 53	82-12-01	83-11-30	IS : 371—1979
184.	09156 55	82-12-01	83-11-30	IS : 6595—1980
185.	09157 56	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (Part IV)—1976
186.	09158 57	82-12-01	83-11-30	IS : 7370—1974
187.	09162 53	82-12-01	83-11-30	IS : 9128—1979
188.	09178 61	82-12-16	83-12-15	IS : 2509—1973
189.	09184 59	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1979
190.	09185 60	82-12-16	83-12-15	IS : 694—1977
191.	09186 61	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (Part I)—1976
192.	09189 64	82-12-16	83-12-15	IS : 2713 (Part II)—1980
193.	09194 61	82-12-16	83-12-15	IS : 564—1975
194.	09197 64	82-12-01	83-11-30	IS : 4323—1980
195.	09198 65	82-12-01	83-11-30	IS : 4159—1976
196.	09200 42	82-12-16	83-12-15	IS : 2816 (Part II)—1971
197.	09207 49	82-12-16	83-12-15	IS : 1660 (Part I)—1982
				IS : 1660 (Part II & III)—1972
				IS : 1660 (Part IV)—1977
198.	09217 44	82-12-16	83-12-15	IS : 9301—1982
199.	09227 53	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1976
200.	09229 55	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1979
201.	09232 50	82-12-16	83-12-15	IS : 4431—1978
202.	09240 50	83-01-01	83-12-31	IS : 694—1977
203.	09241 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1554 (Part I)—1976
204.	09263 57	83-01-01	83-12-31	IS : 8737 (Part II)—1978
205.	09283 61	83-01-16	84-01-15	IS : 2312—1967
206.	09288 66	83-01-16	84-01-15	IS : 3537—1966
207.	09310 47	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1968
208.	09322 51	82-02-01	83-01-31	IS : 2074—1962
209.	09326 55	83-02-01	84-01-31	IS : 133—1975
210.	09327 56	83-02-01	84-08-31	IS : 564—1975
211.	09334 55	83-02-01	84-01-31	IS : 4246—1978
212.	09409 57	82-11-16	83-11-15	IS : 4954—1980
213.	09868 80	82-08-16	83-08-15	IS : 264—1976
214.	09869 81	82-08-16	83-08-15	IS : 265—1976
215.	09870 74	82-08-16	83-08-15	IS : 266—1977
216.	09871 75	82-08-16	83-08-15	IS : 695—1975
217.	10033 14	82-11-01	83-10-31	IS : 1475—1978
218.	10048 21	82-11-16	83-11-15	IS : 7270—1974

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
219.	10058 23	82-11-16	83-11-15	IS : 565—1975
220.	10060 17	82-11-16	83-11-15	IS : 7122—1973
221.	10083 24	82-12-01	83-11-30	IS : 3317—1965
222.	10084 25	82-12-01	83-11-30	IS : 5672—1970
223.	10085 26	82-12-01	83-11-30	IS : 2653—1980
224.	10086 27	82-12-01	83-11-30	IS : 2653—1980
225.	10112 12	82-12-01	83-11-30	IS : 4984—1978
226.	10113 13	82-12-01	83-11-30	IS : 171—1973
227.	10117 17	82-12-01	83-11-30	IS : 1011—1981
228.	10127 19	82-12-16	83-12-15	IS : 2861—1980
229.	10142 18	82-12-16	83-12-15	IS : 2730—1977
230.	10148 24	82-12-16	83-12-15	IS : 1783—1974
231.	10149 25	82-12-16	83-12-15	IS : 2834—1981
232.	10158 26	82-12-16	83-12-15	IS : 8074—1976
233.	10159 27	82-12-16	83-12-15	IS : 758—1982
234.	10168 28	82-12-16	83-12-15	IS : 1011—1981
235.	10174 26	82-12-16	83-12-15	IS : 1729—1979
236.	10178 30	82-12-16	83-12-15	IS : 226—1975
237.	10185 29	82-12-16	83-12-15	IS : 1596—1977
238.	10187 31	82-12-16	83-12-15	IS : 1554 (Part I)—1976
239.	10191 27	83-01-01	83-12-31	IS : 5604—1970
240.	10192 28	83-01-01	83-12-31	IS : 1135—1973
241.	10194 30	83-01-01	83-12-31	IS : 1729—1979
242.	10196 32	83-01-01	83-12-31	IS : 2465—1969
243.	10209 20	83-01-01	83-12-31	IS : 4654—1974
244.	10212 15	83-01-01	83-12-31	IS : 5424—1969
245.	10224 19	83-01-01	83-12-31	IS : 633—1975
246.	10225 20	83-01-01	83-12-31	IS : 3903—1975
247.	10226 21	83-01-01	83-12-31	IS : 1011—1981
248.	10227 22	83-01-01	83-12-31	IS : 2567—1978
249.	10231 18	83-10-01	83-12-31	IS : 2400—1976
250.	10234 21	83-01-01	83-12-31	IS : 2400—1976
251.	10235 22	83-01-16	84-01-15	IS : 1786—1979
252.	10238 25	83-01-16	84-01-15	IS : 428—1969
253.	10239 26	82-12-16	83-12-15	IS : 4985—1981
254.	10241 20	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
255.	10249 28	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
256.	10250 21	83-01-16	84-01-15	IS : 7834 (Part IV)—1975
257.	10251 22	83-01-16	84-01-15	IS : 1703—1977
258.	10252 23	83-01-16	84-01-15	IS : 4985—1981
259.	10253 24	83-01-16	84-01-15	IS : 1307—1982
260.	10273 28	83-01-16	84-01-15	IS : 4245—1978
261.	10274 29	83-01-16	84-01-15	IS : 694—1977
262.	10331 21	82-12-01	83-11-30	IS : 3790—1971
263.	10338 28	83-02-16	84-02-15	IS : 4984—1978

[No. CMD/13:12]

का० आ० 3369— समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विभाग) विनियम, 1955 के विनियम 8 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन 315 लाइसेंसों के व्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, उनका दिनांक, 1982 में नवीकरण किया गया है।

## अनुसूची

क्रम	सांख्यिक	वैद्य	भारतीय मानक
संख्या	संख्या	से	तक
(1)	(2)	(3)	(4)

1. 00082 18 82-11-01 83-10-31 IS : 10 (भाग 2)—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
2.	00188 27	82-11-16	83-11-15	IS : 1184—1977	43.	02395 40	82-12-01	83-11-30	IS : 774—1971
3.	00351 20	82-09-01	83-08-31	IS : 10 (भाग 2) —1976	44.	02713 34	82-12-01	83-11-30	IS : 2580—1965
4.	00554 29	82-11-01	83-10-31	IS : 561—1978	45.	02738 43	82-12-01	83-11-30	IS : 1554 (भाग 1) —1976
5.	00598 41	82-12-01	83-11-30	IS : 694—1977	46.	02782 47	82-10-16	83-10-15	IS : 2925—1975
6.	00649 35	82-11-01	83-10-31	IS : 325—1978	47.	92851 43	82-12-16	83-12-15	IS : 2566—1965
7.	00662 32	82-12-01	83-11-30	IS : 692—1973	48.	02862 46	82-12-01	83-11-30	IS : 2580—1965
8.	00831 31	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	49.	02942 45	82-12-16	83-12-15	IS : 415—1978
9.	00832 32	82-11-16	83-11-15	IS : 1977—1975	50.	03042 22	82-10-16	83-10-15	IS : 10 (भाग 2) —1976
10.	00844 36	82-12-01	83-11-30	IS : 2818 (भाग 2) —1978	51.	03065 29	82-11-16	83-11-15	IS : 458—1971
11.	00845 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	52.	03104 19	82-12-01	83-11-30	IS : 434 (भाग 1) —1964
12.	00851 35	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	53.	03156 31	82-11-16	83-11-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976
13.	00853 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	54.	03244 30	82-12-16	83-12-15	IS : 10 (भाग 2) —1976
14.	00855 39	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	55.	03569 48	82-10-16	83-10-15	IS : 398 (भाग 1 और भाग 2)—1976
15.	00860 36	83-01-01	83-12-31	IS : 2818 (भाग 2) —1971	56.	03588 51	82-11-16	83-11-15	IS : 6438—1980
16.	00872 40	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	57.	03602 32	82-11-01	83-10-31	IS : 1601—1960
17.	00876 44	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	58.	03605 35	82-12-01	83-11-30	IS : 1879—1975
18.	00878 46	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	59.	03811 39	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977
19.	00882 42	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	60.	03821 41	82-11-01	83-10-31	IS : 3975—1979
20.	00927 38	82-12-01	83-11-30	IS : 2818 (भाग 2) —1971	61.	03999 66	82-11-01	83-10-31	IS : 1520—1980
21.	00928 39	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	62.	04003 19	82-11-01	83-10-31	IS : 6595—1980
22.	00934 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	63.	04015 23	82-11-01	83-10-31	IS : 6914—1978
23.	00950 37	82-12-01	83-11-30	IS : 2566—1965	64.	04016 24	82-11-01	83-10-31	IS : 6915—1978
24.	01105 12	82-12-01	83-11-30	IS : 1554 (भाग 1) —1976	65.	04019 27	82-11-01	83-10-31	IS : 398—1976
25.	01162 21	83-01-01	83-12-31	IS : 398 (भाग 2) —1976	66.	04057 33	82-11-16	83-11-15	IS : 633—1975
26.	01186 29	83-01-01	83-12-31	IS : 398 (भाग 2) —1976	67.	04061 29	82-12-01	83-11-30	IS : 398 (भाग 2) —1976
27.	01209 19	82-12-01	83-11-30	IS : 398 (भाग 2) —1976	68.	04062 30	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (भाग 4) —1976
28.	01432 24	82-11-16	83-11-15	IS : 1596—1977	69.	04421 33	82-11-01	83-10-31	IS : 633—1975
29.	01545 32	82-11-16	83-11-15	IS : 325—1978	70.	04478 50	82-11-16	84-05-15	IS : 2567—1978
30.	01558 37	82-12-01	83-11-30	IS : 398 (भाग 1) —1976	71.	04496 52	82-10-16	83-10-15	IS : 778—1971
31.	01642 32	82-11-01	83-10-31	IS : 2567—1978	72.	04550 41	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975
32.	01649 39	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	73.	04610 36	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (भाग 4) —1976
33.	01687 45	82-09-01	83-08-31	IS : 398 (भाग 1 और भाग 2)—1976	74.	04643 45	82-12-01	83-11-30	IS : 3976—1975
34.	01698 48	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	75.	04729 50	82-10-16	83-10-15	IS : 1165—1975
35.	01734 35	82-11-01	83-10-31	IS : 417—1974	76.	04732 45	82-10-16	83-10-15	IS : 1711—1970
36.	01814 34	82-10-16	83-10-15	IS : 1660—1967	77.	04746 51	80-04-01	83-03-31	IS : 778—1971
37.	01869 49	82-12-16	83-12-15	IS : 3564—1975	78.	04747 52	82-11-01	83-10-31	IS : 10 (भाग 3) —1974
38.	01936 43	82-01-01	82-12-31	IS : 10 (भाग 2) —1976	79.	04749 54	82-11-01	83-10-31	IS : 2052—1979
39.	02104 15	82-10-16	83-10-15	IS : 10 (भाग 4) —1976	80.	04750 47	82-11-01	83-10-31	IS : 1374—1979
40.	02155 26	82-10-16	83-10-15	IS : 10 (भाग 3) —1974	81.	04757 54	82-11-01	83-10-31	IS : 10—1970
41.	02294 36	82-10-01	83-09-30	IS : 2480—1982	82.	04772 53	82-11-01	83-10-31	IS : 829—1978
42.	02313 22	82-11-01	83-10-31	IS : 3686—1966	83.	04787 60	82-11-01	83-10-31	IS : 916—1975
					84.	04812 44	82-08-16	83-08-15	IS : 1692—1974
					85.	04815 47	82-12-01	83-11-30	IS : 335—1972
					86.	04827 51	81-04-01	83-03-31	IS : 1703—1977
					87.	04828 52	82-11-16	83-11-15	IS : 1848—1981



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	*
88.	04834 50	82-09-01	83-08-31	IS : 269—1976	134.	06533 48	82-11-16	83-11-15	IS : 6914—1978	
89.	04855 55	82-12-01	83-11-30	IS : 6003—1970	135.	06534 49	82-11-16	83-11-15	IS : 6915—1978	
90.	04860 52	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (भाग 2) —1980	136.	06539 54	82-12-01	83-11-30	IS : 5852—1977	
91.	04861 53	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (भाग 2) —1980	137.	06555 54	82-12-01	83-11-30	IS : 8249—1976	
92.	04914 49	83-01-01	83-12-31	IS : 7407 (भाग 2) —1980	138.	06559 58	82-12-01	83-11-30	IS : 4323—1967	
93.	04916 51	83-01-01	83-12-31	IS : 624—1975	139.	06619 53	83-01-01	83-12-31	IS : 5281—1979	
94.	04995 66	82-08-16	83-08-15	IS : 375—1978	140.	06665 59	82-08-01	83-07-31	IS : 303—1975	
95.	05060 32	82-03-16	83-03-15	IS : 7407 (भाग 2) —1980	141.	07179 54	82-09-01	83-08-31	IS : 4964—1980	
96.	05160 35	82-11-01	83-10-31	IS : 1786—1979	142.	07201 35	82-09-16	83-09-15	IS : 1786—1979	
97.	05161 36	82-11-01	83-10-31	IS : 226—1975	143.	07206 41	82-09-16	83-09-15	IS : 564—1974	
98.	05338 43	82-12-16	83-12-15	IS : 6914—1973	144.	07209 43	82-09-16	83-09-15	IS : 410—1977	
99.	05339 44	82-12-16	83-12-15	IS : 6915—1978	145.	07212 38	83-01-01	83-12-31	IS : 1221—1971	
100.	05416 40	82-11-01	83-10-31	IS : 6248—1971	146.	07219 45	82-09-16	83-09-15	IS : 398—(भाग 2) —1976	
101.	05500 35	82-09-16	83-09-15	IS : 694—1971	147.	07221 39	82-10-01	83-09-30	IS : 2653—1980	
102.	05561 48	82-11-01	83-10-31	IS : 561—1978	148.	07256 50	82-10-01	83-09-30	IS : 1786—1979	
103.	05564 51	82-10-16	83-10-15	IS : 564—1975	149.	07265 51	82-10-16	82-10-15	IS : 834—1975	
104.	05570 49	82-10-16	83-10-15	IS : 325—1978	150.	07269 55	82-10-16	83-10-15	IS : 561—1972	
105.	05593 56	82-12-01	83-11-30	IS : 2906—1980	151.	07272 50	81-10-16	82-10-15	IS : 934—1976	
106.	05615 45	82-11-16	83-11-15	IS : 398 (भाग 1 और 2)—1976	152.	07273 51	82-10-16	83-10-15	IS : 6595—1980	
107.	05619 49	82-11-16	83-11-15	IS : 1475—1978	153.	07275 53	82-10-16	83-10-15	IS : 1786—1966	
108.	05626 48	82-11-16	83-11-15	IS : 10 (भाग 2)— —1976	154.	07277 55	82-11-01	83-10-31	IS : 829—1965	
109.	05631 45	82-11-16	83-11-15	IS : 1308—1974	155.	07284 54	82-11-01	83-10-31	IS : 1766—1974	
110.	05634 48	82-11-01	83-10-31	IS : 325—1978	156.	07285 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4467—1980	
111.	05672 54	82-12-01	83-11-30	IS : 778—1971	157.	07286 56	82-11-01	83-10-31	IS : 4588—1977	
112.	05673 55	82-12-01	83-11-30	IS : 1222—1973	158.	07290 52	82-01-11	83-10-31	IS : 4323—1980	
113.	05690 56	82-12-16	83-12-15	IS : 458—1971	159.	07292 54	82-11-01	83-10-31	IS : 398 (भाग 2) —1976	
114.	05771 56	82-12-16	83-12-15	IS : 781—1977	160.	07296 58	82-11-01	83-10-31	IS : 4985—1981	
115.	05866 62	82-08-16	83-08-15	IS : 10 (भाग 4) —1976	161.	07309 46	82-11-16	83-11-15	IS : 2344—1973	
116.	05980 63	82-03-16	83-03-15	IS : 2567—1973	162.	07319 48	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	
117.	06074 42	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971	163.	07330 43	82-07-16	83-07-15	IS : 303—1975	
118.	06095 47	82-08-01	83-07-31	IS : 8144—1976	164.	07350 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1251—1973	
119.	06204 34	82-12-01	83-11-30	IS : 1223 (भाग 2) —1972	165.	07352 49	82-12-01	83-11-30	IS : 1786—1979	
120.	06217 39	82-07-01	83-06-30	IS : 2567—1978	166.	07366 55	82-11-29	83-11-30	IS : 1601—1962	
121.	06402 38	82-09-16	83-09-15	IS : 4964—1980	167.	07387 60	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971	
122.	06421 41	82-10-01	83-09-30	IS : 1660 (भाग 1 से 4)	168.	07390 55	82-12-01	83-11-30	IS : 1879—1975	
123.	06433 45	82-10-01	83-09-30	IS : 6047—1970	169.	07398 63	82-12-01	83-11-30	IS : 7407 (भाग 2) —1980	
124.	06443 47	82-10-16	83-10-15	IS : 5456—1969	170.	07405 45	82-12-01	83-11-30	IS : 2834—1964	
125.	06459 55	82-10-16	83-10-15	IS : 4964—1980	171.	07414 46	82-12-16	83-12-15	IS : 4174—1977	
126.	06466 54	82-11-01	83-10-31	IS : 6595—1980	172.	07440 48	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	
127.	06475 55	82-10-16	83-10-15	IS : 8057—1976	173.	07442 50	83-01-01	83-12-31	IS : 1601—1960	
128.	06504 43	82-11-01	83-10-31	IS : 4250—1980	174.	07443 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1601—1960	
129.	06513 44	82-11-16	83-11-15	IS : 633 —1975	175.	07531 50	82-02-16	83-02-15	IS : 1891 (भाग 1) —1978	
130.	06514 45	82-11-01	83-10-31	IS : 6914—1978	176.	07813 57	82-12-01	83-11-30	IS : 7098 (भाग 2) —1973	
131.	06515 46	82-11-01	83-10-31	IS : 6915—1978	177.	07843 63	82-07-16	83-07-15	IS : 781 —1977	
132.	06527 50	82-11-16	83-11-15	IS : 3564—1975	178.	07928 67	82-09-01	83-08-31	IS : 10 (भाग 4) —1976	
133.	06528 51	82-11-16	83-11-15	IS : 5346—1975	179.	07932 63	82-09-01	83-08-31	IS : 564—1975	
					180.	07988 79	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	
					181.	08030 38	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
182.	08042 42	82-10-16	83-10-15	IS : 1786—1979	232.	09025 45	82-10-16	83-10-15	IS : 561—1978
183.	08063 47	82-11-01	83-10-31	IS : 1786—1979	233.	09026 46	82-10-16	83-10-15	IS : 2052—1975
184.	08064 48	82-11-01	84-03-31	IS : 398 (भाग 2) —1976	234.	09031 43	82-10-16	83-10-15	IS : 7121—1973
185.	08066 50	82-11-01	83-10-31	IS : 774—1971	235.	09052 48	82-10-16	83-10-15	IS : 2653—1980
186.	08076 52	82-10-16	83-10-15	IS : 1547—1968	236.	09066 54	82-11-01	83-10-31	IS : 3901—1975
187.	08078 54	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	237.	09081 53	82-11-01	83-10-31	IS : 398 (भाग 1) —1976
188.	08079 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	238.	09085 57	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977
189.	08086 54	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	239.	09088 60	82-11-16	83-11-15	IS : 4654—1974
190.	08087 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	240.	09090 54	82-11-16	83-11-15	IS : 1977—1975
191.	08100 35	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	241.	09092 56	82-11-16	83-11-15	IS : 8828—1978
192.	08105 40	82-11-16	83-11-15	IS : 7538—1975	242.	09093 57	82-11-01	83-10-31	IS : 398 (भाग 2) —1976
193.	08107 42	82-11-16	83-11-15	IS : 633—1975	243.	09109 48	82-11-16	83-11-15	IS : 564—1975
194.	08126 45	82-11-16	83-11-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976	244.	09115 46	82-11-16	83-11-15	IS : 8249—1976
195.	08132 43	82-09-01	83-08-31	IS : 2993—1975	245.	09116 47	82-11-16	83-11-15	IS : 2567—1978
196.	08141 44	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977	246.	09117 48	82-11-16	83-11-15	IS : 561—1978
197.	08147 50	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	247.	09121 44	82-11-16	83-11-15	IS : 8249—1976
198.	08148 51	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	248.	09122 45	82-11-16	83-11-15	IS : 778—1971
199.	08152 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1135—1973	249.	09146 53	82-12-01	83-11-30	IS : 158—1968
200.	08168 55	82-12-01	83-11-30	IS : 226—1975	250.	09147 54	82-12-01	83-11-30	IS : 341—1973
201.	08173 52	82-12-16	83-12-15	IS : 1977—1975	251.	09148 55	82-12-01	83-11-30	IS : 694—1977
202.	08175 54	82-12-16	83-12-15	IS : 4654—1974	252.	09149 56	82-12-01	83-11-30	IS : 562—1978
203.	08177 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	253.	09153 52	82-12-01	83-11-30	IS : 565—1975
204.	08179 58	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	254.	09165 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1786—1979
205.	08183 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	255.	09170 53	82-12-01	83-11-30	IS : 5455—1969
206.	08187 58	82-12-16	83-12-15	IS : 158—1968	256.	09171 54	82-12-01	83-11-30	IS : 9224 (भाग 1 और 2)—1979
207.	08191 54	82-12-16	83-12-15	IS : 1161—1968	257.	09176 59	82-12-16	83-12-15	IS : 909—1975
208.	08208 46	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	258.	09181 56	82-12-16	83-12-15	IS : 2568—1978
209.	08209 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	259.	09245 55	83-01-01	83-12-31	IS : 2573—1975
210.	08218 48	82-12-16	83-12-15	IS : 226—1975	260.	09540 59	82-04-01	83-03-31	IS : 694—1977
211.	08223 50	83-01-01	83-12-31	IS : 4323—1967	261.	09824 68	82-07-16	83-07-15	IS : 2580—1965
212.	08243 49	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	262.	09979 86	82-10-01	83-09-30	IS : 261—1966
213.	08250 48	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	263.	09992 83	82-10-16	83-10-15	IS : 246—1972
214.	08259 57	83-01-01	83-12-31	IS : 398 (भाग 2) —1976	264.	09995 86	82-10-16	83-10-15	IS : 4964—1980
215.	08271 53	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	265.	09997 88	82-10-16	83-10-15	IS : 633—1975
216.	08293 59	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	266.	09998 89	82-10-16	83-10-15	IS : 4323—1980
217.	08295 61	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	267.	09999 90	82-10-16	83-10-15	IS : 8259—1976
218.	08354 55	82-02-01	83-01-31	IS : 10 (भाग 2)— —1976	268.	10009 14	82-10-16	83-10-15	IS : 6595—1980
219.	08385 62	82-12-01	83-11-30	IS : 2874—1964	269.	10010 07	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975
220.	08388 65	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	270.	10017 14	82-10-16	83-10-15	IS : 398 (भाग 2) —1976
221.	08442 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	271.	10019 16	82-11-01	83-10-31	IS : 3906 (भाग 1) —1974
222.	08523 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	272.	10027 16	82-11-01	83-10-31	IS : 5279—1969
223.	08708 61	82-06-16	83-06-15	IS : 1554 (भाग 1) —1976	273.	10034 15	82-11-01	83-10-31	IS : 2465—1969
224.	08855 71	82-08-16	83-08-15	IS : 1786—1979	274.	10036 17	82-11-01	83-10-31	IS : 2865—1964
225.	08886 78	82-08-16	83-08-15	IS : 1729—1969	275.	10039 20	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980
226.	08984 79	82-10-01	83-09-30	IS : 171—1973	276.	10040 13	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980
227.	08989 84	82-10-01	83-09-30	IS : 3312—1974	277.	10045 18	82-11-01	83-10-31	IS : 103 (भाग 1) —1977
228.	08999 86	82-10-01	83-09-30	IS : 3575—1977	278.	10046 19	82-11-16	83-11-15	IS : 2548—1980
229.	09007 43	82-10-01	83-09-30	IS : 3196—1976	279.	10054 19	82-11-16	83-11-15	IS : 2465—1969
230.	09014 42	82-11-01	83-10-31	IS : 8074—1976	280.	10063 20	82-11-16	83-11-15	IS : 5410—1969
231.	09023 43	82-09-16	83-09-15	IS : 1239 (भाग 1) —1979					

## SCHEDULE

Sl. No.	CM/L No.	Valid From	Indian Standard Specification No.
(1)	(2)	(3)	(4)
281.	10067 24	82-11-16	83-11-15 IS : 4174—1977
282.	10068 25	82-11-16	83-11-15 IS : 4323—1980
283.	10080 81	82-11-16	83-11-15 IS : 3564—1966
284.	10082 23	82-12-01	83-11-30 IS : 4654—1974
285.	10088 29	82-12-01	83-11-30 IS : 10 (Pt II)—1976
286.	10090 23	82-12-01	83-11-30 IS : 1780—1980
287.	10091 24	82-12-01	83-11-30 IS : 398 (Pt II)—1976
288.	10098 31	82-12-01	83-11-30 IS : 778—1971
289.	10099 32	82-12-01	83-11-30 IS : 1921—1975
290.	10100 08	82-12-01	83-11-30 IS : 7406 (Pt I)—1974
291.	10101 09	82-12-01	83-11-30 IS : 7406 (Pt II) 1980
292.	10106 14	82-12-01	83-11-30 IS : 2834—1964
293.	10107 15	82-12-01	83-11-30 IS : 5950—1971
294.	10108 16	82-12-01	83-11-30 IS : 2932—1974
295.	10114 14	82-12-01	83-11-30 IS : 694—1977
296.	10115 15	82-12-01	84-06-30 IS : 9295—1979
297.	10116 16	82-12-01	83-1-30 IS : 9182 (Pt-III)—1979
298.	10128 15	82-12-16	83-12-15 IS : 398 (Pt-I)—1976
299.	10124 16	82-12-16	83-12-15 IS : 3975—1979
300.	10126 18	82-12-16	83-12-15 IS : 4323—1980
301.	10130 14	82-12-16	83-12-15 IS : 1307—1973
302.	10131 15	82-12-16	83-06-15 IS : 4323—1967
303.	10134 18	82-12-16	83-12-15 IS : 10 (Pt-III)—1974
304.	10136 20	82-12-16	83-12-15 IS : 1786—1979
305.	10138 22	82-12-16	83-12-15 IS : 2580—1965
306.	10139 23	82-12-16	83-12-15 IS : 2580—1965
307.	10144 20	82-12-16	83-12-15 IS : 8960—1978
308.	10150 18	82-12-01	83-11-30 IS : 458—1971
309.	10156 24	82-12-01	83-11-30 IS : 458—1971
310.	10163 23	82-12-01	83-11-30 IS : 4985—1968
311.	10167 27	82-12-16	83-12-15 IS : 1221—1971
312.	10169 29	82-12-16	83-12-15 IS : 1943—1964
313.	10171 23	82-12-16	83-12-15 IS : 2818 (Pt-II)—1971
314.	10203 14	82-12-16	83-12-15 IS : 398 (Pt-II)—1976
315.	10377 35	83-01-01	83-12-31 IS : 398 (Pt-I)—1976

[सं. सी. एम. डी./13.12]

**S.O. 3369.**—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations 1955, as amended from time to time, the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 315 licences, particulars of which are given in the following Schedule, have been renewed during the month of December, 1982 :

Sl. No.	CM/L No.	Valid From	Indian Standard Specification No.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	00082 18	82-11-01	83-10-31 IS : 10 (Pt. II)—76
2.	00188 27	82-11-16	83-11-15 IS : 1184—1977
3.	00351 20	82-09-01	83-08-31 IS : 10 (Pt. II)—1976
4.	00554 29	82-11-01	83-10-31 IS : 561—1978
5.	00598 41	82-12-01	83-11-30 IS : 694—1977
6.	00649 35	82-11-01	83-10-31 IS : 325—1978
7.	00662 32	82-12-01	83-11-30 IS : 692—1973
8.	00831 31	82-11-16	83-11-15 IS : 226—1975
9.	00832 32	82-11-16	83-11-15 IS : 1977—1975
10.	00844 36	82-12-01	83-11-30 IS : 2818 (Pt. II)—1978
11.	00845 37	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
12.	00851 35	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
13.	00853 37	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
14.	00855 39	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
15.	00860 36	83-01-01	83-12-31 IS : 2818 (Pt. II)—1971
16.	00872 40	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
17.	00876 44	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
18.	00878 46	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
19.	00882 42	83-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
20.	00927 38	82-12-01	83-11-30 IS : 2818 (Pt. II)—1971
21.	00928 39	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
22.	00934 37	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
23.	00950 37	82-12-01	83-11-30 IS : 2566—1965
24.	01105 12	82-12-01	83-11-30 IS : 1554 (Pt. I)—1976
25.	01162 21	83-01-01	83-12-31 IS : 398 (Pt. II)—1976
26.	01186 29	83-01-01	83-12-31 IS : 398 (Pt. II)—1976
27.	01209 19	82-12-01	83-11-30 IS : 398 (Pt. II)—1976
28.	01432 24	82-11-16	83-11-15 IS : 1596—1977
29.	01545 32	82-11-16	83-11-15 IS : 325—1978
30.	01558 37	82-12-01	83-11-30 IS : 398 (Pt. I)—1976
31.	01642 32	82-11-01	83-10-31 IS : 2567—1978
32.	01649 39	82-11-16	83-11-15 IS : 1786—1979
33.	01687 45	82-09-01	83-08-31 IS : 398 (Pt. II)—1976
34.	01698 48	82-11-16	83-11-15 IS : 226—1975
35.	01734 35	82-11-01	83-10-31 IS : 417—1974
36.	01814 34	82-10-16	83-10-15 IS : 1660—1967
37.	01869 49	82-12-16	83-12-15 IS : 3564—1975
38.	01936 43	82-01-01	82-12-31 IS : 10 (Pt. II)—1976
39.	02104 15	82-10-16	83-10-15 IS : 10 (Pt. IV)—1976
40.	02155 26	82-10-16	83-10-15 IS : 10 (Pt. III)—1974
41.	02294 36	82-10-01	83-09-30 IS : 2480—1982
42.	02313 22	82-11-01	83-10-31 IS : 3686—1966
43.	02395 40	82-12-01	83-11-30 IS : 774—1971
44.	02713 34	82-12-01	83-11-30 IS : 2580—1965
45.	02738 43	82-12-01	83-11-30 IS : 1554 (Pt. I)—1976
46.	02782 47	82-10-16	83-10-15 IS : 2925—1975
47.	02851 43	82-12-16	83-12-15 IS : 2566—1965
48.	02862 46	82-12-01	83-11-30 IS : 2380—1965
49.	02942 45	82-12-16	83-12-15 IS : 415—1978
50.	03042 22	82-10-16	83-10-15 IS : 10 (Pt. II)—1976
51.	03065 29	82-11-16	83-11-15 IS : 458—1971
52.	03104 19	82-12-01	83-11-30 IS : 434—(Pt. I) 1964
53.	03156 31	82-11-16	83-11-15 IS : 1554 (Pt. I)—1976
54.	03244 30	82-12-16	83-12-15 IS : 10 (Pt. II)—1976
55.	03569 48	82-10-16	83-10-15 IS : 398 (Pt. II)—1976
56.	03588 51	82-11-16	83-11-15 IS : 6438—1980
57.	03602 32	82-11-10	83-10-31 IS : 1601—1960
58.	03605 35	82-12-01	83-11-30 IS : 1879—1975

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
59. 03811 39	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977		124. 06443 47	82-10-16	83-10-15	IS : 5456—1969	
60. 03821 41	82-11-01	83-10-31	IS : 3975—1979		125. 06459 55	82-10-16	83-10-15	IS : 4964—1980	
61. 03999 66	82-11-01	83-10-31	IS : 1520—1980		126. 06466 54	82-11-01	83-10-31	IS : 6595—1980	
62. 04003 19	82-11-01	83-10-31	IS : 6595—1980		127. 06475 55	82-10-16	83-10-15	IS : 8057—1976	
63. 04015 23	82-11-01	83-10-31	IS : 6914—1978		128. 06504 43	82-11-01	83-10-31	IS : 4250—1980	
64. 04016 24	82-11-01	83-10-31	IS : 6915—1978		129. 06513 44	82-11-16	83-11-15	IS : 633—1975	
65. 04019 27	82-11-01	83-10-31	IS : 398—1976		130. 06514 45	82-11-01	83-10-31	IS : 6914—1978	
66. 04057 33	82-11-16	83-11-15	IS : 633—1975		131. 06515 46	82-11-01	83-10-31	IS : 6915—1978	
67. 04061 29	82-12-01	83-11-30	IS : 398 (Part II)—1976		132. 06527 50	82-11-16	83-11-15	IS : 3564—1975	
68. 04062 30	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (Pt. 4)—1976		133. 06528 51	82-11-16	83-11-15	IS : 5346—1975	
69. 04421 33	82-11-01	83-10-31	IS : 633—1975		134. 06533 48	82-11-16	83-11-15	IS : 6914—1978	
70. 04478 50	82-11-16	84-05-15	IS : 2567—1978		135. 06534 49	82-11-16	83-11-15	IS : 6915—1978	
71. 04496 52	82-10-16	83-10-15	IS : 778—1971		136. 06539 54	82-12-01	83-11-30	IS : 5852—1977	
72. 04550 41	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975		137. 06555 54	82-21-01	83-11-30	IS : 8249—1976	
73. 04610 36	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (Pt. IV)—1976		138. 06559 58	82-12-01	83-11-30	IS : 4323—1967	
74. 04643 45	82-12-01	83-11-30	IS : 3976—1975		139. 06619 53	83-01-01	83-12-31	IS : 5281—1979	
75. 04729 50	82-10-16	83-10-15	IS : 1165—1975		140. 06665 59	82-08-01	83-07-31	IS : 303—1975	
76. 04732 45	82-10-16	83-10-15	IS : 1711—1970		141. 07179 54	82-09-01	83-08-31	IS : 4964—1980	
77. 04746 51	80-04-01	83-03-31	IS : 778—1971		142. 07201 35	82-09-16	83-00-15	IS : 1786—1979	
78. 04747 52	82-11-01	83-10-31	IS : 10 (Pt. III)—1974		143. 07206 40	82-09-16	83-09-15	IS : 564—1974	
79. 04749 54	82-11-01	83-10-31	IS : 2052—1979		144. 07209 43	82-09-16	83-09-15	IS : 410—1977	
80. 04750 47	82-11-01	83-10-31	IS : 1374—1979		145. 07212 38	83-01-01	83-12-31	IS : 1221—1971	
81. 04757 54	82-11-01	83-10-31	IS : 10—1970		146. 07219 45	82-09-16	83-09-15	IS : 398 (Pt. II)—1976	
82. 04772 53	82-11-01	83-10-31	IS : 829—1978		147. 07221 39	82-10-01	83-09-30	IS : 2653—1980	
83. 04787 60	82-11-01	83-10-31	IS : 916—1975		148. 07256 50	82-10-01	83-09-30	IS : 1786—1979	
84. 04812 44	82-08-16	83-08-15	IS : 1692—1974		149. 07265 51	82-10-16	83-10-15	IS : 834—1975	
85. 04815 47	82-12-01	83-11-30	IS : 335—1972		150. 07269 55	82-10-16	83-10-15	IS : 561—1972	
86. 04827 51	81-04-01	83-03-31	IS : 1703—1977		151. 07272 50	81-10-16	82-10-15	IS : 934—1976	
87. 04828 52	82-11-16	83-11-15	IS : 1848—1981		152. 07273 51	82-10-16	83-10-15	IS : 6595—1980	
88. 04834 50	82-09-01	83-08-31	IS : 269—1976		153. 07275 53	82-10-16	83-10-15	IS : 1786—1966	
89. 04855 55	82-12-01	83-11-30	IS : 6003—1970		154. 07277 55	82-11-01	83-10-31	IS : 829—1965	
90. 04860 52	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (Pt. II)—1980		155. 07284 54	82-11-01	83-10-31	IS : 7466—1974	
91. 04861 53	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (Pt. II)—1980		156. 07285 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4467—1980	
92. 04914 49	83-01-01	83-12-31	IS : 7407 (Pt. II)—1980		157. 07286 56	82-11-01	83-10-31	IS : 4582—1977	
93. 04916 51	83-01-01	83-12-31	IS : 624—1975		158. 07290 52	82-11-01	83-10-31	IS : 4323—1980	
94. 04995 66	82-08-16	83-08-15	IS : 375—1978		159. 07292 54	82-11-01	83-10-31	IS : 398 (Pt. II)—1976	
95. 05060 32	82-03-16	83-03-15	IS : 7407 (Pt. II)—1980		160. 07296 58	82-11-01	83-10-31	IS : 4985—1981	
96. 05160 35	82-11-01	83-10-31	IS : 1786—1979		161. 07309 46	82-11-16	83-11-15	IS : 2344—1973	
97. 05161 36	82-11-01	83-10-31	IS : 226—1975		162. 07319 48	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	
98. 05338 43	82-12-16	83-12-15	IS : 6914—1973		163. 07330 43	82-07-16	83-07-15	IS : 303—1975	
99. 05339 44	82-12-16	83-12-15	IS : 6915—1978		164. 07350 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1251—1973	
100. 05416 40	82-10-01	83-10-31	IS : 6248—1971		165. 07352 49	82-12-01	83-11-30	IS : 1786—1979	
101. 05500 35	82-09-16	83-09-15	IS : 694—1971		166. 07366 55	82-11-29	83-11-30	IS : 1601—1962	
102. 05561 48	82-11-01	83-10-31	IS : 561—1978		167. 07387 60	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971	
103. 05564 51	82-10-16	83-10-15	IS : 564—1975		168. 07390 55	82-12-01	83-11-30	IS : 1879—1975	
104. 05570 49	82-10-16	83-10-15	IS : 325—1978		169. 07398 63	82-12-01	83-11-30	IS : 7407 (aPt 2)—1980	
105. 05593 56	82-12-01	83-11-30	IS : 2906—1980		170. 07405 45	82-12-01	83-11-30	IS : 2834—1964	
106. 05615 45	82-11-16	83-11-15	IS : 398 (Pt. I)—1976		171. 07414 46	82-12-16	83-12-15	IS : 4174—1977	
107. 05619 49	82-11-16	83-11-15	IS : 1475—1978		172. 07440 48	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	
108. 05626 48	82-11-16	83-11-15	IS : 10 (Pt. II)—1976		173. 07442 50	83-01-01	83-12-31	IS : 1601—1960	
109. 05631 45	82-11-16	83-11-15	IS : 1308—1974		174. 07443 51	83-01-01	83-12-31	IS : 1601—1960	
110. 05634 48	82-11-01	83-10-31	IS : 325—1978		175. 07531 50	82-02-16	83-02-15	IS : 1891 (Part I)—1978	
111. 05672 54	82-12-01	83-11-30	IS : 778—1971		176. 07813 57	82-12-01	83-11-30	IS : 709 (Pt II)—1973	
112. 05673 55	82-12-01	83-11-30	IS : 1222—1973		177. 07843 63	82-07-16	83-07-15	IS : 781—1977	
113. 05690 56	82-12-16	83-12-15	IS : 458—1971		178. 07928 67	82-09-01	83-80-31	IS : 10 (Part IV)—1976	
114. 05771 56	82-12-16	83-12-15	IS : 781—1977		179. 07932 63	82-09-01	83-08-31	IS : 564—1975	
115. 05866 62	82-08-16	83-08-15	IS : 10 (Pt. IV)—1976		180. 07988 79	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	
116. 05980 63	82-03-16	83-03-15	IS : 2567—1973		181. 08030 38	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975	
117. 06074 42	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971		182. 08042 42	82-10-16	83-10-15	IS : 1786—1979	
118. 06095 47	82-08-01	83-07-31	IS : 8144—1976		183. 08063 47	82-11-01	83-10-31	IS : 1786—1979	
119. 06204 34	82-12-01	83-11-30	IS : 1223—(Pt II)—1972		184. 08064 48	82-11-01	84-03-31	IS : 398 (Pt II)—1976	
120. 06217 39	82-07-01	83-06-30	IS : 2567—1978		185. 08066 50	82-11-01	83-10-31	IS : 774—1971	
121. 06402 38	82-09-16	93-09-15	IS : 4964—1980		186. 08076 52	82-10-16	83-10-15	IS : 1547—1968	
122. 06421 41	82-10-01	83-09-30	IS : 1660 (Pt. I to IV)		187. 08078 54	82-11-01	83-10-31	KS : 4964—1980	
123. 06433 45	82-10-01	83-09-30	IS : 6047—1970						

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
188.	08079 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	252.	09149 56	82-12-01	83-11-30	IS : 562—1978
189.	08086 54	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	253.	09153 52	82-12-01	83-11-30	IS : 565—1975
190.	08087 55	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980	254.	09165 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1786—1979
191.	08100 35	82-11-16	83-11-15	IS : 226—1975	255.	09170 53	82-12-01	83-11-30	IS : 5455—1969
192.	08105 40	82-11-16	83-11-15	IS : 7538—1975	256.	09171 54	82-12-01	83-11-30	IS : 9224 (Pt I & II)—1979
193.	08107 42	82-11-16	83-11-15	IS : 633—1975	257.	09176 59	82-12-16	83-12-15	IS : 909—1975
194.	08126 45	82-11-16	83-11-15	IS : 1554 (Pt. I)—1976	258.	09181 56	82-12-16	83-12-15	IS : 2568—1978
195.	08132 43	82-09-01	83-08-31	IS : 2993—1975	259.	09245 55	83-01-01	83-12-31	IS : 2573—1975
196.	08141 44	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977	260.	09540 59	82-04-01	83-03-31	IS : 694—1977
197.	08147 50	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	261.	09824 68	82-07-16	83-07-15	IS : 2580—1965
198.	08148 51	82-11-16	83-11-15	IS : 1786—1979	262.	09979 86	82-10-01	83-09-30	IS : 261—1966
199.	08152 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1135—1973	263.	09992 83	82-10-16	83-10-15	IS : 246—1972
200.	08168 53	82-12-01	83-11-30	IS : 226—1975	264.	09995 86	82-10-16	83-10-15	IS : 4964—1980
201.	08173 52	82-12-16	83-12-15	IS : 1977—1975	265.	09997 88	82-10-16	83-10-15	IS : 633—1975
202.	08175 54	82-12-16	83-12-15	IS : 4654—1974	266.	09998 89	82-10-16	83-10-15	IS : 4323—1980
203.	08177 56	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	267.	09999 90	82-10-16	83-10-15	IS : 8259—1976
204.	08179 58	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	268.	10009 14	82-10-16	83-10-15	IS : 6595—1980
205.	08183 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	269.	10010 07	82-10-16	83-10-15	IS : 226—1975
206.	08187 58	82-12-16	83-12-15	IS : 158—1968	270.	10017 14	82-10-16	83-10-15	IS : 398 (Pt II)—1976
207.	08191 54	82-12-16	83-12-15	IS : 1161—1968	271.	10019 16	82-11-01	83-10-31	IS : 3906 (Pt I)—1974
208.	08208 46	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	272.	10027 16	82-11-01	83-11-31	IS : 5279—1969
209.	08209 47	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	273.	10034 15	82-11-01	83-10-31	IS : 2465—1969
210.	08218 48	82-12-16	83-12-15	IS : 226—1975	274.	10036 17	82-11-01	83-10-31	IS : 2865—1964
211.	08228 50	83-01-01	83-12-31	IS : 4323—1967	275.	10039 20	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980
212.	08243 49	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	276.	10040 13	82-11-01	83-10-31	IS : 4964—1980
213.	08250 48	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	277.	10045 18	82-11-01	83-10-31	IS : 1003 (Pt I)—1977
214.	08259 57	83-01-01	83-12-31	IS : 398 (Part II)—1976	278.	10046 19	82-11-16	83-11-15	IS : 2548—1980
215.	08271 53	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	279.	10054 19	82-11-16	83-11-15	IS : 2465—1969
216.	08293 59	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	280.	10063 20	82-11-16	83-11-15	IS : 5410—1969
217.	08295 61	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	281.	10067 24	82-11-16	83-11-15	IS : 4174—1977
218.	08354 55	82-02-01	83-01-31	IS : 10 (Pt II)—1976	282.	10068 25	82-11-16	83-11-15	IS : 4323—1980
219.	08385 62	82-12-01	83-11-30	IS : 2874—1964	283.	10080 21	82-11-16	83-11-15	IS : 3564—1956
220.	08388 65	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	284.	10082 23	82-12-01	83-11-30	IS : 4654—1974
221.	08442 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	285.	10088 29	82-12-01	83-11-30	IS : 10 (Pt II)—1976
222.	08523 54	82-12-01	83-11-30	IS : 1943—1964	286.	10090 23	82-12-01	83-11-30	IS : 780—1980
223.	08708 61	82-06-16	83-06-15	IS : 1554 (Pt I)—1976	287.	10091 24	82-12-01	83-11-30	IS : 398 (Pt II)—1976
224.	08855 71	82-08-16	83-08-15	IS : 1786—1979	288.	10098 31	82-12-01	83-11-30	IS : 778—1971
225.	08886 78	82-08-16	83-08-15	IS : 1729—1969	289.	10099 32	82-12-01	83-11-30	IS : 1921—1975
226.	08984 79	82-10-01	83-09-30	IS : 171—1973	290.	10100 08	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (Pt I)—1974
227.	08989 84	82-10-01	83-09-30	IS : 3312—1974	291.	10101 09	82-12-01	83-11-30	IS : 7406 (Pt II)—1980
228.	08999 86	82-10-01	83-09-30	IS : 3575—1977	292.	10106 14	82-12-01	83-11-30	IS : 2834—1964
229.	09007 43	82-10-01	83-09-30	IS : 3196—1976	293.	10107 15	82-12-01	83-11-30	IS : 5950—1971
230.	09014 42	83-11-01	83-10-31	IS : 8074—1976	294.	10108 16	82-12-01	83-11-30	IS : 2932—1974
231.	09023 43	82-09-16	83-09-15	IS : 1239 (Pt I)—1979	295.	10114 14	82-12-01	83-11-30	IS : 694—1977
232.	09025 45	82-10-16	83-10-15	IS : 561—1978	296.	10115 15	82-12-01	84-06-30	IS : 9295—1979
233.	09026 46	82-10-16	83-10-15	IS : 2052—1975	297.	10116 16	82-12-01	83-11-30	IS : 9182 (Pt III)—1979
234.	09031 43	82-10-16	83-10-15	IS : 7121—1973	298.	10123 15	82-12-16	83-12-15	IS : 398 (Pt I)—1976
235.	09052 48	82-10-16	83-10-15	IS : 2653—1980	299.	10124 16	82-12-16	83-12-15	IS : 3975—1979
236.	09066 54	82-11-01	83-10-31	IS : 3901—1975	300.	10126 18	82-12-16	83-12-15	IS : 4323—1980
237.	09081 53	82-11-01	83-10-31	IS : (398 Part I)—1976	301.	10130 14	82-12-16	83-12-15	IS : 1307—1973
238.	09085 57	82-11-16	83-11-15	IS : 694—1977	302.	10131 15	82-12-16	83-06-15	IS : 4323—1967
239.	09088 60	82-11-16	83-11-15	IS : 4654—1974	303.	10134 18	82-12-16	83-12-15	IS : 10 (Pt III)—1974
240.	09090 54	82-11-16	83-11-15	IS : 1977—1975	304.	10136 20	82-12-16	83-12-15	IS : 1786—1979
241.	09092 56	82-11-16	83-11-15	IS : 8828—1975	305.	10138 22	82-12-16	83-12-15	IS : 2580—1965
242.	09093 57	82-11-01	83-10-31	IS : 398 (Pt II)—1976	306.	10139 23	82-12-16	83-12-15	IS : 2580—1965
243.	09109 48	82-11-16	83-11-15	IS : 564—1975	307.	10144 29	82-12-16	83-12-15	IS : 8960—1978
244.	09115 46	82-11-16	83-11-15	IS : 8249—1976	308.	10150 18	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971
245.	09116 47	82-11-16	83-11-15	IS : 2567—1978	309.	10156 24	82-12-01	83-11-30	IS : 458—1971
246.	09117 48	82-11-16	83-11-15	IS : 561—1978	310.	10163 23	82-12-01	83-11-30	IS : 4985—1968
247.	09121 44	82-11-16	83-11-15	IS : 8249—1976	311.	10167 27	82-12-16	83-12-15	IS : 1221—1971
248.	09122 45	82-11-16	83-11-15	IS : 778—1971	312.	10169 29	82-12-16	83-12-15	IS : 1943—1964
249.	09146 53	82-12-01	83-11-30	IS : 158—1968	313.	10171 23	82-12-16	83-12-15	IS : 2818 (Pt II)—1971
250.	09147 54	82-12-01	83-11-30	IS : 341—1973	314.	10203 14	82-12-16	83-12-15	IS : 398 (Pt II)—1976
251.	09148 55	82-12-01	83-11-30	IS : 694—1977	315.	10377 35	83-01-01	83-12-31	IS : 398 (Pt I)—1976

नई दिल्ली, 1983-07-27

का० अ० 3370—समय- समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन विज्ञान) विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के ब्यौरे नोबे अनुमोदी में दिए गए हैं वे रद्द कर दिए गए हैं और अब वापस लिए गए हैं।

## अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या और पदनाम	भारत के राजपत्र की एस ओ संख्या और दिनांक जिसमें भारतीय मानक की स्थापना छरी थी	विवरण
1	2	3	4
1.	IS: 1885 (भाग 13/अनु 1)—1968 विद्युत् तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली : भाग 13 दूर संचारण प्रेषण लाइनें और तरंग नियंत्रक : अनु-1 सामान्य प्रेषण लाइन	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1968-06-08 में एस ओ 2036 दिनांक 1968-05-20 के अधीन प्रकाशित	} क्योंकि इस भारतीय मानक में दी गई अपेक्षाएं अब
2.	IS: 1885 (भाग 13/अनु 2)—1967 विद्युत् तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली भाग 13 दूर संचारण प्रेषण लाइनें और तरंग नियंत्रक : अनु-2 सूक्ष्म तरंग प्रेषण लाइनें और तरंग नियंत्रक	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1967-08-05 में एस ओ 2645 दिनांक 1967-07-27 के अधीन प्रकाशित।	
3.	IS: 2106 (भाग 10)—1965 इलेक्ट्रॉनिकी और बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरण परीक्षण : भाग 10 जल डुबाऊ परीक्षण	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1965-10-02 में एस ओ 3059 दिनांक 1965-09-21 के अधीन प्रकाशित	} क्योंकि इस भारतीय मानक में दी गई अपेक्षाएं अब
4.	IS: 2106 (भाग 15)—1966 इलेक्ट्रॉनिकी और बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरण परीक्षण : भाग 16 गैस कसावट परीक्षण	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1966-12-31 में एस ओ 4023 दिनांक 1966-12-20 के अधीन प्रकाशित	
5.	IS: 2106 (भाग 16)—1971 इलेक्ट्रॉनिकी और बिजली संयंत्रों के लिए पर्यावरण परीक्षण : भाग 16 कंपन परीक्षण	भारत के राजपत्र भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) दिनांक 1973-11-24 में एस ओ 3255 दिनांक 1973-11-12 के अधीन प्रकाशित	IS: 1885 (भाग 16)—1981 में शामिल कर ली गई हैं।  IS: 9000 (भाग 15)—1982 में शामिल कर ली गई हैं।  IS: 9000 (भाग 8) 1981 में शामिल कर ली गई हैं।

[सं० सी एम डी/13 : 7]

New Delhi, the 1983-07-27

S.O. 3370 In pursuance of sub-regulation (1) of regulation 5 of the Indian Standards Institution (certification Marks) Regulations 1955 as amended from time to time, it is, hereby notified that the Indian Standard(s), particulars of which are mentioned in the Schedule, given hereafter, have been cancelled and stands withdrawn:

## SCHEDULE

Sl. No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
1	2	3
1. IS : 1885 (Part XIII/Sec 1)—1968 Electro-technical Vocabulary: Part XIII Telecommunication transmission lines and waveguides Sec 1 General transmission lines	S.O. 2036 dated 1968-05-20 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3 Sub-section (ii) dated 1968-06-08	} As the requirements of these Indian Standards have been covered in IS : 1885 (Part LVI)—1981
2. IS : 1885 (Part XIII/Sec 2)—1967 Electro-technical Vocabulary : Part XIII Telecommunication transmission lines and waveguides Sec 2 Microwave transmission lines and waveguides	S.O. 2645 dated 1967-07-27 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1967-08-05	

1	2	3	4
3. IS : 2106 (Part X)—1965 Environmental tests for electronic and electrical equipment: Part X Water immersion test	S.O. 3059 dated 1965-09-21 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1965-10-02	} As the requirements of these Indian Standards have been covered in IS : 9000 (Part XV)—1982	
4. IS : 2106 (Part XV)—1966 Environmental tests for electronic and electrical equipment: Part XV Gas-tightness test	S.O. 4023 dated 1966-12-20 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1966-12-31		
5. IS : 2106 (Part XVI)—1971 Environmental tests for electronic and electrical equipment: Part XVI Vibration test.	S.O. 3255 dated 1973-11-12 published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 1973-11-24	As the requirements of these Indian Standard have been covered in IS: 9000 (Part VIII)—1981	

[No. CMD/13 : 7]

नई दिल्ली, 1983-08-08

क्र०आ० 3371.—समय- समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 14 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या सी एम/एल-1098856 जिसके ब्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं लाइसेंसधारी के निवेदन पर 1983-03-24 से रद्द कर दिए गए हैं।

## अनुसूची

क्रम	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक संख्या
1	2	3	4	5
	सी एम/एल-1098856 1983-07-14	मैमर्स बोरा कम्पोनेंट्स एंड कंटे- नर्स प्रा० लि० 9-बी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट कांडीवली पश्चिम बम्बई-400067 (महाराष्ट्र)	द्रवित पेट्रोलियम गैसों के साथ प्रयुक्त घरेलू गैस के चूल्हे	IS : 4246-1978 द्रवित पेट्रो- लियम गैसों के साथ प्रयुक्त- घरेलू गैस के चूल्हों की विशिष्ट

[सी एम डी/551098856]

New Delhi, 1983-08-08

S.O. 3371.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (certification Marks) Regulation, 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies the licence No. CM/L—1098856 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1983-03-24 at the request of the licensee.

## SCHEDULE

Sl. Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
1. CM/L—1098856 1983-07-14	M/s. Vora Components & Containers Pvt. Ltd., 9-B, Govt. Industrial Estate, Kandivli West, Bombay-400067 (Maharashtra)	Domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases	IS : 4246—1978 Specification for domestic gas stoves for use with liquefied petroleum gases

[CMD/55 : 1098856]

क्र०आ० 3372.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंस संख्या 0790762 जिसके ब्योरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं लाइसेंसधारी के अपने अनुरोध पर 1979-08-16 से रद्द कर दिया गया है:

## अनुसूची

क्रम लाइसेंस संख्या और तिथि लाइसेंसधारी का नाम और पता रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन सम्बद्ध भारतीय मानक संख्या वस्तु/प्रक्रिया

1	2	3	4	5
1. सी एम/एल-0790762 1979-08-03	सर्वश्री स्वास्तिक टैक्सटाइल सादे केलिको करवों की नाल IS : 1794—1971 सादे केलिको करवों की नाल की विशिष्टि	इंजीनियर्स प्रा० लि० एम्बिका-रीज डिवीजन अम्बिका आयल मिल कम्पाउंड गोमती-पुर दरवाजे के बाहर अहमदाबाद 380021 (गुजरात)		

[सी एम सी/55 : 0790762]

ए० पी० बनर्जी, अपर महानिदेशक

S.O. 3372.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (certification Marks) Regulation 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that licence No. 0790762 particulars of which are given below has been cancelled with effect from 1979-08-16 at the request of the licensee.

## SCHEDULE

Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the licence cancelled	Relevant Indian Standards
CM/L—0790762 1979-08-03	M/s. Swastik Textile Engineers Pvt. Ltd., Accessories Division, Ambika Oil Mill Compound, Outside Gombtipur Darwaja, Ahmedabad—380021 (Gujarat)	Shuttles for Plain Calico Looms	IS: 1794—1971 Specification for Shuttles for plain calico looms

[CMD/55 : 0790762]

A.P. BANERJI, Additional Director General

## ऊर्जा मन्त्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1983

का०आ० 3373.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन० के० 62 से एन० के० ई० बी० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदपात्र अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962

(1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षों कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेपसक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।



## अनुसूची

ए. के-62 से एन के ई बी

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	ए आर आई	से०
चालास	58	0	07	20
कार्टट्रेक		0	00	80
73/पी		0	05	90
73/पी		0	13	00

[सं० 12016/87/83-प्रोड०]

## MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 6th August, 1983

**S.O. 3373.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NK-62 to NKEB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from N. K.—62 To N.K.E.B.

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Chalasan	58	0	07	20
	Cart track	0	00	80
	73/P	0	05	90
	73/P	0	13	00

[No. 12016/87/83-Prod.]

**का०आ० 3374.**—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-9 से कलोल-169 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

589GI83—7

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगी ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

कलोल-9 से कलोल-169 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य : गुजरात जिला और तालुका : गांधीनगर

गांव	ब्लॉक नं०	हे०	आर	से०
अडालज	407	0	18	75
	कार्टट्रेक	0	05	10
	410	0	09	10

[सं० ओ-12016/99/83 प्रोड०]

**S.O. 3374.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Kalol-9 to Kalol-169 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission :

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from Kalol—9 to Kalol—169.

State : Gujarat District Taluka : Gandhinagar

Village	Block No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiare
Adalaj	407	0	18	75
	Cart track	0	05	10
	410	0	09	10

[No. O-12016/99/83-Prod.]

का० आ० 3375.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कलोल-111 से के-7 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

कलोल 111 से के-7 तक पाइप लाईन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला और तालुका - गांधीनगर

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सें०
शेरथा	1001/2	0	02	62
	1000	0	11	20

[सं० ओ० 12016/100/83-प्रोड०]

S.O. 3375.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport

of petroleum from Kalol-111 to K-7 in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## SCHEDULE

Pipeline from Kalol -111 to K-7

State : Gujarat Dist &amp; Taluka : Gandhinagar

Village	Survey No.	Hec- tare	Acre	Cen- tiar
Sertha	1001/2	0	02	62
	1000	0	11	20

[No. O-12016/100/83-Prod.]

का० आ० 3376,—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उभेराट से हजीरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

**अनुसूची**

उभेराट से हजीरा तक पाईप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य : गुजरात जिला : बलसार तालुका : नवसारी

गांव	ब्लॉक नं०	हे०	आर०	से०
दांती	49	0	42	08
	60	0	12	80
	61	0	10	11
	36	0	89	75
	240	2	51	00

[सं० O-12016/101/83-प्रोड०]

**S.O. 3376.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Ubharat to Hajira in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

**SCHEDULE**

Pipeline from Ubharat to Hajira

State : Gujarat District : Bulsar Taluka : Navsari

Village	Block No.	Hectare	Area	Centiare
Danti	49	0	42	08
	60	0	12	80
	61	0	10	11
	36	0	89	75
	240	2	51	00

[No. O-12016/101/83-Prod.]

**का०आ० 3377.**—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में उभेराट से हजीरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये

पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

**अनुसूची**

उभेराट से हजीरा तक पाईप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य : गुजरात जिला : सुरत तालुका : चोरसी

गांव	ब्लॉक नं०	हे०	आर०	से०
भाटपार	333	0	71	52

[सं० O-12016/102/83-प्रोड०]

राजेन्द्र सिंह, निदेशक

**S.O. 3377.**—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from UBHARAT to HAJIRA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

**SCHEDULE**

Pipeline from Ubharat to Hajira

State : Gujarat District : Surat Taluka : Chorasi

Village	Block No.	Hect.	Area	Cen.
Bhatpore	333	0	71	52

[No. O-12016/102/83-Prod.]

RAJENDRA SINGH, Director

## परमाणु ऊर्जा विभाग

## आदेश

बम्बई, 12 अगस्त, 1983

क्र०आ० 3378.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2) नियम 12 के उपनियम (2) की धारा (ख) तथा नियम 24 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के दिनांक 7 जुलाई, 1979 के आदेश सं०आ० 2537 में निम्नलिखित संशोधन करने हैं अर्थात्:—

अनुसूची में—

(क) भाग 1—सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग “ख” में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
2. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	सभी	निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र/सचिव, भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग	
5. तारापुर परमाणु बिजली घर के पद	मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजली घर	मुख्य अधीक्षक, तारापुर परमाणु बिजली घर	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक, विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
6. विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग के पद	निदेशक, (अभियांत्रिकी)	निदेशक, (अभियांत्रिकी)	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
7. राजस्थान परमाणु बिजली घर के पद	स्टेशन अधीक्षक तथा मुख्य परियोजना अभियन्ता राजस्थान परमाणु बिजली घर	स्टेशन अधीक्षक तथा मुख्य परियोजना अभियन्ता राजस्थान परमाणु बिजली घर	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, निदेशक विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
8. मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पद	परियोजना निदेशक, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	परियोजना निदेशक, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग, निदेशक विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
9. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के पद	मुख्य परियोजना अभियन्ता, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य परियोजना अभियन्ता, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग : निदेशक विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
15. निर्माण तथा सेवा वर्ग के पद	निदेशक निर्माण तथा सेवा वर्ग	निदेशक निर्माण तथा सेवा वर्ग	सभी	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
(ख) भाग-II सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "सी" में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—					
(5) विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग के पद	मुख्य प्रशासन अधिकारी विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	मुख्य प्रशासन अधिकारी विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	सभी	निदेशक (अभियांत्रिकी), विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
(6) राजस्थान परमाणु बिजली घर के पद	मुख्य प्रशासन अधिकारी, राजस्थान परमाणु बिजली घर	मुख्य प्रशासन अधिकारी, राजस्थान परमाणु बिजली घर	सभी	स्टेशन अधीक्षक तथा मुख्य परियोजना अभियन्ता राजस्थान परमाणु बिजली घर	

1	2	3	4	5	6
(7) मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना के पद	मुख्य प्रशासन तथा लेखा अधिकारी, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य प्रशासन तथा लेखा अधिकारी, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	सभी	परियोजना निदेशक, मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	
(8) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य प्रशासन अधिकारी, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य प्रशासन अधिकारी, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	सभी	मुख्य परियोजना अभियंता, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	
(15) निर्माण सेवा वर्ग के पद	निदेशक निर्माण तथा सेवा वर्ग	निदेशक, निर्माण तथा सेवा वर्ग	सभी	अपर सचिव/संयुक्त सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	
(ग) भाग-III—सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "घ" वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—					
(4) तारापुर परमाणु बिजली के पद धर	प्रशासन अधिकारी-3	प्रशासन अधिकारी-3	सभी	मुख्य प्रशासन अधिकारी, तारापुर परमाणु जली धर	
(8) नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के पद	प्रशासन अधिकारी-III नरोरा परमाणु परियोजना	प्रशासन अधिकारी-III नरोरा परमाणु परियोजना	सभी	मुख्य प्रशासन अधिकारी, नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	
(15) निर्माण तथा सेवा वर्ग	प्रशासन अधिकारी, निर्माण तथा सेवा वर्ग	प्रशासन अधिकारी, निर्माण तथा सेवा वर्ग	सभी	निदेशक, निर्माण तथा सेवा वर्ग।	

राष्ट्रपति यह भी निदेश देते हैं कि उपर्युक्त आदेश की अनुसूची के भाग 1, 2 तथा 3 में त्रिनिदिष्ट सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "म", सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ग" तथा सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "घ" के पदों के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी :—

(क) भाग 1—सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "ख"

1	2	3	4	5	6
17. काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के पद	मुख्य परियोजना अभियन्ता काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य परियोजना अभियन्ता काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	सभी (1) से (4) तक	प्रधान सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग निदेशक, विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग	
(ख) भाग II—सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग “ग”					
17 काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के पद	मुख्य प्रशासन अधिकारी, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	मुख्य प्रशासन अधिकारी, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	सभी	मुख्य परियोजना अभियन्ता काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	
(ग) भाग III—सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग “घ”					
(17) काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना के पद	प्रशासन अधिकारी-III, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	प्रशासन अधिकारी-III, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	सभी	मुख्य प्रशासन अधिकारी, काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना	

[सं० 2/2/82-सतर्कता]  
टी०सी० सत्यकीर्ति, निदेशक

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

#### ORDER

Bombay, 12th August 1983

S.O. 3378.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 of clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following amendments in the order of the Department of Atomic Energy S.O. 2537, dated the 7th July 1979, namely:—

In the Schedule:—

(a) In Part I—General Central Service, Group 'B' the existing entries shall be substituted by the following, namely:—

1	2	3	4	5	6
2. Bhabha Atomic Research Centre (BARC)	Controller, Bhabha Atomic Research Centre	Controller, Bhabha Atomic Research Centre	All	Director, Bhabha Atomic Research Centre/Secretary to the Govt. of India, Department of Atomic Energy.	
5. Posts in the Tarapur Atomic Power Station (TAPS)	Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station	Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.	
6. Posts in the Power Projects Engineering Division (PPED)	Director (Eng.)	Director (Eng.)	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.	
7. Posts in the Rajasthan Atomic Power Station (RAPS)	Station Superintendent and Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Station	Station Superintendent and Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Station	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.	
8. Posts in the Madras Atomic Power Project (MAPP)	Project Director, Madras Atomic Power Project	Project Director, Madras Atomic Power Project	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.	
9. Posts in the Narora Atomic Power Project (NAPP)	Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project	Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.	
15. Posts in the Construction & Services Group (C & S Group).	Director, Construction and Services Group.	Director, Construction & Services Group.	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy.	

(b) in part II—General Central Service, Group 'C'—against the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
(v)	Posts in the Power Projects Engineering Division (PPED)	Chief Administrative Officer, Power Projects Engineering Division	Chief Administrative Officer, Power Projects Engineering Division.	All	Director (Eng.), Power Projects Engineering Division.
(vi)	Posts in the Rajasthan Atomic Power Station (RAPS)	Chief Administrative Officer, Rajasthan Atomic Power Station	Chief Administrative Officer, Rajasthan Atomic Power Station.	All	Station Superintendent & Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Station.
(vii)	Posts in the Madras Atomic Power Project (MAPP)	Chief Administrative & Accts Officer, Madras Atomic Power Project.	Chief Administrative & Accounts Officer, Madras Atomic Power Project.	All	Project Director, Madras Atomic Power Project.
(viii)	Posts in the Narora Atomic Power Project (NAPP)	Chief Administrative Officer, Narora Atomic Power Project.	Chief Administrative Officer, Narora Atomic Power Project.	All	Chief Project Engineer, Narora Atomic Power Project.
(xv)	Posts in the Construction & Services Group (C&S G)	Director, Construction & Services Group	Director, Construction & Services Group	All	Additional Secretary/Joint Secretary, Department of Atomic Energy.

1	2	3	4	5	6
(c) in Part III—General Central Service, Group 'D' against the existing entries, the following shall be substituted, namely:—					
(iv) Posts in the Tarapur Atomic Power Station (TAPS)	Administrative Officer-III	Administrative Officer-III	All	Chief Administrative Officer, Tarapur Atomic Power Station.	
(viii) Posts in the Narora Atomic Power Project (NAPP)	Administrative Officer-III, Narora Atomic Power Project.	Administrative Officer-III, Narora Atomic Power Project.	All	Chief Administrative Officer, Narora Atomic Power Project.	
(xv) Posts in the Construction and Services Group (C & S Group)	Administrative Officer, Construction and Services Group	Administrative Officer, Construction & Services Group	All	Director, Construction & Services Group	

The President also directs that in respect of the posts in the General Central Service, Group 'B' the General Central Service Group 'C' and the General Central Service, Group 'D' specified in Parts I, II and III of the Schedules to the above said Order, the following entries shall be added:—

(a) Part I, General Central Service, Group 'B'

17. Posts in the Kakrapar Atomic Power Project (KAPP)	Chief Project Engineer, Kakrapar Atomic Power Project	Chief Project Engineer, Kakrapar Atomic Power Project	All	Principal Secretary, Department of Atomic Energy. (i) to (iv) Director, Power Projects Engineering Division.
---	---	---	-----	---

(b) Part II—General Central Service, Group 'C'

(xvii) Posts in the Kakrapar Atomic Power Project (KAPP)	Chief Administrative Officer, Kakrapar Atomic Power Project	Chief Administrative Officer, Kakrapar Atomic Power Project	All	Chief Project Engineer, Kakrapar Atomic Power Project.
--	---	---	-----	--

(c) Part III—General Central Service, Group 'D'

(xvii) Posts in the Kakrapar Atomic Power Project (KAPP)	Administrative Officer-III, Kakrapar Atomic Power Project.	Administrative Officer-III, Kakrapar Atomic Power Project	All	Chief Administrative Officer, Kakrapar Atomic Power Project.
--	--	---	-----	--

[No. 2/2/82—Vig]

T. C. SATHYAKEERTHY, Director

### निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1983

कां०आ० 3379—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली की बृहत योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61वां) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 12-2-1983 के नोटिस संख्या एफ० 3 (154)/67/एम पी द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्ति सुझावे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर आमन्त्रित किए गए थे:

और यतः उपर्युक्त संशोधन के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 "क" को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की बृहत योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः—

### संशोधन

धारा-क (मुख्य योजना के मूल पाठ के क्षेत्रीय विनियम अध्याय-2) में लिखित पैरा-5 जो "उपयोग क्षेत्रों में आवश्यकताओं से सम्बन्धित व्यवस्था ए" के शीर्षक के अन्तर्गत है तथा जिसमें क्षेत्रीय व उप खण्ड सम्बंधी विनियमों का वर्णन है:

1. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 55 पर दाईं ओर के नोट (3) जिसे अधिसूचना संख्या के-12014/6/75-यू० डी० 1 डी० डी० II ए (आयतन-3) दिनांक 29-10-82 द्वारा संशोधित किया गया था, के बाद इसमें निम्नलिखित नोट (4) जोड़ा गया है:—

"(4) घनता की गणना हेतु बरसाती मंजिल को आवासीय इकाई के रूप में माना जाए।"

2. दिल्ली मुख्य योजना के पृष्ठ 57 पर दाईं ओर (डी) भूखण्ड का अभिमुख के ऊपर पैरा (1) के उप-पैरा (सी) के अन्तिम पैरे की पहली एवं तीसरी पंक्तियों में क्रमशः 25 तथा 500 की संख्याओं के स्थान पर अब क्रमशः 50 तथा 100 किया गया है।

[सं० के-12016/10/82-डी० डी० II ए]

चन्द्र सैन, उप सचिव

**MINISTRY OF WORKS & HOUSING**

New Delhi, the 10th August, 1983

**S.O. 3379.**—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding zoning regulations mentioned hereunder, were published as Notice No. F. 3(154)/67-M.P. dated 12-2-1983 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objection/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

And whereas, no objection or suggestions have been received with regard to the said modifications ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, namely;

**MODIFICATIONS**

In paragraph 5 titled 'Provision Regarding Requirements In Use Zones' occurring in Section A—Zoning Regulations—Chapter II of the text of Master Plan dealing with the zoning and sub-division regulations:

1. At page 55, for left hand side of the Master Plan for Delhi, after note(3) amended vide notification No. K-12014/6/75-UDI/DDIIA (Vol. III) dated 29-10-82 the following note (4), is inserted namely :—

"(4) For the purpose of density calculation, Barsati Floor is reckoned as a dwelling unit."

2. "At page-57, right hand side of the Master Plan for Delhi, last para of sub-para I(c) the figures of 25 and 500 occurring in the first and third line respectively are substituted by 50 and 1000 respectively".

[No. K-12016/10/82-DDIIA]  
CHANDAR SAIN, Dy. Secy.

**संचार मंत्रालय**

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1983

**का० आ० 3380.**—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गये भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 134 के ढङ्ग III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बुधापाण्डि टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-83 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[संख्या 5-4/83-सी एच बी]

आर० सी० कटारिया, सहायक महानिदेशक  
(पो० एच० बी०)

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

(P&amp;T Board)

New Delhi, the 19th August, 1983

**S.O. 3380.**—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by

S.O. No. 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specified 1-9-1983 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in BOOTH A PANDY Telephone Exchange TAMIL NADU Circle.

[No. 5-4/83-PHB]

R. C. KATARIA, Asstt. Director General (PHB)

**MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION**

(Department of Labour)

New Delhi, the 6th August, 1983

**S.O. 3381.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1983.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD**

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 63 of 1981

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Jealgora Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited.

**AND**

Their Workmen

**APPEARANCES :**

For the Employers—Shri R. S. Murty, Advocate.

For the Workman—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh

**STATE :** Bihar**INDUSTRY :** Coal.

Dhanbad, dated the 29th July, 1983

**AWARD**

By Order No. L-20012(234)/81-D.III(A) dated, the 3rd November, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of its powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Jealgora Colliery of Bhowra Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, at and Post Office Jealgora District Dhanbad, in refusing employment to Shri S. N. Ojha, Accounts Clerk, with effect from the 11th April, 1981 is justified? If not to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The case of the concerned workman, Shri S. N. Ojha, Accounts Clerk, is that he is a permanent employee of Jealgora Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited. In the year 1979 Jealgora colliery was closed for sometime as the mine caught fire and almost all the workmen of Jealgora colliery were transferred by the management to their other establishments, and, in that process, he too was transferred and posted in Development & Construction Division at 'Vikas Bhawan' at Bhuggatdih, Jharia, where he joined. Consequent upon the normalisation of Jealgora colliery the management again transferred back all those employees to Jealgora colliery who had been earlier transferred to other establishments, and, in that process, by Office Order dated 8-12-80 issued by the Head Quarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., at Karmik Bhawan, Dhanbad, he too was re-transferred to Jealgora colliery where he was directed to join on being relieved by the Development & Construction Division at Vikas Bhawan where he was then posted. The authorities of the Development & Construction Division at Vikas Bhawan relieved him with effect from 10-4-81 by an Office Order of the same



date whereupon he reported for duty to the Agent, Jealgora Colliery, on 11-4-81. He was, however, not allowed to join his duty at Jealgora colliery and was asked to wait for appropriate orders, and, subsequently, by letter dated 16-4-81 of the Agent, Jealgora colliery, he was informed that since he did not join soon after his transfer order dated 8-12-80 issued by the Head Quarters, the colliery management had in the meantime arranged for another Accounts Clerk from Bhowra Area office within which Jealgora colliery lies and hence his services were not required and he should report back to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan. Thus, when he was refused to resume duty at Jealgora colliery, the matter was reported to higher authorities by him as well as by the sponsoring union, and, ultimately, he was allowed to resume his duty in his original post of Accounts Clerk at Jealgora colliery with effect from 30-10-81 but he was refused his wages for the period between 11-4-81 and 30-10-81. His contention is that the action of the management in refusing to pay his wages for the period between 11-4-81 and 30-10-81 is unjustified and he should be paid full wages and all other benefits for the said period as if he was in employment throughout the said period.

3. The case of the management, on the other hand, is that the concerned workman, Sri S. N. Ojha, Accounts Clerk, was, no doubt, previously working in Jealgora, colliery. There was, however, a very serious fire in January, 1979 in the said colliery and in consequence the colliery was closed but instead of retrenching the workmen the management transferred them to different collieries and establishments of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and in that process, he was also transferred to Development & Construction Division of Head Office located in Vikas Bhawan, Jharia, Dhanbad, which was previously known as Bhuggatdih building. After Jealgora colliery was re-opened towards the end of 1980 he was transferred back to Jealgora colliery vide Office Order dated 8-12-80 issued by the Senior Personnel Officer (Man power) of the Head Office of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. at Karmik Bhawan, Dhanbad. He, however, did not evince any interest in getting himself relieved from the Development & Construction Division at Vikas Bhawan. He, however, got himself relieved from the Development & Construction Division at Vikas Bhawan with effect from 10-4-81 and reported at Jealgora colliery on 11-4-81. He was then directed by the Agent, Jealgora colliery, to report back for duty to the Development and Construction Division at Vikas Bhawan immediately and he was also issued a letter dated 16-4-81 to this effect by the Agent, Jealgora colliery. This had become necessary as a considerable period had lapsed since his transfer order dated 8-12-80 posting him back to Jealgora colliery and in the meantime because of urgent requirement another Accounts Clerk was posted at Jealgora. He, however, refused to carry out the order given to him to report back to the Development Construction Division at Vikas Bhawan and preferred to remain idle for which he is solely to be blamed. Subsequently, the case was reviewed by the management of Bhowra Area of Ms. Bharat Coking Coal Ltd. within which Jealgora colliery lies and he was posted in Bhowra Area office by order dated 14/16-7-81 of the Personnel Manager, Bhowra Area and was directed to report for duty to the Area Finance Manager/Senior Administrative Officer, Bhowra Area, with immediate effect but he refused to carry out that order as well and remained idle even thereafter. Subsequently, he was posted at Jealgora colliery, but even thereafter he did not join duty at Jealgora colliery for a long time and ultimately he reported for duty there only on 2-11-81 and for this the management had to find a post for him at Jealgora colliery and carry out necessary re-organisation and allocation of work. Under the circumstances the presumption made in the order of reference that the management refused employment to him with effect from 11-4-81 is misconceived and untenable, and the question of paying any wages to him for the period between 11-4-81 and 30-10-81 as claimed by him also does not arise and he is entitled to no relief.

4. The parties have examined one witness each and some documents have also been got exhibited on either side.

5. It is the admitted position that there was a serious outbreak of fire in Jealgora colliery in early 1979 as a result whereof the workmen of the said colliery were transferred by the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. to their other collieries and establishments and, in that process, the concerned workman, Sri S. N. Ojha, Accounts Clerk of Jealgora colliery, was also transferred to Development & Construc-

tion Division at Vikas Bhawan at Jharia where he joined, and, consequent upon normalisation of the Jealgora colliery towards the end of 1980, the management again transferred back to Jealgora colliery all those employees who had been earlier transferred to other establishment, and, in that process, the concerned workman, Sri S. N. Ojha, was also transferred back to Jealgora colliery by Office Order dated 8-12-80 (Ext. W-1) issued from the Head Quarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. at Karmik Bhawan, Dhanbad under the signature of Sr. Personnel Officer (Man Power) under which he was directed to report to the Supdt. Jealgora colliery, for further assignment of duty on being relieved by his then controlling officer at the Development & Construction Division at Vikas Bhawan. It is also the admitted position that thereafter he was not immediately relieved by the Development & Construction Division at Vikas Bhawan to join his new posting at Jealgora colliery and it was only after a lapse of about four months that, by Office Order dated 10-4-81 (Ext. W-2) of the Development & Construction Division at Vikas Bhawan, he was relieved with effect from that date to join his new posting at Jealgora colliery and on the very next date he submitted his joining report dated 11-4-81 (Ext. W-3) to the Agent, Jealgora colliery, but he was not allowed to join and instead he was given a letter dated 16-4-81 (Ext. W-4) by the Agent, Jealgora colliery, with reference to his joining report dated 11-4-81, intimating him that the letter releasing him from Development & Construction Division at Vikas Bhawan had not been received at Jealgora colliery till then but since there had been considerable delay in his joining at Jealgora colliery after his transfer order dated 18-12-80 issued by the Headquarters, another Accounts Clerk from the Bhowra Area had been arranged in the meantime who had already been posted at Jealgora in his place and hence there being no requirement of any other Accounts Clerk at Jealgora colliery he should report back to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan immediately. The concerned workman admittedly did not rejoin at the Development & Construction Division at Vikas Bhawan in pursuance of the said letter dated 16-4-81 (Ext. W-4) of the Agent, Jealgora colliery and his evidence in his cross-examination is that on receipt of the said letter dated 16-4-81 from the Agent, Jealgora colliery, he had gone to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan to join there but he was not permitted to join there and he was told there that he had already been relieved from there to join at Jealgora colliery and the joining report which he had submitted there was neither received by anybody nor anything was given to him in writing refusing him to join there. On the other hand it is the evidence of Sri N.K. Prasad Singh (MW 1) Personnel Manager of Bhowra Area, within which Jealgora colliery lies, that the concerned workman, Sri S. N. Ojha, did not go back to Vikas Bhawan to join his duty nor did he join his duty there as directed.

6. It is next the evidence of Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) that after sometime Sri S. P. Rai, Joint General Secretary of the sponsoring union, took up the issue with the General Manager, Bhowra Area, and thereafter Sri S. N. Ojha was directed to report at Bhowra Area Office as Accounts Clerk by Office Order dated 14/16-7-81 (Ext. M-2). The said Office Order (Ext. M-2) stated, inter-alia, that since Sri S. N. Ojha, on being transferred by the Head Quarters from the Development & Construction Division to Jealgora colliery had reported for duty at Jealgora colliery, after being relieved by the Development & Construction authorities, but was not allowed to join at Jealgora colliery as there was no requirement of Accounts Clerk at Jealgora colliery, he was now being posted as Accounts Clerk in the Bhowra Area Office and was directed to report for duty to the Area Finance Manager/Sr. Administrative Officer, Bhowra Area, with immediate effect. Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) has further deposed that Sri S. N. Ojha also did not join at Bhowra Area Office in spite of the aforesaid Office Order dated 14/16-7-81 (Ext. M-2) although the distance between Jealgora colliery and Bhowra Area office is only about 3 to 4 kilometres. It is also not disputed by the concerned workman Sri S. N. Ojha (WW-1) that he did not join at Bhowra Area Office, but his explanation for that in his cross-examination is that he had not received any Office Order dated 14/16-7-81 (Ext. M-2) directing him to join at Bhowra Area Office. But I am not prepared to believe his aforesaid evidence as there is no specific denial of the receipt of this Office Order dated 14/16-7-81 by the concerned workman in his written statement or in his rejoinder, and the "distributions" noted below the said Office Order (Ext. M-2) also clearly show that copies of the Office Order had been sent to the person concerned, namely, Sri S. N. Ojha, besides other concerned authorities.

7. It is further the evidence of Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) that subsequently Sri Bindeshwari Dubey, President of the sponsoring union, took up the issue with the General Manager and Director (Personnel) at the Head Quarters at Dhanbad and then the issue was again reviewed and Sri S. N. Ojha was allowed to join at Jealgora colliery as an extra hand in the Accounts Section since an Accounts Clerk was already working there who had been deputed earlier from Bhowra Area Office. In this connection he has further deposed that no written order to this effect was issued to Sri S. N. Ojha and he was only orally advised to join at Jealgora colliery as an extra hand and this oral advice was given to him sometime in the month of August, 1981, but thereafter also he did not join at Jealgora colliery, and thereafter in October, 1981 he issued the letter dated 22-10-81 (Ext. M-3) advising him in writing to report for duty to the Agent, Jealgora, without further delay. It is next his evidence that before issuing this letter he had also met Sri S. N. Ojha at Jealgora colliery at his house and had advised him to join at Jealgora colliery. This fact is also mentioned in the aforesaid letter dated 22-10-81 (Ext. M-3). Sri S. N. Ojha (WW-1) had also in his cross-examination at first admitted that in August, 1981 Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1), Personnel Manager, Bhowra Area, had met him at his residence, but he subsequently changed his statement by stating that Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) had met him at his residence not in August 1981 but in October, 1981. He has, however, admitted to have received the letter dated 22-10-81 of which Ext. M-3 is the Office copy in which, however, there is a clear mention about the verbal discussion which Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) had with Sri S. N. Ojha in August, 1981 and subsequently two weeks ago at the Jealgora colliery quarters of Sri S. N. Ojha. In that letter Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) had advised Sri S. N. Ojha once again to report for duty to the Agent, Jealgora colliery, without further delay, as it had been reported that he had not till then reported at Jealgora colliery. It is the evidence of the concerned workman, Sri S. N. Ojha (MW-1), that after the receipt of the aforesaid letter dated 22-10-81 (Ext. M-3) of Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) he had gone to Jealgora colliery and had submitted his joining report on 25th or 26th December, 1981, but thereafter he received the letter dated 30-10-81 (Ext. M-5) from the Agent of the colliery and thereupon he again submitted his joining report on 1-11-81 whereupon he was permitted to join with effect from 2-11-81. The said letter dated 30-10-81 (Ext. M-5) from the Agent, Jealgora colliery, states with reference to a joining report dated 24-10-81 of Sri S. N. Ojha, which had been received through post, that he had not physically reported himself for duty till date and hence his joining report dated 24-10-81 was being treated as meaningless and ineffective, and that his joining will be accepted only when he physically reported for duty. This falsifies the statement of Sri S. N. Ojha (WW-1) that he had gone to Jealgora colliery and had submitted his joining report on 25th or 26th of December, 1981. That subsequently Sri S. N. Ojha joined at Jealgora colliery with effect from 2-11-81 is not in dispute as that is the case of the management in its rejoinder to the written statement of the concerned workman and that is also the evidence of the concerned workman Sri S. N. Ojha (WW-1) in his cross-examination.

8. Since the concerned workman, Sri S. N. Ojha, admittedly joined as an Accounts Clerk at Jealgora colliery on 2-11-81, a day before the present reference dated 3-11-81, the question of refusing him employment by the management of Jealgora colliery with effect from 11-4-81, as posed in the order of reference, has not been raised or canvassed by the parties at the time of hearing. The only issue which has been raised and canvassed is the entitlement or otherwise of Sri S. N. Ojha to get his wages from 11-4-81, the date when he submitted his joining report at Jealgora colliery but was not allowed to join there, to 1-11-81, the day just preceding his joining at Jealgora on 2-11-81, the contention of the concerned workman, Sri S. N. Ojha, being that he is entitled to his full wages for the aforesaid entire period whereas the contention of the management being that he is not entitled to any wages for the said period as he himself was solely to be blamed for his absence during the said period.

9. [I have thus discussed above all the relevant evidence adduced by the parties and referred the issue raised and

canvassed by them at the time of hearing from which it would appear that by office order dated 8-12-80 (Ext. W-1) issued from the Head Quarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhawan, Dhanbad by the Senior Personnel Officer (Man Power), the concerned workman, Sri S. N. Ojha, Accounts Clerk, was transferred from the Development & Construction Division, Headquarters Office, Vikas Bhawan, Jharia to Jealgora colliery and he was directed to report to the Supdt. Jealgora colliery for further assignment of duty on being relieved by his controlling officer in the Development & Construction Division at Vikas Bhawan. It was, however, only after a lapse of about four months that by Office Order dated 10-4-1981 (Ext. W-2) he was relieved from the Development & Construction Division at Vikas Bhawan with effect from the date of the order whereupon he immediately on the very next date on 11-4-81 submitted his joining report of the same date (Ext. W-3) to the Agent, Jealgora colliery, but he was not allowed to join there and instead he was issued a letter dated 16-4-81 (Ext. W-4) by the Agent, Jealgora colliery asking him to report back to Development & Construction at Vikas Bhawan, Jharia as another Accounts Clerk from Bhowra Area, within which Jealgora colliery lies, had already been brought to Jealgora colliery and there was no requirement of another Accounts Clerk there. Sri S. N. Ojha, however, did not join back at Development & Construction Division at Vikas Bhawan, Jharia. In this connection it has been contended by Sri S. Bose, appearing for the concerned workman Sri S. N. Ojha, that since Office Order dated 8-12-80 (Ext. W-1) transferring Sri S. N. Ojha from Development & Construction Division Headquarters office, Vikas Bhawan, Jharia to Jealgora colliery had been issued by the Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. at Karmik Bhawan, Dhanbad, by the Senior Personnel Officer (Man Power), only the Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. at Karmik Bhawan, Dhanbad could have cancelled or modified that transfer order and the Agent, Jealgora colliery had no power to do so as he purported to have done by his letter dated 16-4-81 (Ext. W-4) by which he did not allow Sri S. N. Ojha to join at Jealgora colliery and instead asked him to report back to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan Jharia on the ground that there was no place for him at Jealgora colliery as in the meantime another Accounts Clerk had been arranged at Jealgora colliery from the Bhowra Area office. Sri S. Bose has referred in this connection to the evidence of the concerned workman Sri S. N. Ojha (MW-1) elicited in his cross-examination on behalf of the management that there are 12 Areas under M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and in every Area there is a separate General Manager of the Area and there are a number of contiguous collieries in each Area and Jealgora colliery is in Bhowra Area and when an employee is transferred from one Area to another Area the transfer order is issued by the Man Power Division at the Headquarters in Karmik Bhawan at Dhanbad but when an employee is transferred from one colliery to another colliery within the same Area the order of transfer is issued by the General Manager of that Area. Sri S. Bose has, therefore, contended that since the Development & Construction Division at Vikas Bhawan, Jharia is admittedly outside the Bhowra Area within which Jealgora colliery lies, the order dated 8-12-80 (Ext. W-1) transferring Sri S. N. Ojha from the Development & Construction Division Headquarters office, Vikas Bhawan, Jharia to Jealgora colliery was rightly issued by the Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Limited at Karmik Bhawan, Dhanbad by the Senior Personnel Officer (Man Power) but the order of the Agent, Jealgora colliery contained in his letter dated 16-4-81 (Ext. W-4) not allowing Sri S. N. Ojha to join at Jealgora colliery and directed him to report back to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan, Jharia, which amounted to his re-transfer from Jealgora colliery to the Development & Construction Division at Vikas Bhawan, Jharia, was without any authority as the Agent of Jealgora had no power to transfer an employee outside the Bhowra Area within which Jealgora colliery lies. Sri S. Bose has also submitted that there is no evidence on the record to show that after the transfer order dated 8-12-80 (Ext. W-1) of Sri S. N. Ojha from the Development & Construction Division at Vikas Bhawan, Jharia to Jealgora colliery issued by the Headquarters to M/s. Bharat Coking Coal Ltd. at Karmik Bhawan, Dhanbad, the Agent of Jealgora colliery had ever intimated to the Headquarters prior to the submission of the joining report dated 11-4-1981 by Sri S. N. Ojha at Jealgora colliery that another Accounts Clerk from Bhowra Area had been arranged and that Sri S. N. Ojha, Accounts Clerk was no longer required to be posted at Jealgora colliery. There is substance and force in the aforesaid arguments of Sri S. Bose which is upheld.

10. But there seems to be no plausible reason or explanation why Sri S. N. Ojha did not report for duty to the Area Finance Manager/Sr. Administrative Officer at Bhowra Area, as ordered in Office Order dated 14/16-7-81 (Ext. M-2) issued by the Personnel Manager, Bhowra Area, as the Personnel Manager, Bhowra Area had admittedly the authority and the power to transfer Sri S. N. Ojha from Jealgora colliery to Bhowra Area office as Jealgora colliery admittedly lies within Bhowra Area. The only explanation given by Sri S. N. Ojha for not doing so is that he did not receive a copy of the said Office Order, which I have already disbelieved above. Even after the matter was again reviewed on the President of the sponsoring union taking up the issue with the General Manager and Director (Personnel) at Headquarters at Dhanbad leading to the issue of the letter dated 22-10-81 (Ext. M-3) by Sri N. K. Prasad Sinha (MW-1) Personnel Manager of Bhowra Area, advising Sri S. N. Ojha to report for duty to the Agent, Jealgora without further delay in which there is also a mention about Sri N. K. Prasad Sinha having met him earlier in the month of August, 1981 and again two weeks prior to the date of the letter at his Jealgora quarter to persuade him in this connection, Sri S. N. Ojha, maintained and hesitant attitude, and he submitted his joining report dated 24-10-81 not by physically reporting himself at Jealgora office but by post which was rightly treated by the Agent, Jealgora colliery in his letter dated 30-10-81 (Ext. W-5) as meaningless and ineffective and in which Sri S. N. Ojha was informed that his joining would be accepted only when he physically reported for duty, and was only thereafter that he joined at Jealgora colliery with effect from 2-11-81. Therefore, there was no justification or plausible explanation for Sri S. N. Ojha for having remained absent from 16-7-81 which is the date of Office Order dated 14/16-7-81 (Ext. W-2) in which he was directed by the Personnel Manager, Bhowra Area office to report for duty to the Area Finance Manager/Sr. Administrative Officer, Bhowra Area with immediate effect which Sri S. N. Ojha did not comply till before 2-11-1981 on which date he actually joined at Jealgora colliery.

11. As already mentioned above since the concerned workman Sri S. N. Ojha admittedly joined as an Accounts Clerk at Jealgora colliery on 2-11-81, a day before the present reference dated 3-11-1981, the question of refusing him employment by the management of Jealgora colliery with effect from 11-4-1981, as posted in the order of reference, has not been raised or canvassed by the parties at the time of hearing, and the only issue which has been raised and canvassed is the entitlement or otherwise of Sri S. N. Ojha to get his wages from 11-4-81 to 1-11-81, both days inclusive. In the facts and circumstances of the case, as discussed above, Sri S. N. Ojha is held entitled to his full wages from 11-4-81 to 15-7-81 both days inclusive but is held not entitled to any wages from 16-7-81 to 1-11-81 both days inclusive and the management is directed to make payment to him accordingly. In the circumstance of the case there will be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.  
[No. L-20012(234)/81-D.III(A)]

New Delhi, the 9th August, 1983

**S.O. 3382.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Barora Area No. 1 of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) DHANBAD**

Reference No. 27 of 1982.

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

**PARTIES :** Employers in relation to the management of Barora Area No. 1 of Messrs Bharat Coking Coal

Limited, Post office Nawagarh, District Dhanbad and their workmen.

**APPEARANCES :**

On behalf of the employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.  
On behalf of the workmen : Shri D. Narsingh, Advocate.

**STATE :** Bihar

**INDUSTRY :** Coal.

**AWARD**

Dhanbad, 25th July, 1983

This is an industrial dispute under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012 (392)/81-D.III(A) dated 19th March, 1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

**SCHEDULE**

"Whether the demand of the workmen of Barora Area No. 1 of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Nawagarh, district Dhanbad that Shri B. N. Mondal, Office Superintendent, is entitled to Technical and Supervisory Grade 'A' scale from 1973 is justified? If so, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The concerned workman, Shri B. N. Mondal was working in Khas Sindih colliery before the take over of non Coking Coal Mines and was designated as office superintendent on a basic pay of Rs. 550/-. After nationalisation M/S Bharat Coking Coal Limited in 1973 became the owner of this mine and proper categorisation of workers of the colliery was made. The concerned workman was allowed the basic pay of Rs. 550 and he was allowed one increment of Rs. 15. According to the workman his basic pay then stood as Rs. 565 in 1973. The maximum clerical grade as laid down by the wage board recommendation was special clerical grade in the scale of Rs. 305-15-425-20-505. According to the concerned workman the private colliery owner in the course of his service considered his efficiency and raised him to a post above the clerical grade and designated him as office superintendent. The equivalent grade for office superintendent was technical and supervisory grade 'A' of the wage board recommendation. His case therefore is that M/S BCCL in 1973 actually gave him the basic pay in technical and supervisory grade 'A' fixing his pay at Rs. 565. This situation continued till the NCWA-I was introduced w.e.f 1-1-75. His pay then was fixed in clerical special grade of which the scale was Rs. 510-27-726-33-792. The concerned workman protested against his placement in the special grade (clerical) since 1-1-75 and always pressed the management to put him into the scale of technical and supervisory grade 'A' of the NCWA-I. Since he did not get any relief from the management this industrial dispute was raised resulting into this reference.

3. The case of the management, on the other hand, is that in spite of the designation of office superintendent as given by the private owner before take over and nationalisation, the concerned workman could not be above the clerical special grade, because this was the last grade in clerical cadre as provided in the wage board recommendation in 1967. For all practical purposes anything given to the concerned workman by the private owner above the maximum of special clerical grade i.e. Rs. 505 would be deemed to be special pay. According to the management there could not be any change made by the management of M/S BCCL, because his pay and other emoluments was protected under the Coal Mines Nationalisation Act. He was given an increment of Rs. 15 because there was a demand of the workers that one increment should be allowed while fixing the pay of the workman. The concerned workman was given an increment of Rs. 15 due to the demand of the workmen. According to the management, therefore, the proper categorisation of the concerned workman was in the special clerical grade and it could not be in technical and supervisory grade 'A'. The management's further case is that in 1977 the management of BCCL formulated a promotion policy and in that a post of office

superintendent was created in technical and supervisory grade 'A'. A seniority list was subsequently prepared in 1981 July in which the concerned workman has been placed under Sl. No. 56. It means that the concerned workman is junior in this list by 55 persons and he could not be provided technical and supervisory grade superseding all others above him.

4. Now let us analyse the evidence in this case. The management has examined MW-1 Shri S. P. Singh. He has been working in BCCL from the date of take over i.e., 17-10-1971. From 1961 he has been working in Barora Area as Dy. Personnel Manager and prior to that he was in Area No. III of M/S BCCL. The concerned workman was first appointed in 1954 in the Khas Sinidih colliery. MW-1 was working with the Custodian when he took over Khas Sinidih colliery on 31-1-73. He collected Man. Power list. His evidence is that in Khas Sinidih colliery the management did not implement wage board recommendations and wages were paid on ad-hoc basis to the workers. The wage board recommendation was implemented after the take over. He has said that there was no post of office superintendent in technical and supervisory grade 'A' in any of the private colliery and the BCCL created such a post for the first time in the year 1977. He has proved a circular, Ext. M1 to that effect. He knows the concerned workman and has said that his extra pay was fixed in the pay scale of clerical special grade and the pay that he was getting was protected. He has said that in Ext. M1 the duties of office superintendent in technical and supervisory grade 'A' are laid down. But the nature of job done by the workman concerned is simply clerical. He has said that the concerned workman is now in the area office. In his evidence MW-1 has admitted that besides the concerned workman there were clerks in other collieries holding the designation of office superintendent. But they were all placed in clerical special grade and none of them has been placed in technical and supervisory grade 'A'. In his cross-examination he has said that Ext. M2 the seniority list was published on 4-7-81 but he has no idea whether the concerned workman was intimated his seniority in that list. He has also said that in the case of the concerned workman an increment of Rs. 15 was given as per direction of the Area General Manager because he was already above the pay scale of clerical special. He has further admitted that the designation of the concerned workman after take over and even after nationalisation was never disturbed and his designation still stands as office superintendent.

5. WW-1 is the concerned workman. He has proved certain documents which are Exts. W.1, W.2, W.3, W.4, W.5 and W.6. In the documents Exts. W.1 to W.4 the concerned workman has always been designated as office superintendent.

6. Now let us consider the position as emerged from the aforesaid evidence. MW-1 has admitted that the private colliery owner used to have office superintendent inspite of the fact that there was no grade of office superintendent as given in the wage board recommendation. This appears to be the thinking of M/S BCCL which owned the mines after nationalisation. The contention raised on behalf of the workmen is that in 1977 the management of M/S BCCL came out with the promotion policy, a copy of which is on the record of this case and marked Ext. M1. A post of office superintendent was for the first time created by M/S BCCL. It means that the need which M/S BCCL felt in 1977 was already felt by the private owners and they created a post of office superintendent to supervise and control their business.

The private owner did not pay them in the clerical grade and put them in a higher grade. The higher grade is technical and supervisory grade 'A' and it appears that the concerned workman as office superintendent was placed in technical and supervisory grade 'A' of the wage board recommendation. MW-1 has said that the private owners did not implement the wage board recommendation and had simply ad-hoc arrangement. The question is whether by allowing the concerned workman to retain his pay as given by the private owner, the management of M/S BCCL actually considered

the pay above Rs. 505 as personal pay. The conciliation officer in his report doubted this plea of the management because the personal pay could not go beyond Rs. 45. Moreover, an increment was given to the concerned workman to raise his pay from Rs. 550 to Rs. 565. No office order with regard to the fixation of pay of the concerned workman at the time of re-categorisation was issued by the management of M/S BCCL. According to the concerned workman it was not even disclosed to him that he was placed in the clerical special grade. In fact all the documents filed on behalf of the workman shows that the management of M/S BCCL always gave him to understand that he was on the post of office superintendent. MW-1, of course, has said that the concerned workman was not performing the duties of office superintendent as detailed in the circular, Ext. M1. But it has not been shown as to what job the concerned workman was doing. In fact the documents of BCCL filed by the concerned workman which are Exts. W.1 to W.4 would go to show that the management always treated him to be office superintendent which can simply mean that he has supervisory duty over other clerks who are working below him. Considering all these, I have no doubt in my mind that in 1973 the management did not come out with a clear decision that the concerned workman was in special clerical grade instead of technical and supervisory grade 'A'. The question for the first time arose when NCWA-I came into effect from 1-1-75. Since the management was not prepared to give him technical and supervisory grade 'A' he was for the first time placed in clerical special grade. This does not appear to be justified. The management has said that there was no post of office superintendent in the collieries of M/S BCCL and for the first time it was introduced in 1977 by virtue of Ext. M1. This is no doubt true. But is it going to affect the case of the concerned workman? He is not claiming any promotion on the ground that right from the time of the private owners, the concerned workman has been in technical and supervisory grade 'A' and not in any of the clerical grades as provided in the wage board recommendation. In this situation the management of M/S BCCL could not place him in special clerical grade which would be simply a case of demotion. I am afraid the management of M/S BCCL cannot be permitted to do so. I accordingly hold that the concerned workman has been in technical and supervisory grade 'A' at the time of take over and he continues to be in that grade since he has not got the benefits of technical and supervisory grade 'A' when NCWA-I was introduced and not even under NCWA-II, he is entitled to the benefits as given in these two agreements.

7. Thus having considered all aspects of the case this reference is answered as below :—

The demand of the workmen of Barora Area No. 1 of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Nawagarh, District Dhanbad that Shri B. N. Mondal, office superintendent is entitled to Technical and Supervisory Grade 'A' scale from 1973 is justified. Consequently, he is entitled to the difference in wages and other emoluments arising out of NCWA-I and NCWA-II.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer

[No. L-20012(392)/81-D.III(A)]

**S.O. 3383.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Katras Area No. IV of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Katrasgarh, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD.

Reference No. 30 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d)  
of the I.D. Act, 1947.

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Katras Area  
No. IV of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post  
Office Katrasgarh, Dist. Dhanbad and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri J. D. Lal, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

## AWARD

This is a reference under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012(377)/81-D. III(A) dated 21-3-1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

## THE SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Katras Area No. IV of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Katrasgarh, district Dhanbad, that Shri Shankar Singh should be regularised in Supervisory Grade-A with effect from 1976 is justified? If so, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The concerned workman, Shri Shankar Singh is in clerical grade II of the wage board recommendation and he is at present attached to the office of the Administrative officer of Katras Area No. IV of M/s Bharat Coking Coal Limited. His case is that since July, 1976 he has been entrusted with the following jobs :

- (1) Maintenance of Impressed Fund and Accounts.
- (2) Procurement of printing/stationery materials.
- (3) Supervision, maintenance and Upkeep of the area office vis-a-vis supervision of sweepers and garden staffs.
- (4) Entertainment of office guests and also participants in conference meetings, etc.
- (5) Canteen supervision.

According to him the jobs which have been entrusted to him are of higher responsibility for which he should be allowed supervisory Grade-A i.e. Rs. 722-1278. Shri Singh represented his case before the competent authorities several times but his request was not considered. Consequently, he approached his union, but even then the management turned down the request of the union. His union therefore raised this dispute before the Assistant Labour Commissioner(C) Dhanbad. There was a protracted conciliation which ultimately ended in failure and this reference was made to this Tribunal for adjudication. The prayer of the concerned workman is that he should be regularised in supervisory Grade A w.e.f. July, 1976.

3. The management in their written statement have denied the case of the concerned workman as he was doing duties of supervisory grade-A so as to entitle him to be regularised in that grade. It has been pointed out that the principle duties of the concerned workman were to procure stationery and to prepare bills for the same, and so as a bill clerk he has been correctly placed in grade II. It has further been contended that on the very case of the concerned workman that he was doing supervisory duties, his case cannot be considered because he is outside the scope of workman.

With regard to the admissibility of supervisory grade-A to the clerical staff it has been pointed out that for the first time M/s. Bharat Coking Coal Ltd. brought out a cadre scheme under circular dated 20-6-77 under which promotion of a clerical staff could be given to technical and supervisory grade-A. The management therefore has contended that there is no question of any clerical staff getting supervisory grade-A prior to 20-6-77 as claimed by the concerned workman.

4. We will first take up the question as to whether this reference is not maintainable on account of the fact that the concerned workman has claimed supervisory grade-A on the basis of his contention that he has been doing supervisory work. The concerned workman is in clerical grade II and he is a workman competent to claim higher wages in his capacity as grade II clerk. Consequently, the promotion policy and the cadre scheme drawn up by the management entitles a clerical staff to be given supervisory grade. It means that besides doing clerical duties he is also entrusted with supervisory duty. For these two reasons it cannot be said that the concerned workman by virtue of his doing some supervisory duty, he is outside the category of workman. In support of this view, SCLJ, Vol. 8 Page 367 may be referred to. In this case Blending Supervisor were held to be workmen though they were designated as supervisors. Moreover, SCLJ, Vol. 7 Page 447 may also be referred to. Their Lordships held that the designation of a person is not significant to determine whether he is a workman or not. What is material is to find out the nature of duties. In the reported case the designation was of a manager, but he was allotted works. Their Lordships held that the concerned workman was a workman and not a supervisor. I therefore hold that the concerned workman whose primary business are clerical and other duties incidentally supervisory comes within the category of workman and so he is competent to claim relief under Industrial Disputes Act.

5. Before I go to discuss the evidence adduced in this case, I would like to point out that under the wage board recommendation only 4 grades of clerical cadre had been laid down. These are : (1) Grade III clerical, (2) Grade II clerical, (3) Grade I clerical, (4) Clerical special grade. In July, 1967 M/s. Bharat Coking Coal Limited introduced supervisor grade. A to this cadre and laid down specific duties to be performed by such clerks. The duties may be enumerated below :

He shall possess very high degree of trustworthiness and sense of responsibility and shall be in charge of section. He will exercise supervision control over the staff put under section and should be thoroughly conversant with the jobs being done by subordinates.

(ii) He shall ensure expeditious disposal of all papers/documents under the control of the officer concerned.

(iii) He shall also supervise the work of staff attached to the section.

(iv) He shall ensure the submission of returns/reports to headquarters, Ministry and other authorities in time independently.

(v) He shall be capable of independently compiling, analysing and projecting various reports, returns data received or generated from his Section.

(vi) He shall be able to supervise the payments of civil works, establishments bills and their proper accounting as per accounts procedure, shall be conversant with establishment rules in respect of employees claims.

(vii) He shall be fully conversant with purchase procedures and sales accounting and be able to ensure its proper adherence.

(viii) The post which could be covered in this grade shall be Sr. PA, Office superintendent, Accountant, Sr. Stores supervisor, Legal Assistant etc.



6. The main case of the concerned workman is that the duties assigned to him since July, 1976 are of supervisory grade-A and on the basis of his duties he should have been given supervisory grade-A. In this connection I intend to bring out the worth changes that have come out within a decade of the wage board recommendation. There have been two Nationalisation Acts with regard to the coal industry and under the centralised control of Coal India Ltd. we have organisations such as Bharat Coking Coal Ltd., Central Coalfields Ltd., Eastern Coalfields Ltd. etc. which are managing the coal industry in the different areas. M/s. Bharat Coking Coal Ltd. have their head office and also a number of area offices besides managements at colliery level. This centralised control has made the organisation very vast and naturally the administration is very complex. Before nationalisation the collieries used to be managed by private owners with the minimum number of staff and officers as laid down in the Mines Act. But after nationalisation complexities of administration and control have grown up as a result of centralised administration. For our purpose in this case the concerned workman has been allotted to the office of administrative officer of the area. Now this Administrative Officer has his duties which are also multifarious. The clerks attached to his office have to assist him in every way in discharging of his duties. He has to maintain accounts and this function in his office has to be made by the concerned workman. This is admitted by MW-1, Shri S.B. Sinha who is Senior Administrative Officer in Katras Area since 1980. He has admitted in his evidence that as Administrative Officer he has to perform multifarious duties connected with the administration. He has to look after canteens, stores, gardens, motor vehicles, purchase of materials and a lot of other administrative affairs. He has said that his clerk carries on the clerical duties relating to all these matters. He has made it clear that the concerned workman in his capacity as clerk carries on all the duties in connection with his administrative works. In his cross-examination he has said that the concerned workman is a Graduate. He maintains Impressed Fund and Account, procurement of printing and other stationery materials, arrangement of entertainment of guests and participants in conferences and meetings. Now such duties as admitted by MW-1, Administrative Officer did not actually come within the duties prescribed under the wage board recommendation for any of the clerical duties enumerated in the wage board recommendation. I need not quote the wage board recommendation in this connection because this is an admitted position. It means that the concerned workman is performing the duties which are not normally under the wage board recommendation, but without such duties being assigned to the clerical cadre, the work of the office of the Administrative Officer cannot go on. It is clear that the management of M/s. BCCI is taking from the clerical cadre such duties which are not ordinarily within the sphere of the work of clerical cadre. What I mean to say is that under the changed set up of administration after nationalisation new types of work have emerged, and so far as administrative officer is concerned, he has to be provided with an assistant who could not only look after the office duties but also perform some other duties connected with the normal work of administrative office. It is here that we should consider the evidence which has been produced on behalf of the workman.

7. We have Ext. W. 1 which is an office order of Katras Area office dated 23-11-79. It has been signed by the Administrative Officer, Katras Area. It says that Shri Shankar Singh shall continue to maintain Impressed cash and its proper accounts, to supervise garden works, sanitary supervision, procurement of printing and stationery materials, arrangement of entertainment of guests, canteen supervision and stationery and stores supervision etc. as usual. This document shows that although it is dated 23-11-79 the duties prescribed therein were being performed by Shri Shankar Singh the concerned workman from before.

8. Ext. W. 2 is an office order signed by Katras Area Manager dated 12-9-80. Under this order all drivers before moving unattached vehicles should report to the administrative section viz. Shri K. P. Singh or Shri Shankar Singh. So the concerned workman was also to see that the vehicles were not taken out by the drivers without his permission.

9. The other documents Ext. W. 3 has been signed by the Assistant Survey Officer and addressed to Shri Shankar Singh the concerned workman for supply of ammonia printing paper, liquid ammonia and tracing paper and sketch pen ink.

10. Ext. W. 4 is a document signed by the Assistant Commandant, Katras Area addressed to the Senior Administrative Officer of that area. He has demanded Rs. 350 for purchase of 5 tons of fleet from the market. The Administrative Officer ordered Shri Shankar Singh, the concerned workman to make out an advance of Rs. 300. Ext. W. 5 is a voucher signed by the concerned workman. It is in respect of an amount of Rs. 21.80. Ext. W. 6 is a promotion policy which we have already dealt with. It has been filed only to show that in this promotion the supervisory grade-A was made available for the clerical cadre. Ext. W. 7 is addressed to the concerned workman signed by the Administrative officer. The concerned workman was directed to do certain duties because the Administrative Officer for some reason was not coming to office.

11. Ext. W. 8 is dated 28-11-80. In this letter the designation of Shri Shankar Singh is shown to the supervisor. He was directed by the General Manager to take delivery of a consignment from M/s. Associated Traders & Engineers Ltd. Ext. W. 9 is a direction from the Administrative Officer to Shri Shankar Singh to pay cash for 30 litres of petrol for a Fiat car. Ext. W. 10 is signed by the Dy. C. M. E. and a copy has been made over to Shri Shankar Singh, store supervisor of Katras Area.

12. It will appear from Ext. W. 8 and W. 10 that the concerned workman has been designated as supervisor. We have already pointed out that the concerned workman is doing account works as admitted MW. 1. We have seen from Ext. W. 1 that he has been looking after canteen sanitation, garden and other works. He has been attending to the guests and he has been also arranging for refreshment to the participants in the meetings. He has been also looking after canteens. So all these documents thoroughly go to support the case of the concerned workman that ever since he has been posted under the Administrative Officer, he has been doing not only clerical work but also such works which are outside the sphere of clerical duties and those works are mostly supervisory. The case of the concerned workman is that he has been doing such duties since July, 1976. This is a basis for his claiming to be placed in supervisory grade-A. What he has prayed is that he should be regularised in this grade. The management has contended that this supervisory grade can never be given to the concerned workman because such a grade was permissible to the clerical cadre since July, 1977. It is no doubt true that if the status of the supervisor grade-A was not open to the clerical cadre. The management has also contended that the concerned workman was promoted from clerical grade III to clerical grade II in the year 1979 and that he was in clerical grade III in July, 1976 or even in July, 1977 when the supervisory grade-A was made available to the clerical cadre. For these reasons it has been urged that the concerned workman could not be regularised in supervisory grade-A even from July, 1977. It is to doubt true that if the status of the concerned workman in the clerical cadre is considered, he will be too junior to be placed in supervisory grade-A. Already a seniority list, Ext. M. 1 has been filed by the management to show that the concerned workman is far below in the list being Sl. No. 139 in the list. This list has been prepared area-wise. But the case of the concerned workman is based on a separate footing altogether. He is a Graduate and possesses much more qualification than the minimum qualification required for entering the clerical cadre. He has also shown his efficiency while working under the Administrative Officer and there appears no complaint against his work. The concerned workman has said that he was not claiming for promotion to the post of supervisory grade-A because his demand is merely for regularisation in supervisory grade-A. It is no doubt true that he has been working with the Administrative Officer since July, 1976 and has put in a quite a number of years in that office performing the same duties. For supervisory work done by him, there is no doubt that he is entitled to the wages of supervisory grade-A because every workman has to be paid according to the work done by him. The only question is whether

he should be regularised. This has to depend upon the length of service put in by him in such a job. It has not been controverted that since July, 1976 the concerned workman has been working with the Sr. Administrative Officer of Katras Area. This shows that for about 7 years, he has been working under the Sr. Administrative Officer in this area and performing not only clerical but multifarious supervisory duties. It is clear that for having worked for a long time in that capacity his service has to be regularised in that particular job. I, therefore, hold that the concerned workman is entitled to be regularised in supervisory grade-A from July, 1977 instead of July, 1976.

13. The demand of the workmen of Katras Area No. IV of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Katrasgarh, Dist. Dhanbad that Shri Shankar Singh should be regularised in supervisory grade-A is justified. As stated above, Shri Shankar Singh should be regularised in supervisory grade-A with effect from July, 1977 instead of from July, 1976. He will also be entitled to all the back wages and other emoluments in supervisory grade-A from July, 1977.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer  
[No. L-20012(377)/81-D. III (A)]

S.O. 1384—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Lodna Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, in Area No. X, Post Office Jeenagera, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, (No. 2) DHANBAD.

Reference No. 55 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947.

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Lodna colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, in Area No. X, Post office Jeenagera, District Dhanbad and their workmen.

#### APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri B. Joshi, Advocate.  
On behalf of the workmen.—Shri S. Bose, Secretary, Rastriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 25th July, 1983

#### AWARD

This is an industrial dispute under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012 (48)/82-D. III(A) dated 29th May, 1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

#### SCHEDULE

"Whether the action of the management of Lodna colliery of Area No. X of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Jeenagera, District Dhanbad in refusing employment to Shrimati Ashwa, Wagon Loader with effect, from December, 1980 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The concerned workman Shrimati Ashwa happened to be a permanent wagon loader of Lodna colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited. Although she was working in that colliery from before, she was regularised by the management of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. from 24-7-74. She also became a member of Coal Mines Provident Fund in the year 1974. She performed her duty till 1-9-76 and she became suddenly indisposed. She was taken to the nearest medical unit at South Tisra hospital where she received her treatment. Since then she remained ill and was unable to move out till the 1st December, 1980. The medical officer of South Tisra colliery hospital declared the concerned workman fit for out-door work and granted a certificate to that effect on 6-12-80. The concerned workman reported for duty on 7-12-80 and produced the medical certificate. She was asked to come again and accordingly she reported for duty on 10-12-80 when she was told that the matter was under investigation and she will be informed in due course. The local union of the concerned workman took up the matter with the management and in course of discussions it was disclosed that the medical certificate granted to her was wrong and the claim of the workman to resume duty was not acceptable. No charge-sheet was issued and she did not receive any notice of termination of her service. An industrial dispute was raised on the ground that the action of the management in not allowing her to resume duty was illegal and unjustified. The conciliation ended in failure and hence this reference for adjudication was made.

The management accepted the facts as put forth on behalf of the workman, but it was contended that the medical certificate was false as the hospital record did not show that she received treatment there. The management, due to long absence of the workman, considered this matter to be a case of abandonment of service. It was admitted that no chargesheet was submitted nor any order for termination of service was issued by the management.

4. No oral evidence was adduced but certain documents filed on behalf of the management were marked on admission. Ext. M 1 is a letter dated 12-5-80 written by the Agent, Lodna colliery to the Personnel Manager, Lodna Area. There is a note, Ext. M 2 showing that the concerned workman had absented for more than 10 days. The Personnel Manager advised chargesheet against the concerned workman for her continued absence. No charge-sheet was submitted as is stated above. Ext. M 3 is an application by the concerned workman addressed to the Agent, Lodna colliery. Ext. M 4 is a note thereon. Ext. M 5 is a medical certificate granted by the Medical Superintendent, Regional Hospital, Tisra. It has been stated in this certificate that Shrimati Ashwa had been a case of chronic Public Inflammation and was under treatment from 9-2-76 to 6-12-80. She was found to be fit for duty from 8-12-80. Ext. M 6 is another note by the Medical Superintendent dated 22-2-80. On verification of the hospital records the concerned reference was not found. The concerned certificate was perhaps issued in haste without any immediate verification.

5. Shri S. Bose appearing on behalf of the workman has argued that even if the medical certificate justifying the absence of the concerned workman from duty be ignored in view of the subsequent note, Ext. M 6, the case of the workman has to stand when her service has not been terminated according to law and therefore the management was wrong in not permitting her to join duty. He has admitted that her long absence gave cause for the management to frame a charge-sheet and after domestic enquiry to order her dismissal or termination of service. But she being a permanent employee could not be refused permission to join her duty in absence of any order as dismissing her or terminating her service. This was not even a case of retrenchment because the procedure for retrenchment as laid down under S. 25F of the I. D. Act, 1947 has not been followed by the management. Shri B. Joshi, Advocate appearing on behalf of the management simply argued that the concerned workman is certainly not entitled to back wages due to prolonged absence of four years without proper justification. He has drawn my attention to the fact

that wagon loaders are piece rated workman and they are not entitled to wages if they do not appear for work. Shri Bose has conceded to this aspect of the case and has said that the workman will not claim any back wages, but the continuity of service should not be disturbed.

6. In view of the above discussions this reference is answered as below :

The action of the management of Lodna Colliery of Area No. X of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Jeenagora, District Dhanbad in refusing employment to Shrinati Ashwa, wagon loader with effect from December, 1980 is not justified. She is, therefore, entitled to join her duty within 15 days of the publication of this award. She will not be entitled to any back wages but there will be no break in the continuity of her service and other service conditions will not be disturbed. The concerned workman will be entitled to payment of wages after 15 days of the publication of this award if the management in spite of her joining duties will not permit her to do her normal duties.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer,

[No. L-20012(48)/82-D. III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 10th August, 1983

**S.O. 3385.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of West Bokaro Colliery of M/s. TISCO Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2) DHANBAD**

Reference No. 26 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of West Bokaro Colliery of M/s. TISCO Ltd. and their workmen.

**APPEARANCES :**

On behalf of the employers.—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri B. Joshi, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 27th July, 1983

**AWARD**

This is an industrial dispute under S. 10 of the I. D. Act, 1947. The Central Government by its Order No. L-24012/(20)/81-D-IV(B) dated 23rd March, 1982 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :—

**SCHEDULE**

"Whether the action of the management of West Bokaro Colliery of M/s. TISCO Ltd. in dismissing S/Shri B. N. Roy, Ex-excavator Operator, Ram Prakash Singh, Ex-Dumper Operator and Lal Saheeb Singh, Ex-General Mazdoor with effect from 23-3-81 is justified and legal? If not, to what relief the said workmen are entitled?"

2. In this reference three workmen are involved and they were all dismissed after a domestic enquiry was held against them. They were found guilty of violation of Regulation 39(a) of Coal Mines Regulation, 1957.

3. Both the parties were represented and written statement were filed and also rejoinders. One of the concerned workman Shri B. N. Roy is an excavator operator, another concerned workman Shri Ram Prakash Singh is a Dump-operator. The 3rd concerned workman Shri Lal Saheeb Singh is a general mazdoor working as Trip man. The charge against Shri B. N. Roy is that he allowed the excavator at 10 face to be used by Shri Ram Prakash Singh. Similarly Shri Ram Prakash Singh allowed his own dumper to be operated by Shri Lal Saheeb Singh. This was against Regulation 39 of the Coal Mines Regulation 1957, Shri Lal Saheeb Singh was not competent to operate a dumper. He had therefore offended the Coal Mines Regulation, 1957. After departmental enquiry it was found that the charges were proved and the management dismissed them. An industrial dispute was raised resulting into this reference.

4. On a prayer made by the management, preliminary hearing was given on the point as to whether the domestic enquiry was fair and proper. The management examined, MW-1 Shri P. K. Gandhi who happened to be the enquiry officer. All the documents relating to the enquiry were produced by the management and they were marked Exts M-1 to M-32 with the consent of the parties. MW-1 was cross-examined on behalf of the workmen. No witness was examined on behalf of the workman and both the parties were heard on the preliminary point. By a separate order it was found that the enquiry was fair and proper and the parties were given opportunity to be heard on the question of merit. At that stage MW-2, Shri Ram Singh, Manager of West Bokaro Colliery was examined. He has said that he issued authorisation to Shri B. N. Roy and Shri Ram Prakash Singh to work on excavator operator and dumper operator respectively. These authorisations have been marked Ext. M-31 and M-32. These are counter-foils and the evidence of MW-2 is that the other half of the authorisation had been handed over to S/Shri B. N. Roy and Ram Prakash Singh.

5. At the time of argument on the question of merit it was pointed out by Shri S. S. Mukherjee, Advocate for the management that with regard to two of the concerned workman viz., S/Shri Ram Prakash Singh and Lal Saheeb Singh the management has entered into a settlement and the settlement would be soon filed. In fact a settlement has been filed. We need not therefore discuss the case against these two workmen because there is to be an award concerning them on the basis of the settlement amicably arrived at between the parties.

6. We are only left to consider the case of dismissal in respect of Shri B. N. Roy, excavator operator. The fact is very simple. Shri B. N. Roy was on duty on 26-2-81 in the second shift i.e. from 5 P.M. to 1 A.M. of 27-2-81. Thereafter he had to work 4 hours overtime i.e. from 1 A.M. to 5 A.M. His duty was for operating excavator No. 10 at quarry B. It so happened that during this overtime period one Ouyumuddin who was also on duty during the O.T. met with an accident against dumper and died. A police case was instituted and there was a lot of official investigation. A dumper operator named Ramprakash Singh was charged by the management for having crashed this Ouyumuddin under the wheels of the dumper. Shri P. K. Gandhi, MW-1 held the departmental enquiry on the charges against Shri Ramprakash Singh. He found him guilty and the management dismissed him also. For some reasons he was reinstated by the management in his own job. In the course of enquiry against Shri Ramprakash Singh it transpired that excavator No. 10 was being operated by Shri Ram Prakash Singh without any authority. The dumper of Shri Ramprakash Singh was being driven by Shri Lal Saheeb Singh. Shri B. N. Roy, at that time was sitting in a dumper which was lying in that face of the colliery. On the basis of the evidence collected in the domestic enquiry against Shri Ramprakash Singh for having caused the accident and the death of Ouyumuddin, these three concerned workmen were charge-sheeted for having violated Regulation 39(a) and after they were found guilty they were dismissed. It is apparent that these concerned workmen had nothing to do with the accident and with the death of



Quyumuddin. But the management was on alter on account of the fact that due to certain malpractices such an accident took place. I have to say this because in the cross-examination of the witnesses it has transpired that the Regulations are not actually followed by these heavy vehicle drivers. It has also come out that for a pretty long time these heavy vehicle drivers are asked to perform 4 hours O.T. after second shift. The result is that from 5 P.M. to 5 A.M. these heavy vehicle drivers are put to 12 hours duty during night time. It is likely that under these circumstances some work is done due to some private arrangements among these drivers which are against the Regulation, but nevertheless allowed them sometime to have some rest. In this case Shri B. Joshi, Advocate for the workman has conceded that under Regulation 36 Shri B. N. Roy and Shri Ram Prakash Singh were given authorisations. He, however, denies that Shri B. N. Roy had entrusted excavator No. 10 to Shri Ram Prakash Singh to operate the same. But in this case the witness Shri Ramprovesh Singh has said that Shri Ram Prakash Singh was plying the excavator operator and he did three trips on his dumper when Shri Ram Prakash Singh was driving the excavator. Then again witness No. 2 for the management Shri Sideswar has said that Shri B. N. Roy was in his dumper and his excavator No. 10 was being plied by Shri Ram Prakash Singh. Witness No. 3 Shri Dwarka Prasad has also said that Shri Ram Prakash Singh loaded a few dumpers from excavator No. 10 and thereafter Shri B. N. Roy came and took over the operation on the shovel Shri Ramprovesh Singh then got down and went to his own dumper and operated the same.

7. Now witness No. 1 and witness No. 2 and witness No. 3 for the management have admitted that they did not report this fact to anyone. Witness No. 1 Shri Ramprovesh Singh has said in his evidence that in the query he has seen that every operator operates whatever machine he wants to operate. He has also seen haulage and grader are operated even by helpers and mechanics, and the officers have also seen them doing this and have not objected. MW-2 has said in his cross-examination that the overman was present and saw that Shri Ramprovesh Singh was operating the shovel but he did not report. From the evidence of these witnesses in cross-examination it appears that to the knowledge of the supervisory staff such machines like excavators and dumpers are used by even such persons who have not been authorised by the manager of the colliery to operate them. A practice appears to have grown up about it for the convenience of work. The position is that Shri B. N. Roy was authorised to operate the excavator and Shri Ram Prakash Singh was authorised to operate the dumper. So both of them are authorised persons without any doubt and both have got licence for operating heavy duty machines. The fault complained against both of them is that they have violated the Regulation 39(a). This is therefore a technical offence and the first of its kind noticed by the management in the context of an accident happening. Shri Ramprovesh Singh was charged for having caused the accident from his dumper and he was dismissed also but reinstated. The other two concerned workmen in this case viz. S/Shri Ram Prakash Singh and Lal Saheeb Singh have also been reinstated by virtue of a settlement arrived in this case. All the three concerned workmen who have been dismissed for the same technical offence of violation of Regulation 39(a) of the Coal Mines Regulation, 1957. I see no reason why the concerned workman Shri B. N. Roy should lose his job. The evidence indicates that inspite of his duty from 1 A.M. on 27-2-81 he came to his duty at 1.30 A.M. It appears that during his absence excavator No. 10 was being operated by Shri Ram Prakash Singh. There is no complaint that by the action of Shri Ram Prakash Singh there was an accident. In fact Shri Ramprovesh Singh was charged for the accident. Shri Ramprovesh Singh in his evidence has said that his dumper's brake was faulty and had started rolling down. It may be that this caused the accident. Shri B. N. Roy has said that he was operating excavator No. 11 and from there he came to excavator No. 10 and started operating the same at 1.30 A.M. There is nothing to indicate as to whether he was on duty at excavator No. 11. In any case the offence being of a technical nature in the background that the Regulation has not been followed properly by the operators within the knowledge of superior officers, a dismissal for this technical fault cannot be said to be justified. Since it was the first offence brought to the notice of the higher management in course of a

domestic proceeding against Shri Ramprovesh Singh relating to an accident, the concerned workman Shri B. N. Roy should have been at best warned so that he could not commit such mistake in the future. At any rate a lighter punishment was indicated even if it was accepted that he committed a breach of the Regulation.

8. Thus having considered all aspects of the case this reference is answered as below :

(1) The action of the management of West Bokaro Colliery of Messrs TISCO Ltd. in dismissing Shri B. N. Roy, Ex-excavator operator w.e.f. 23-3-81 is not justified. He therefore should be reinstated in his job with effect from the date of his dismissal i.e. 23-3-81 and will be entitled to all the back wages and other emoluments w.e.f. 23-3-81.

(2) With regard to Shri Ram Prakash Singh, Ex-Dumper Operator and Shri Lal Saheeb Singh, Ex-General Mazdoor there has been a settlement between them and the management. This settlement being fair and proper to these workmen, is accepted and will form part of this award. They will be entitled to the relief of reinstatement and continuity of service as embodied in this settlement.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer  
[No. L-24012(20)/81-D.IV(B)]

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, DHANBAD

Reference 26 of 1982

Employers in relation to the Management of West Bokaro Collieries of M/s. TISCO Ltd.

AND

Their Workmen.

The parties above named beg to submit as follows :

That out of the three concerned workmen, the dispute has been amicably settled in relation to two of the workmen, namely Shri Ram Prakash Singh, Ex. Dumper Operator, Ex. P. No. 3852 and Shri Lal Saheeb Singh, Ex. General Mazdoor, Ex. P. No. 4806, without prejudice to the respective written statement of the parties on the following terms :

1. That Shri Ram Prakash Singh and Shri Lal Saheeb Singh will be reinstated in their respective original job and will be permitted to resume their duties with effect from the dates they report for duties.
2. That the above reinstatement will not affect their continuity of service.
3. That period from the date of their dismissal, till they join their duties, will be treated as if the concerned workmen were leave without pay.
4. That they will not be entitled to any back wages or the usual annual increment, falling due from the date of their dismissal, till they are reinstated in the service.
5. That the parties will bear their own respective costs of this proceedings.

That the terms of settlement are fair and proper.

It is, therefore, humbly prayed that the settlement may kindly be accepted, and an award passed in terms thereof regarding the above two workmen namely Shri Ram Prakash Singh and Shri Lal Saheeb Singh.

Workman

Sd/- illegible

Sd/- illegible

For and on behalf of the Employer

Sd/- illegible

Divisional Manager (West Broker)

Dated : 20-7-1983.

**S.O. 3386.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of New Kenda Colliery of Eastern Coalfields Limited, Post Office Kenda, District Burdwan and their workmen, which was received by the Central Government on the 4th August, 1983.

**CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
CALCUTTA**

Reference No. 58 of 1982

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of New Kenda Colliery of Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

**APPEARANCES :**

On behalf of Employers—Mr. B. W. Chatterjee, Personnel Manager, with Mr. I. P. Singh, Deputy Personnel Manager, and Mr. P. L. Ojha, Senior Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Mr. A. K. Gupta, President of the Union.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Coal

**AWARD**

By Order No. L-19011(3)/81D.IV(B) dated 31st October 1981 read with order No. L-19012(54)/80-D.IV(B) dated 6th November 1982 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the demand of the workmen for departmentalisation of contract labour of New Kendra Colliery under Kenda Colliery of Eastern Coalfields Ltd., number 65 as per Annexure-A is justified ? If so to what relief are the workmen entitled ?

**ANNEXURE A**

1. Bijoy Singh
2. Indar Gope
3. Surajdayal Gope
4. Jiton Gore
5. Rajkishore Gore
6. Kamal Jadav
7. Siddique Mia
8. Ramchandar Shaw
9. Mustafa Khan
10. Omprakash Singh
11. Tulshi Jadav
12. Beni Shaw
13. Anadi Jadav
14. Yakub Ansari
15. Taleswar Jadav
16. Dasarath Shaw
17. Lachman Gore
18. Baleswar Jadav
19. Omprakash Thakur

20. Sisir Banerjee
21. Mahagoo Mallah
22. Jagarnath Harijan
23. Md. Naimuddin Ansari
24. Rakhohari
25. Fago Jadav
26. Nimai Chand Dey
27. Jagdish Paswan
28. Banka Jadav
29. Rameswar Jadav
30. Bankan Jadav
31. Ramakant Jadav
32. Bedashi Jadav
33. Mahendar Sharma
34. Jalram Mahato
35. Ramnarayan Jadav
36. Mahendar Ram
37. Bishu Bouri
38. Baljnath Jadav
39. Bhaneswar Turi
40. Hari Jadav
41. Sanichar Jadav
42. Banwari Harijan
43. Sarju Paswan
44. Chandrika Mondal
45. Mohan Majhi
46. Sk. Sorab
47. Sk. Jamal
48. D. Krishna
49. Monoranjan Gope
50. S. K. Jantti
51. Md. Hanif
52. Chattamen Gope
53. Thaku Dayal Shaw
54. Kailash Ram
55. Naimuddin Ansari
56. Ramchandar Shaw
57. Rabi Sarkar
58. Bijoy Singh
59. Ramkripal Harijan
60. Mahendar Sharma
61. Ramser Mandal
62. Bedashi Jadav
63. Sabadeo Shaw
64. Biswanath Bouri
65. Ramasis Paswan.”

2. On a perusal of the terms of the reference it is quite clear that the demand of the workmen in reality is for abolition of the contract labour. The colliery management has raised the following preliminary objections :

- (i) that after the enforcement of the Contract Labour (Regularisation and Abolition) Act, 1970 (briefly, the Act) no dispute relating to abolition of contract labour can be legally referred to an Industrial Court under the provisions of the said special Act and such dispute can only be resolved in accordance with the provisions of the Act and hence the present reference is barred under the provisions of the said Act and it is incompetent ;
- (ii) that the matter of dispute is not an industrial dispute within the meaning of Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 1947 because the demand for departmentalisation is not covered by Schedule III of the Industrial Disputes Act.
- (iii) that the Ningha Colliery Mazdoor Union had no locus standi to sponsor the cause of the contract labour of the New Kenda Colliery because it had no following whatsoever from amongst the workmen of the New Kenda Colliery of the Eastern Coalfields Ltd, its jurisdiction being confined to the limited area of Ningha colliery and hence the reference is invalid, there is no industrial dispute on this ground also.
- (iv) that the reference is vague because the date from which the effect will be given is not stated therein.

3. I will first take up preliminary objection No. (i). his objection is that in view of the provisions of the Act, the Central Government had no jurisdiction to refer this dispute relating to abolition of contract labour for adjudication to this Tribunal and the Tribunal also has no jurisdiction to decide it. In my opinion this contention is well founded. The Act was passed to prevent the exploitation of contract labour and also to introduce better conditions of work. The Act provides for regulating and abolition of contract labour. The underlying policy of the Act is to abolish contract labour, wherever possible and practicable, and where it cannot be abolish altogether the policy of the Act is that the working conditions of the contract labour should be so regulated as to ensure payment of wages and provision of essential amenities. That is why the Act provides for regulated conditions of work and contemplates progressive abolition to the extent contemplated by S. 10 of the Act. Section 10 of the Act deals with abolition while the rest of the Act deals mainly with regulation. The dominant idea of S. 10 of the Act is to find out whether contract labour is necessary for the industry, trade, business, manufacture or occupation which is carried on in the establishment. The Act in S. 10 empowers the Government to prohibit employment of contract labour in any establishment. The Government under that section has to apply its mind to various factors before the Government prohibits by notification in the official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment. Section 10 of the Act runs as follows:

"10. Prohibition of employment of contract labour—(1) Notwithstanding anything contained in this Act the appropriate Government may, after consultation with the Central Board or, as the case may be, a State Board, prohibit, by notification in the Official Gazette, employment of contract labour in any process, operation or other work in any establishment.

(2) Before issuing any notification under sub-section (1) in relation to an establishment, the appropriate Government shall have regard to the conditions of work and benefits provided for the contract labour in that establishment and other relevant factors, such as—

- (a) whether the process, operation or other work is incidental to, or necessary for the industry, trade business, manufacture or occupation that is carried on in the establishment.

(b) whether it is of perennial nature, that is to say, it is so of sufficient duration having regard to the nature of industry, trade, business, manufacture or occupation carried on in that establishment.

(c) whether it is done ordinary through regular workmen in that establishment or an establishment similar thereto.

(d) whether it is sufficient to employ considerable number of whole-time workmen."

It is obvious that Section 10 confers power on appropriate Government to abolish contract system of work in accordance with the provisions of the Act. In other words, the jurisdiction to abolish the contract labour is completely vested in the Government and not in the Industrial Tribunal. It is the Government and Government alone which can entertain such matter. The matter has been settled at rest by the decision in *Vegoils Private Ltd. v. The Workmen*, 1972 Lab IC 760 (SC)—1971 II LLJ 567. At page 770 of 1972 Lab IC the Supreme Court observed :

"The appropriate Government then taking action under Section 10 will have an overall picture of the industry carrying on similar activities and decide whether contract labour is to be abolished in respect of any of the activities of that industry. Therefore it is reasonable to conclude that the jurisdiction to decide about the abolition of contract labour or to put it differently to prohibit the employment of contract labour is now to be done in accordance with Sec. 10. Under Section 10 of the said Act the jurisdiction to decide matters connected with prohibition of contract labour is now vested in the appropriate Government. Therefore with effect from February 10 1971 it is only the appropriate Government that can prohibit contract labour by following the procedure and in accordance with the provisions of the Central Act. The Industrial Tribunal in the circumstances will have no jurisdiction though its award is dated November 29, 1970 to give a direction in that respect which becomes enforceable after the date of the coming into force of the Central Act. In any event such a direction contained in the award cannot be enforced from a date when abolition of contract labour can only be done by the appropriate Government in accordance with the provisions of the Central Act. In this view also it must be held that the direction of the Industrial Tribunal abolishing contract labour with effect from May 1, 1971 regarding loading and unloading cannot be sustained."

From a perusal of the above there is no doubt the Industrial Tribunal has now no jurisdiction to give a direction for abolition of contract labour. It is incompetent to give relief to the concerned workmen in this behalf and cannot adjudicate the dispute. Following the above Supreme Court case a Division Bench decision of the Andhra Pradesh High Court in *Burmah Shell Company v. Industrial Tribunal*, 1975 Lab. IC 165 it was held that the Government had no jurisdiction to refer a dispute relating to abolition of contract labour and as such the reference made to the Industrial Tribunal was invalid and the industrial tribunal had no jurisdiction to adjudicate the dispute referred to it. I may also state here that it has long been well settled that where power is given to do a certain thing a certain way, the thing must be done in that way and in no other; See *Taylor v. Taylor* (1873) 1 Ch. D 426, Jerral MR. The dispute in the instant case, therefore, can only be resolved in accordance with the provisions of Section 10 of the Special Act and in no other manner. Any other method of performance is necessarily forbidden. It must therefore, be held that the jurisdiction of the industrial tribunal to adjudicate the dispute relating to abolition of the contract labour has been taken away by legislation.

4. In the view which I have taken above on objection No. (i), it is not necessary to decide the other objections raised by the management.

5. For the foregoing reasons my concluded opinion is that the Central Government had no jurisdiction to refer and this tribunal has no jurisdiction to adjudicate the dispute in

question relating to departmentalisation of contract labour, number.ug 65, of New Kenda Colliery of Eastern Coalfields Ltd. I hold that the reference is invalid, bad in law and incompetent and it is rejected as such.

Dated, Calcutta,

The 23rd July, 1983.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-19011(3)/81-DIV(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

New Delhi, the 16th August, 1983

**S.O. 3387.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Jabalpur (M.P.), in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Burhar Sub-Area of Western Coalfield Limited, Post Office, Amlai, Distt. Shahdol and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th August, 1983.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT

JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)/(19)/1982

PARTIES :

Employers in relation to the management of Burhar Sub-Area of Western Coalfields Limited, P.O. Amlai, District Shahdol and their workmen represented through the Koyla Mazdoor Sabha P.O. Dhanpuri District Shahdol (M.P.).

APPEARANCES :

For Workmen—Shri Jagdish Singh.  
For Management—Shri P. S. Nair, Advocate.

INDUSTRY : Coal

DISTRICT : Shahdol(M.P.)

AWARD

Dated August 3, 1983

The Central Government in exercise of its power under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act vide their Notification No. L-22012(6)/81-D.IV(B) Dated 12th February, 1982 referred the dispute relating to removal of Shri Atish Singh from services for adjudication. The matter for adjudication is in the following terms —

“Keeping in view that the Safety belts are not supplied to Shri Atish Singh, Asstt. Supervisor/Tub-Writer Burhar No. 3 Mine of WCL, on demand, whether the action of the management dismissing the workman vide their letter No. SAM(B)[6-10]3215 dated 17-11-79 is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. Shri Atish Singh, Asstt. Supervisor/Tub-writer Burhar No. 3 mines of Western Coalfields Limited was dismissed from service vide management's letter No. SAM(B)[C]10/3215 dated 17-11-1979 for certain misconduct alleged to have been committed by him vide charge-sheet No. A-1-W-15/79/03907 dated 18-6-1979. Shri Y. K. Singh, Manager Burhar No. 3 conducted a departmental enquiry into the charges levelled against Shri Singh and after the enquiry he gave a finding holding the workman Shri Atish Singh guilty of the charges levelled against him. On the basis of the findings of the Enquiry Officer Shri Atish Singh's services were terminated with effect from 17-11-1979.

3. After the termination of services Shri Atish Singh case was taken up by the General Secretary, Koyla Mazdoor

Sabha, Dhanpuri, District Shahdol. After the failure of the conciliation proceedings the Central Government referred the dispute as stated above for adjudication.

4. During the pendency of the reference before this Tribunal the parties have arrived at an amicable settlement. The settlement is signed by both the parties. I would therefore, make this award in terms of the settlement which are these :—

1. That the workman, Shri Atish Singh, Asstt. Supervisor/Tub-Writer of Burhar No. 3 mine W.C. Ltd. Sohagpur Area will be reinstated on duty w.e.f. 16-8-1983 without any back wages or any other benefit for the period 17-11-79 till 16.8.1983. However, that period will be treated on the basis of no work no pay.
2. That Shri Atish Singh will be given continuity of service for the period during which he remained idle.
3. That Rs. 500 (Rupees five hundred) will be paid by the management to the Union towards costs.
4. This settlement will be implemented by the party w.e.f. 16-8-1983.”

Since in terms of the settlement the management shall pay Rs. 500 as costs to the Union there shall be no other costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer

[No. L-22012(6)81-D.IV(B)]

**S.O. 3388.**—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of D.V.C. Mines Bermo, P.O. Bermo, District Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 65 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S.10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of D.V.C. Mines, Bermo and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri N. Mehato, Senior Personnel Officer.

On behalf of the workmen—None.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 26th July, 1983

AWARD

This is an industrial dispute under S.10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. 24012(8)/82-IV(B) dated 9th July, 1982 has referred this dispute to its Tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

“Whether the action of the management of DVC Mines, Bermo, Post Office Bermo, District Giridih in terminating the services of Shri Rameshwar Bhuiyan, Dresser is justified ? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. In this case the workman has not appeared inspite of several adjournments given and ultimately the case was heard ex-parte. Only the written statement of the management has been filed and the management representative has placed the case before me. The management has contended that the dispute was raised by Jharkhand Mukti Morcha which is not a registered trade union but a political party. On facts it is said that the concerned workman, Shri Rameshwar Bhuiyan, dresser was absent without permission or authorised leave since 2-7-81, and consequently, the management by letter dated 10-8-81 asked him to join his duty within 10 days from the date of issue of this letter and to explain his unauthorised absence. The concerned workman, however, failed to report for duty and he did not explain his absence. He was therefore dismissed by the letter dated 28-8-81. The concerned workman came to the colliery on 4-9-81 with a certificate of his illness. The medical certificate was not accepted as it was filed long after his dismissal.

3. In absence of the workman we do not know what case the concerned workman has in this dispute. We also do not know whether the concerned workman was a permanent or a temporary employee and what has been his terms and conditions of service. It is no doubt true that if he has attained permanency in his service, he could not be dismissed without a charge-sheet and departmental proceedings. It appears that the concerned workman is not interested in prosecuting this dispute. Hence it is not possible to find that the action of the management in terminating the services of Shri Rameshwar Bhuiyan. Dresser is unjustified.

4. The result is that this reference is answered accordingly: The action of the management of DVC Mines, Bermo, Post office Bermo, District Giridih, in terminating the services of Shri Rameshwar Bhuiyan, Dresser is justified. Consequently, the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-24012(8)/82-D.IV(B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1983

का० आ० 3389.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर, कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड़) के उपखंड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1604 तारीख 24 फरवरी, 1983 द्वारा इंडिया गवर्नमेंट मिंट, बम्बई को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 फरवरी, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि का छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ड़) के उपखंड (VI) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग का उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 24 मार्च, 1983 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017/15/81-डी० 1-ए)]

एस० एच० एस० आय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 16th August, 1983

S.O. 3389.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provision of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1604 dated the 24th February, 1983 the India Government Mint, Bombay to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months, from the 24th February, 1983.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 24th August, 1983.

[No. S-11017/15/81-DIA]

S. H. S. IYER, Under Secy.

New Delhi, the 8th August, 1983

S.O. 3990.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bangalore, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dena Bank, Madras and their workman, which was received by the Central Government on the 1st August, 1983.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA BANGALORE

Dated this the 25th day of July 1983

Central Reference No. 7 of 1981

I PARTY :

Sri M. Papanna, No. 82-Varamowu Village (Via) Banaswadi, Bangalore-560043.

Vs.

II PARTY :

The Regional Manager, Dena Bank, Regional Office, 103-Mungambakkam High Road, Madras-600034.

APPEARANCES :

For the I Party—Sri K. Jayaprakash Hegde, Advocate, Bangalore.

For the II Party—Sri K. R. D. Karanth, Advocate, Bangalore.

REFERENCE

(Government Order No. L-12012/264/80-D.IIA dated 1-8-1981)

AWARD

The Central Government has made a reference of the dispute between the parties for adjudication on the following points :—

"Whether the action of the management of the Dena Bank, Bangalore Region in relation to their Sarajapura Branch in Bangalore region in terminating the services of Shri M. Papanna, Clerk with effect from 27-12-76 is justified? If not, to what relief is the worker concerned entitled?"

2. The I Party submitted a statement contending that his termination from service is invalid as he had applied for leave during his absence on account of his illness as well as that of his wife and no orders were passed on the said leave application. According to him he was victimised for his trade union activities and it was wrong on the part of the management to have terminated his services on the ground of his long absence. He adds that even such unauthorised absence would amount to a misconduct for which a charge should have been framed and an enquiry held giving him an opportunity to defend himself. He says that

he was not paid retrenchment compensation and on this ground also the order of termination is invalid.

3. The II Party filed a statement denying the allegations made by the I Party and contending that the I Party workman was absent from 24-12-1976 and had never joined duty in spite of letters by the management and hence it was treated as a case of voluntary abandonment. According to it there is no question of payment of any retrenchment compensation as his services were not terminated on account of any positive act of the management but on account of abandonment of service and consequent to the removal of the name of the I Party from the Muster Roll.

4. At the time of evidence the I Party remained absent and only the Branch Manager of the II Party-Bank under whom the I Party was working gave evidence. He produced Exts. M-1 to M-7 as the seven leave letters by him and Exts. M-9 to M-11 as the letters written by the management. He has also produced Ext. M-12 as a letter received from the I Party enclosing two medical certificates Exts M-13 and M-14. Ext. M-16 is the copy of the notice issued to the I Party treating his absence as abandonment of service. According to him a copy of Ext. M-16 was served on the I Party workman under his acknowledgement taken on Ext. M-16. The decision in *L. Robert D'Souza vs. Executive Engineer, Southern Railway 1982 (I) LLJ 330* lays down that termination of service on account of absence without leave, without earlier notice and enquiry would amount to contravention of the minimum principles of natural justice and is invalid. The contention that the abandonment of service does not amount to termination is also not correct in view of the decision in *H.M.T. Limited vs. Labour Court 1983 1 LLJ 337*. The learned pleader for the II Party relies on a decision in *Buckingham and Carnatic Co. Ltd., vs. Venkatayya 1963 11 LLJ 638* in support of his argument that it is permissible for the management to treat the absence without leave as sufficient to terminate the service. But the said decision is on the interpretation of the provision of Section 73 of the E.S.I. Act and is not helpful to him to support his contention that the II Party is entitled to terminate the services of the I Party even without an enquiry. The decision in *National Engineering Industries Ltd., vs. Hanuman 1967 11 LLJ 883* relied on by the pleader for the II Party is also not helpful to him as it was the case wherein it was decided that automatic termination of service for long absence under the relevant standing orders would not amount to contravention of Section 33 of the Industrial Disputes Act and hence no complaint under Section 33-A of the said Act would lie.

5. In the present case, the letter seeking leave from 26-12-1976 to 14-4-1977 sent by the I Party to MW-1 is produced at Ext. M-12. In that, there is an endorsement of having received it on 15-4-77 with the seal of that date. The I Party has written therein that if there is no leave to his credit he may be sanctioned leave without pay. He had also enclosed two medical certificates Exts. M-13 and M-14 to cover up that period. There is no order passed on the said application even till the final date of termination from service. The allegation in the letter by the management dated 6-9-77 produced at Ext. M-15 to say that he was remaining absent from duty from 27-12-1976 without intimation or prior sanction cannot be taken to be true when the II Party has kept back Ext. M-12 without passing an order granting or refusing leave. Though the I Party has stated in his statement that from May 1977 his wife who was pregnant fell ill and gave birth to a child and the child was also treated in the hospital and he sent an application for leave upto 28-10-1977, the said leave letter is not produced by either party. Even if it is to be taken that there is no leave letter given by the I Party to cover up his absence from 14-4-1977 it would be still a case where the management ought to have framed a charge against him for his absence without leave and enquired into it in order to find out the truth or otherwise of his allegation and pass suitable orders either condoning his absence or removing him from service for that misconduct. But passing an order as in Ext. M-16 to say that he remained absent from duty from 27-12-1976 without intimation or prior sanction and hence it is presumed that he has voluntarily abandoned the service is highly irregular and improper in view of the first two decisions quoted above. Ext. M-16 is the order passed by the Regional Manager with a copy to the Branch Manager

Sarjapur with instructions to say "Please strike off his name from Muster Roll as on 27-12-1976. Please put a remark "Voluntarily abandoned the service on his own"—in the Muster Roll". This is highly irregular and illegal and in view of the first two decisions quoted above. Such a termination would amount to retrenchment and it is not permissible to do so without complying with the provisions of Section 25FF of the Industrial Disputes Act and consequently I have to hold that the action of the management in terminating the services of the I Party-workman with effect from 27-12-1976 is not justified. The I Party-workman is therefore entitled to the relief of reinstatement with back wages as there is no other evidence on behalf of the management about his gainful employment or otherwise. Award I passed accordingly. Parties to bear their own costs.

V. H. UPADHYAYA, Presiding Officer

[No. L-12012/264/80-D.II(A)]

New Delhi, the 11th August, 1983

S.O. 3391.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad in the industrial between the employers in relation to the State Bank of India, Patna and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1983.

# BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO.2) DHANBAD

REFERENCE NO. 131 OF 1982.

In the matter of an industrial dispute under S. 10 (I)(d) of the I.D. Act, 1947.

## PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Patna and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the employers : Shri U.K. Tewari, Advocate.

On behalf of the workman : Shri D. Mukherjee, Advocate.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Bank

Dhanbad, 23rd July, 1983.

## A W A R D

This is an industrial dispute under S. 10 (1) (d) of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-12012 (108)/82-D. II(A) dated 29-10-82 has referred this dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms :

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of the State Bank of India in relation to their Deoghar Branch in terminating the services of Shri Shatrughan Mishra, cashier with effect from 7-9-1964 is justified ? If not to what relief is the workman concerned entitled."

2. As will appear from the schedule of this reference the services of Shri Shatrughan Mishra, cashier of State Bank of India was terminated as far back as 7-9-1965. His case in short is that he was employed as cashier in the State Bank of India at Deoghar branch in the district of Santhal Parganas in the month of November, 1962. He worked till 6th September, 1965. According to him he worked for 315 days calculating from July, 1964 to June, 1965. Calculating from August, 1964 to July, 1965 he worked for 325 days and again calculating from September, 1964 to August, 1965 he worked

for 313 days. Then again from October, 1964 to September, 1965 he worked for 289 days. The concerned workman actually relies upon the provisions of S. 25B (2) of the I.D. Act, 1947. The management appointed him from time to time by appointment letters for certain periods. Obviously, the management did not treat his services as continuous. In such cases the provisions of I.D. Act S. 25 B (2) is that if a workman has actually worked for 240 days in 12 calendar months, his services should be treated to be continuous. The above calculation has been made on behalf of the workman to show that in 12 calendar months he has worked for more than 240 days, not only in one year but also for several years and therefore he gets the protection of law against retrenchment, as such protection has been provided under S. 25F of the I.D. Act, 1947. It is an admitted position that the concerned workman was retrenched without any notice and without payment of any retrenchment compensation. According to the concerned workman no reason has been assigned as to why his services were terminated when according to the I.D. Act, 1947 as well as the circular of the State Bank of India he should have been permanently absorbed in the services of the State Bank of India. According to the concerned workman such termination of service had no legal validity and in spite of the termination order the concerned workman would be deemed to be in continuous service from 7-9-1965. On behalf of the concerned workman it has been contended that ever since his retrenchment he has been approaching the management verbally as well as in writing for reconsideration of his case and for permanent absorption in the service of the State Bank of India. His representations were never replied. Finding no way of redress, the union of the concerned workman raised an industrial dispute and the conciliation ended in failure resulting into this reference for adjudication.

3. The case of his management, on the other hand, is that the services of the concerned workman was based on contract and not in the ordinary course. He was initially appointed in 1962 only for some days and thereafter he was appointed afresh for a limited period by appointment letters. According to the management there was no need for the management to keep him in service and therefore in terms of his appointment letter his service automatically ended on 6-9-65. The management's case is that the case of the concerned workman is neither covered by S. 25B(2) nor by S. 25F of the I.D. Act, 1947. It has been contended that the case of the concerned workman is governed by proviso to S. 25N (1)(a) of the I.D. Act, 1947. The management has also pleaded that the concerned workman never pressed for any service after the termination of his service and after a lapse of 15 years he started pressing for his appointment sheltering behind the decision in Sundarmon's case as reported in AIR 1976 S.C. 1111.

4. On behalf of the workman no oral evidence has been adduced. But in order to rebut the case of the management the workman has placed on the record a large number of documents to show that he has been always pressing for his appointment on the ground that he was illegally retrenched. Ext. W. 1 is an application dated 24-1-76 submitted by the workman, Shri Shatrughan Mishra to the Agent, Deoghar branch. Ext. W. 2 is a representation dated 6-3-67 registered with A/D submitted by the workman to the Secretary & Treasurer, State Bank of India, L. H.O. Calcutta. Ext. W. 3 is postal registration receipt and Ext. W. 4 is postal acknowledgement. Then again Ext. W. 5 is a representation dated 5-5-67 registered with A/D addressed to the Secretary & Treasurer, State Bank of India, L.H.O., Calcutta Ext. W.6 and Ext. W. 7 are postal registration receipt and postal acknowledgement respectively. In this manner right upto Ext. W. 50 representations, postal receipts and acknowledgements have been filed by the workman upto 21-7-82. The only contention raised in this connection by the management is that they have no knowledge about these letters, but these letters backed up by registration receipts and acknowledgements are ample proof of the fact that the concerned workman has been regularly pressing for his case to be considered by the management, but without any effect. So the ground taken by the management that the concerned workman has made no effort for consideration of his case by the management cannot stand and it has to be held that the delay in raising this industrial dispute by the concerned workman has been fully explained and it cannot be fatal to the case of the concerned workman. In other words, this claim cannot be rejected for the reason that there has been delay in raising this industrial dispute.

5. The next point for consideration is as to whether the case of the concerned workman is covered by the proviso to Section 25N(1)(a) of the I.D. Act, 1947. It is better to quote this section :

"25N condition precedent of retrenchment of workmen—

- (1) No workman employed in any industrial establishment to which this chapter applies, who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer until—
- (a) the workman has been given 3 months' notice in writing indicating the reason for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice :

Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement, which specifies a date for termination of service."

This proviso in effect means a service under an agreement which is commonly known as contract service. The management has filed all the appointment letters under which the concerned workman has worked ever since 1962. These letters are Exts. M1 to M32. Under all these letters the concerned workman was appointed by Deoghar branch of State Bank of India for a particular period with the contention that the appointment will be deemed to have come to an end at the expiry of the aforesaid period, unless in the meantime it is extended at the discretion of the bank for a further period or periods. These are all office copies of appointment letters bearing the signature of Shri Shatrughan Mishra as having received the appointment letters. The contention raised on behalf of the management is that under these appointment letters, the period of service was specified and liable to terminate on the expiry of the fixed term unless extended for a period or periods. For this reason it is said that the proper provision to be applied is not S. 25F but S. 25N of the I.D. Act, 1947. Now S. 25N (1) will show that these are applicable to such cases in which the workman has worked for one year. The proviso means that such workmen under agreement or contract has served for one year. This is believed by the appointment letters which have not been issued for a period of more than 30 days. It means that through appointment letters there has always been a fresh agreement and there has been no agreement covering a period of one year. It is another matter that in course of 12 months he has worked for more than 240 days but for the reason given by me above, there has been no particular contract for one year so as to attract the provision of S. 25N of the I.D. Act. So this contention of the management cannot be held good. It has been contended on behalf of the workman that at the time when the conciliation was going this plea was not advanced on behalf of the management because the only point urged was that the claim of the concerned workman was belated and hence liable to be defeated on that ground alone.

6. Now turning to S. 25 B of the I.D. Act, 1947 reliance has been placed on S. 25B (2) (a). Clause (1) relates to continuous services and we are not concerned with this clause in the present case. Clause (2) reads thus :

"Where a workman is not in continuous service within a meaning of Clause (1) for a period of one year or six months, he shall be deemed to be in continuous service under an employer.—

- (a) For a period of one year if the workman, during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation has to be made, has actually worked under the employer for not less than—
- (i) 190 days in the case of a workman employed below-ground in a mine ;
- (ii) 240 days in any other case."

Clause (2) therefore refers to a workman not in continuous services as is the case here. But it has been shown that in course of his service in one particular calendar year he has worked for more than 240 days. This fact has not been disputed on behalf of the management. It is clear therefore that the management has side tracked this provision of law as laid down in the I.D. Act, 1947 in terminating the service of the

concerned workman. Such a termination of service is not justified. The concerned workman has repeatedly pressed for his appointment and for re-consideration of his case. He has through several representations been approaching not only the local authorities of State Bank of India but also the higher management of State Bank of India with no consequential effect whatsoever. According to the concerned workman he has been sitting idle ever since his termination of service. The law requires his services should not have been terminated without resorting to the provisions of S. 25F of the I.D. Act. It is further clear that such retrenchment is bad in law which can have no legal validity and his service will be deemed to be continuous with effect from the date of termination of his service.

7. Thus, having considered all aspects of the case, the reference is answered accordingly :

The action of the management of the State Bank of India in relation to their Deoghar Branch in terminating the services of Shri Shatrughan Mishra, Cashier with effect from 7-9-65 is not justified. Consequently, the concerned workman should be deemed to be in the service of the Bank w.e.f. 7-9-65 with all back wages and other emoluments. He will be further entitled to all increments, consequential promotions etc. by virtue of his continuity in service.

This is my award.

J.P. SINGH, Presiding Officer,

[No. I-12012/108/82-D. II (A)]

New Delhi, the 16th August, 1983

**S.O. 3392.**—In pursuance of section 17 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India, Varanasi, and their workman.

BEFORE SHRI O.P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 16 of 1983

In the matter of dispute between :  
Shri Gajanand Tambe, Temporary Clerk through  
The General Secretary, U.P. Bank Employees  
Federation, 26/104, Birhana Road Kanpur

AND

The Regional Manager,  
Union Bank of India, Maharaja Bagh,  
Rathyatra Crossing, Varanasi.

PRESENT :

Shri Satpal and Shri Atul Gupta—for the Management.  
None—for the workman.

#### AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, on 15th September, 1982, vide Order No. I-12012/335/81-D. II (A) made the reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the Management of Union Bank of India, Main Branch Varanasi in not providing employment to Shri Gajanand Tambe, Temporary Clerk after 26-8-1978 and terminating his services is justified? If not, to what relief the said workman is entitled?”

2. The matter has been settled between the parties and under the settlement, the workman has reported to Regional Manager, Union Bank of India, Varanasi and he has actually been posted in Varanasi already on 14-4-1983 and is already in the service of the Bank. Accordingly, the dispute does not

survive for adjudication by this Tribunal and has been voluntarily settled by a fair agreement between the parties.

3. Accordingly, a ‘No Dispute Award’ is made in this case. July 1, 1983.

O. P. SINGLA, Presiding Officer

[No. I-12012(335)/81-D. III (A)]

N.K. VERMA, Desk Officer

आवेश

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1983

**का० आ० 3393.**—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में तृतीकोटिन पत्तन न्यास, तृतीकोटिन के प्रबंधाधि से संबंधित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच स्थित है,

और, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुण राज होंगे, जिसका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

#### अनुसूची

“क्या तृतीकोटिन पत्तन न्यास, तृतीकोटिन के प्रबंधाधि के अनुसूचीबद्ध कर्मचारियों को तारीख 1-4-1979 से प्रति घंटे की दर पर अतिकाल भत्ता, जो एक मास के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते को 195 (6 1/2 घंटे/30 दिन) से विभाजित करके प्राप्त देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है?”

[सं० एल-44011/3/82-डी० 4 (ए)]

आर० के० गुप्ता, डेस्क अधिकारी

#### ORDER

New Delhi, the 12th August, 1983

**S.O. 3393.**—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Tuticorin Port Trust, Tuticorin and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Tuticorin Port Trust, Tuticorin in denying the overtime allowance to the Ministerial Staff at the hourly rate arrived at by dividing basic pay and dearness



allowance for a month by 195 (6-1/2 hours X-30 days) with effect from 1-4-1979 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

[No. L-44011/3/82-D.IV(A)]

R. K. GUPTA, Desk Officer

### CORRIGENDA

New Delhi, the 10th August, 1983

**S.O. 3394.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1252 dated the 4th February, 1983 published at page 1119 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of dated the 19th February, 1983, in line 3, for the word "Part" read "Park".

[No. S-35017(115)/82-PF.II]

**S.O. 3395.**—In notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4371 dated the 8th December, 1982 published at page 4461 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 25th December, 1982, in line 3, for the word "Panduregan" read "Pandurang".

[No. S-35019(105)/82-PF.II]

**S.O. 3396.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1259 dated the 4th February, 1983 published at page 1116 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th February, 1983, for the word "Fisher" read "Fischer".

[No. S-35017/80/79-PF. II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1983

**का०आ० 3397.**—मैसर्स भारत कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, डाकघर बिरलाग्राम, नागडा-456331, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश/228) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबन्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं 589 GI/83—10

प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों, संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशितों को प्रति-कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/97/83-पीएफ-2]

New Delhi, the 30th July, 1983

**S.O. 3397.**—Whereas Messrs Bharat Commerce and Industries Ltd., P.O. Birlagram, Nagda-456331, Madhya Pradesh (MP/228) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under

clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the languages of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(97)/83-PF.II]

का०आ० 3398.—मैसर्स वेस्टर्न इण्डियन इरेक्टर्स लिमिटेड, सह्याद्री सदन, तिलक रोड, पूना-411030 (महाराष्ट्र-11278) (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पूयक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन, कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों

के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होती तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रति कर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जो स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदारित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/106/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3398.—Whereas Messrs Western Indian Erectors Ltd., Sahadri Sadan, Tilak Road, Poona-411030 (MH/11278) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(106)/83-PF.II]

का०आ० 3399.—मंसस रूरल इलैक्ट्रिसिटी को-ऑपरेटिव सोसायटी लि०, पानधाना, खण्डवा जिला, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश-3436) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा निगम के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मांस की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्ण, निरीक्षण

प्रभारां संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बात आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने को व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफलता रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अर्न्तगत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संशय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० ए-35014/107/83-पी० एफ-2]

**S.O. 3399.**—Whereas Messrs The Rural Electricity Co-operative Society Ltd., Pandhara, Khandwa District, M.P. (MP/3436) hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts' payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance

Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(107)/83-PF.II]

का० आ० 3400 :—मैसर्स नेशनल कोआपरेटिव शूगर मिन्स लि०, ए-2731, मदुराई (तमिल नाडु/5982) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुजेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रोविडेंट फंड के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हस्तांतर नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/108/83 पी० एफ०-2]

**S.O. 3400.**—Whereas Messrs The National Co-operative Sugar Mills Ltd., A.2731, Madurai (TN)5982), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment extended under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(108)/83-PF.II]

का० आ० 3401-मैसर्स धर्मपुरी मेन्टल को आपरेटिव बैंक लिमिटेड, धर्मपुरी पोस्ट बक्स नं० 16 (तमिल नाडु 4147-एस) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तामिल नाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे पुनरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभाकारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन

फायदों से अधिक अनुकूल हों जो, उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिनी को प्रतिकर को के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्ब अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्ब कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय, जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए व्यक्तिगत का दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

11. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक/वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/309/83 पी० एफ-2]

S.O. 3401.—Whereas Messrs The Dharampuri Central Co-operative Bank Limited, Dharampuri, P. Box No. 16 (TN/4147-A), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);



And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(109)/83-P.F.II]

का० आ० 3402—मैसर्स तुमकुर को-ऑपरेटिव मिल्क प्राइव्ठ सोसायटीज यूनिन लि० न० 46, के० आ० एक्स्टेंशन बी०एच० रोड तुमकुर-1 (कर्नाटका 6739) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रणामन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम की संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस वंश में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत ताराख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/110/83-पी० एफ०-2]

**S.O. 3402.**—Whereas Messrs Tumkur Co-operative Milk Producers Societies Union Ltd., No. 46, K. R. Extension B.H. Road Tumkur-1 (KN/6739) hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees' of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(110)|83-PF. II]

का० आ० 3403.—मैसर्स एस० के० एम० पोल्ट्री सर्विसेस, मार्केटिंग सेन्टर्स, 49/सी गांधीजी रोड, पो० बाकस नं० 415, इरोडे-638002 (तमिलनाडु / 10725) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निश्चय सहबद्ध बीमा स्कीम 1976, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुश्रेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखना जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सानूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम, के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदस्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुश्रेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशित को

प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अर्धान नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्धान कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दण्ड में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उन स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अर्धान आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/111/83-पी० एफ-2]

**S.O. 3403.**—Whereas Messrs S.K.M. Poultry Services Marketing Centres, 49/C Gandhiji Road P.B.No. 415, Erode-638002. (TN/10725 (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And, whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/111/83-PF. II]

का० आ० 3404.—मैसर्स इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लि०, 34-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 (दिल्ली/2436), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उस की मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक

बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न दी गई होती तो, उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काय नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/132/83 पी एफ० 2]

**S.O. 3404.**—Whereas Messrs Indian Farmers Fertiliser Co-operative Ltd., 34-Nehru Place, New Delhi-110019 (DL/2436) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section, (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the

interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014 (132)/83-PF. II]

**का० घा० 3405.**—मैसर्स गुजरात अल्कालीज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डाकघर पेट्रोकेमिकल्स- 391346, जिला बड़ोदा (गुजरात / 10042) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है। ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रोमिसम का संघाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उनसे अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है), के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संघाय करेगा जो केन्द्रीय

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशितों का प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रति कूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो वह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के स्मृति में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार/नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एत 35 014/134/83 पी० एफ-2]

**S.O. 3405.**—Whereas Messrs Gujarat Alkalies and Chemicals Ltd., P. O. Petrochemicals-391346, District Baroda (GI/10042) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act)

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, Maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(134)]83-PF. III]

का० आ० 3408:—मैमर्स गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पो० बाक्स नं० 302, साहाकार भवन, रिलीफ रोड, अहमदाबाद (गुजरात/4655) । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की उपधारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का

संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है, के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करेगा।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसे कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।



7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन प्रदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/136/83-पी०एफ-2]

S.O. 3406.—Whereas Messrs The Gujarat State Co-operative Bank Ltd., P.B. No. 302, Sahakar Bhavan, Relief Road, Ahmedabad (GI/4655), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees

than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment to the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(136)/83-PF. II]

का० आ० 3407:- भैसर्ग रस्नम मिल्म एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली गेट के बाहर, दाधेश्वर रोड, पो० बक्स नं० 131, अहमदाबाद (गुजरात/297), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाता दिवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बावन आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बाढ के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानदेशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके

हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुतिशिवत करेगा।

[संख्या एस-35014(137)/83-प.फ.क-2]

**S.O. 3407.**—Whereas Messrs Rustam Mills and Industries Ltd., out side Delhi Gate, Dadheshwar Road, P.B. No. 131, Ahmedabad (GJ/297), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the

employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and, in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(137)/83-PF. II]

का० आ० 3408:—मैसर्स सूरत डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत (गुजरात 4672) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रश्नों का प्रत्येक मास की समाप्ति पर 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभागों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस/नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्वअनुमोद के बिना नहीं किया जाएगा। और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे,

प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशि-नियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एर-35014(138)83-पी०एफ०-2]

**S.O. 3408.**—Whereas Messrs The Surat Dist. Co-Operative Bank Ltd., Surat (GJ/4672). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for the period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees, Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employer as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Guarat, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(138)/83-PF. II]

का० आ० 3409—मैसर्स राम किशन इस्पात वर्क्स, जी० टी० रोड, ग्राम धूम दात्री, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश/5536), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निशेष सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में त्रिनिदिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त उत्तर प्रदेश को एसी विवरणियां भर्जेंगे और ऐसे लेखा रखेंगे तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस-नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशनितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशनितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/139/83-पी० एफ०-2]

**S.O. 3409.**—Whereas Messrs Ram Kishan Ispat Works, G. T. Road, Village Dboom Dadri, Distt. Ghaziabad (UP/5536). (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and

provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/139/83-PF.II]

का० आ० 3410.—मैसर्स इण्डियन डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मेफतलाल सेंटर, नारीमन प्वाइन्ट बम्बई-21 (महाराष्ट्र 1492-ए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन दो तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्‍यता प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पन्द्रह स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अस्तंगत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार/नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

**S.O. 3410.**—Whereas Messrs Indian Dyestuff Industries Ltd., Melalal Centre, Nariman Point Bombay-21 (MH/1492-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employee than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, is exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of accounts, Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014/140/83-PF.II]

**का० आ० 3411.**—मैसर्स इण्डियन डाइस्टाफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेद्री आगरा, कानपुर-12 (यू० पी० 370) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निपेक्ष सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं ;

अतः ; केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

#### अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे;

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को संपत्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिससे अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण,



निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजन किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भेजने करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समूचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का भेज करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रदेयता भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रदेयता भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियम नियत की प्रीमियम का भेज करने में असफल रहता है, और

पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिवक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तराधिकार नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिवक वारिसों को बीमा कृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत सफल प्राप्त होने के सात दिन के भीतर भुगतान करेगा।

[सं० एर-35014/141/83-पी०एफ० 2]

S.O. 3411.—Whereas Messrs Indian Oxygen Limited Factory Agra, Kanpur-12 (UP/370) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

#### SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment exempted under the said Act, is employed in Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(141)/83-PF.II]

का० आ० 3412.-मैसर्स प्रेमियर वेजोटेबल प्राइवेट्स प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान/1587) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निगम सङ्गठित बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए और इससे उपाबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष के अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

### अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त राजस्थान को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उस की मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या, उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा, स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि, स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में से देय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारियों के विधिक वारिस नामनिर्देशिनी को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, राजस्थान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उनमें सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्दार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मातृ त्रि के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/143/83-पी०एफ-2]

ए० के० भट्टराई, अवर सचिव

**S.O. 3412.**—Whereas Messrs Premier Vegetable Products Private Ltd., Industrial Area, Jaipur (RJ/1587), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

## SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment; the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Rajasthan, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(143)/83-PF. II]  
A. K. BHATTARAI, Under Secy.

